नई दिल्ली । बुधवार, 03 जून, 2026
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया, सिद्धार्थि संवत्सर विक्रम संवत 2083
वर्ष :12, अंक :148/ मूल्य 3.00 रुपए । पृष्ठ 12

दैनिक
विश्व केसरी
सिर्फ पत्रकारिता...
नई दिल्ली संस्करण
vishwakesari.com
@vishwakesariTV
@vishwakesari
vishwa_kesari_official
आर. एन. आई. संख्या डीईएलएच आईएन/2015/61415

@ खेल तृप्ति मुर्गंडे : दक्षिण एशियाई खेलों में जीते 5 गोल्ड... | @ विचार कानून, नैतिकता और जीवन के बीच चिकित्सक की दुविधा... | @ व्यापार सरकार बदलने जा रही होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार...

जम्मू के किश्तवाड़ में 2 जगह बादल फटा : लैंडस्लाइड से सड़कें बंद

सुरक्षाबल रेस्क्यू में जुटे; केरलम में 4 जून को पहुंचेगा मानसून

एजेंसी ■ नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में मंगलवार को दो जगह बादल फटे है। पहला बादल सरथल के गहन इलाके में और दूसरा माछीपाल क्षेत्र में फटा है। कुछ इलाकों में लैंडस्लाइड से सड़कें बंद हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल किसी जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है। पुलिस, रेड क्रॉस, राजस्व विभाग और अन्य एजेंसियों की टीमें मौके पर भेजी गई हैं।

सांसद और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि स्थानीय लोगों से लगातार संपर्क किया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मदद पहुंचाई जा सके।

इधर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आंधी-बारिश से 5 लोगों की मौत हो गई। एमपी के नीमच में सोमवार रात मकान की छत ढहने से मां-बेटे की मौत हो गई। वहीं, राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर में दीवार ढहने से दो बच्चों सहित 3 लोगों की जान चली गई। बादल आकाश में तैरते हुए दिखाई देने वाले पानी के कण या बर्फ होते हैं। जब भाप या वाष्प बनकर पानी के काफी छोटे-छोटे कण वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पहुंचकर ठंडी हवाओं के साथ मिलते हैं तो ये बादल कहलाते हैं। ये तो हुई बात बादल की। अब आगे जानते हैं आखिर बादल फटना क्या होता है। जब किसी छोटे से इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश होती है तो आमतौर पर इसे हम बादल फटना कहते हैं। इसमें बादल फटने जैसा कुछ नहीं होता। हां, ऐसी बारिश इतनी तेज होती है जैसे ज्यादा पानी से भरी हुई एक बहुत बड़ी पॉलिथीन आसमान में फट गई हो। इसलिए इसे हिंदी में बादल फटना और अंग्रेजी में Cloudburst के नाम से पुकारा जाता है।

मौसम विभाग के मुताबिक जब अचानक 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में एक घंटे या उससे कम समय में 100mm या उससे ज्यादा बारिश हो जाए तो इसे बादल फटना कहते हैं। बादल फटने की घटना कितनी खतरनाक हो सकती है, इसे समझने के लिए नीचे दिए गए इस वीडियो को देखिए। इसे वंडर ऑफ साइंस नाम के ट्विटर हैंडल ने पोस्ट किया है। कैप्शन में लिखा है कि ये ऑस्ट्रिया के लेक मिल्स्टैट का है, जिसे पीटर मायर ने अपने कैमरे में कैद किया है।

कई जगहों पर बिजली गिरने की चेतावनी

मौसम विभाग ने बताया कि मानसून 4 जून को केरलम के तट पर पहुंच सकता है। पहले 26 मई को केरलम पहुंचने का अनुमान था। मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरलम पहुंचता है और अगले डेढ़ महीने में पूरे देश को कवर करता है। मौसम विभाग के मुताबिक, 2 से 6 जून के बीच केरलम के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। मंगलवार को मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बाकी 11 जिलों में यलो अलर्ट है। बुधवार को 4 जिलों, गुरुवार को 8 जिलों और शुक्रवार को 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा। बाकी जिलों में यलो अलर्ट रहेगा। इस दौरान कई जगहों पर बिजली गिर सकती है। 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं।

संक्षिप्त खबर

अन्नामलाई ने नितिन नबीन और अमित शाह से की मुलाकात

नई दिल्ली। तमिलनाडु की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा नाम यदि किसी का गूंज रहा है, तो वह के. अन्नामलाई हैं। दिल्ली में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनकी लगातार बैठकों ने साफ संकेत दे दिया है कि राज्य की राजनीति में अब बड़ा भूचाल आने वाला है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा संगठन महासचिव बीएल संतोष से मुलाकातों के बाद यह चर्चा और तेज हो गई है कि अन्नामलाई अब अपनी स्वतंत्र राजनीतिक राह तय करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जिस नेता ने अपने दम पर तमिलनाडु में भाजपा को नई पहचान दी, गांव गांव तक संगठन को पहुंचाया और युवाओं के बीच जबरदस्त जनसमर्थन खड़ा किया।

हाथी की हत्या मामले में फॉरेस्टर निलंबित

भुवनेश्वर। ओडिशा के ढेंकनाल वन प्रभाग में हाथी को मारकर दफनाने की घटना में अंगुल के आरसीसीएफ ने हिंडोल के फॉरेस्टर को निलंबित कर दिया है। इसी के साथ इस घटना में रेंजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल, ढेंकनाल के हिंडोल वन क्षेत्र के अंतर्गत कंदराशुनी में एक फार्म हाउस के अंदर हाथी की हत्या और दफनाने की घटना को लेकर अब वन विभाग एक्टिव मोड में आ गया है। इस घटना में हिंडोल सेक्शन के सेक्शन फॉरेस्टर, दीप्तिरंजन आचार्य को वन विभाग ने निलंबित कर दिया है।

31 आरोपियों के खिलाफ एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की

मालदा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में चुनाव से पहले सड़क जाम करने और न्यायिक अधिकारियों को अवैध रूप से रोकने के मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने इस मामले से जुड़े चार अलग-अलग केसों में कुल 31 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। यह आरोप पत्र कोलकाता स्थित एनआईए की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया गया। यह मामला एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, जिसमें आरोप है कि कुछ लोगों ने सुनियोजित तरीके से सरकारी कार्य में बाधा डालने और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की।

ओएसएम विवाद के बीच लोखंडे प्रशांत सीताराम बने सीबीएसई के नए चेयरमैन

एजेंसी ■ नई दिल्ली

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली को लेकर उठे विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया। मंगलवार को केंद्र सरकार ने सीबीएसई के चेयरमैन का तबादला करते हुए नए अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा कर दी है।

इसके साथ ही, ओएसएम सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति का गठन भी किया गया है।

राहुल सिंह, चेयरमैन | हिमांशु गुप्ता, सचिव

कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा जारी आदेश के अनुसार, गृह मंत्रालय के गृह विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत 2001 बैच के एजीएमयूटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के आईएएस अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उन्हें अतिरिक्त सचिव के स्तर और वेतनमान में यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, वर्तमान सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह (आईएएस, बिहार कैडर 1996) को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। बढ़ती शिकायतों और विवादों के बीच केंद्र सरकार ने न केवल प्रशासनिक स्तर पर बदलाव किया है, बल्कि ओएसएम सेवाओं की खरीद और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं की गहन जांच कराने का भी फैसला लिया है। माना जा रहा है कि जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद मूल्यांकन प्रणाली में आवश्यक सुधारों पर भी विचार किया जा सकता है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा विशेषज्ञों की ओर से ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। मूल्यांकन प्रक्रिया की पारदर्शिता, उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन और परिणामों की सटीकता को लेकर कई शिकायतें सामने आई थीं। सरकार के इस कदम को शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

एनटीए पोर्टल और डीजीलाकर की सिक्योरिटी में बड़ी चूक

सुपरएडमिन डैशबोर्ड बायपास; जेईई एडवांस का डेटा भी लीक

एजेंसी ■ नई दिल्ली

सीबीएसई की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को लेकर उठे साइबर सुरक्षा संबंधी सवालों के बीच अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के री-एग्जामिनेशन पोर्टल में भी तकनीकी खामियां देखने को मिली। इसके साथ ही जेईई एडवांस 2026 के कैंडिडेट का डेटा भी लीक हो गया है। दुबई के साइबर सुरक्षा शोधकर्ता रायलन अनिल ने दावा किया है कि उन्होंने एनटीए के आधिकारिक री-एग्जामिनेशन पोर्टल में एक गंभीर सुरक्षा खामी का पता लगाया, जिसके जरिए उन्होंने सुपरएडमिन Login को बायपास कर डैशबोर्ड तक पहुंच प्राप्त की।

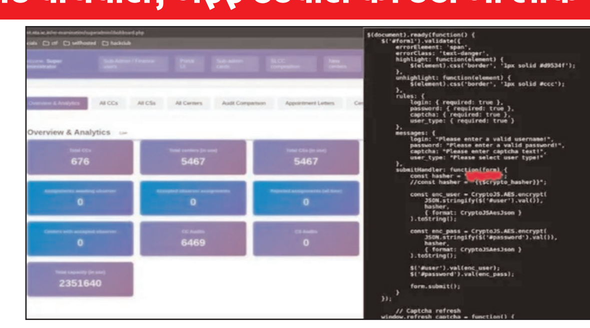

बेहद कमजोर क्रेडेंशियल होने का दावा

रायलन ने इंटरनेट मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पोर्टल में बेहद कमजोर क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल किया गया था, जिससे सुपरएडमिन एक्सेस हासिल करना संभव हुआ। क्रेडेंशियल्स का अर्थ Login ID (Username) और पासवर्ड होता है। यह आपके अकाउंट का प्रमाणपत्र या पहचान होते हैं, जिनका उपयोग करके आप किसी वेबसाइट, ऐप या सिस्टम में सुरक्षित रूप से Login इन करते हैं।

जेईई एडवांस्ड 2026 के अभ्यर्थियों का डाटा भी लीक

साइबर सुरक्षा शोधकर्ता रायलन अनिल ने दावा किया है कि जेईई एडवांस्ड 2026 के अभ्यर्थियों और परिणामों से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुरक्षा खामी से प्रभावित है। उसके अनुसार cdata.jeeadv.ac.in/result2026/ से जुड़ा क्लाउड स्टोरेज गलत कांफिग्रेशन के कारण बिना किसी प्रमाणीकरण (ऑथेंटिकेशन) के सार्वजनिक रूप से सुलभ था। उसने इससे जुड़े स्क्रीनशॉट भी एक्स पर साझा किए हैं।

यह जवाबदेही नहीं, कवर-अप है : राहुल गांधी

एजेंसी ■ नई दिल्ली

सीबीएसई चेयरमैन और सचिव के ट्रांसफर तथा ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति गठित किए जाने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने इस कार्रवाई को 'कवर-अप' बताते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने और स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग की है।

कांग्रेस नेता ने अपनी पोस्ट में कहा कि उनकी मांग पहले की तरह अब भी कायम है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए और पूरे मामले की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराई जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की 'एक महीने पुरानी अधूरी फाइल' को चुपचाप बंद करने की कोशिश की जा रही है।

राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को '18.5 लाख सीबीएसई छात्रों की परवाह होती' तो शिक्षा मंत्री को पहले ही हटा दिया गया होता।

अल नीनो की आशंका पर केंद्र अलर्ट, किसान हितों की सुरक्षा सर्वोच्च : शिवराज सिंह

एजेंसी ■ नई दिल्ली

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दक्षिण-पश्चिम मानसून, संभावित अल नीनो प्रभाव, जल उपलब्धता, बीज व्यवस्था, फसल रणनीति और राज्यों की तैयारियों की आज दिल्ली में विस्तृत समीक्षा की। इस उच्चस्तरीय बैठक में शिवराज सिंह ने निर्देश दिए हैं कि केंद्र के सभी संबंधित विभाग और राज्य सरकारें पूरी गंभीरता, समन्वय और अग्रिम योजना के साथ काम करें, ताकि किसी भी प्रतिकूल मौसमीय स्थिति में किसान को समय पर सलाह, उपयुक्त बीज, वैकल्पिक फसल विकल्प, नमी संरक्षण और जल प्रबंधन की सहायता मिल सके। उन्होंने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सरकार पूरी सतर्कता के साथ तैयारी कर रही है और लक्ष्य यह है कि मौसम की चुनौती का असर खेत और किसान पर न्यूनतम रहे।

कृषि भवन, नई दिल्ली में आयोजित कृषि एवं किसान कल्याण विभाग सहित सभी संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों के हित सर्वोपरि हैं और संभावित अल नीनो प्रभाव को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरी की जाएं। बैठक में मौसम पूर्वानुमान, जल उपलब्धता, फसलों की स्थिति, बीज एवं अन्य कृषि आदानों की व्यवस्था, राज्यों की तैयारियों और संभावित प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने वर्ष 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के सामान्य से कम रहने की संभावना जताई है और मौसमी वर्षा देशभर में दीर्घकालीन औसत के लगभग 90 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

'किसी तीसरे की जरूरत नहीं': बालेन शाह की मांग पर भारत का दो टूक जवाब

विदेश मंत्रालय ने यूरोपीय संघ और पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर पर दिए गए संयुक्त बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया

एजेंसी ■ नई दिल्ली

विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को भारत-नेपाल सीमा विवाद को सुलझाने में किसी भी तीसरे पक्ष की भागीदारी को पूरी तरह खारिज कर दिया। यह बयान नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के उस बयान के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने विवाद के समाधान के लिए चीन और ब्रिटेन की भूमिका की मांग की थी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, 'हमने सीमा संबंधी सभी मुद्दों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। यह साफ होना चाहिए कि भारत-नेपाल के बीच यह द्विपक्षीय मामला है और इसमें किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।'

द्विपक्षीय तंत्र पर जोर

जायसवाल ने नेपाल के प्रधानमंत्री की टिप्पणियों और नेपाल विदेश मंत्रालय के बयान पर ध्यान दिया। उन्होंने दोहराया कि दोनों देशों के पास सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए पहले से ही स्थापित तंत्र मौजूद हैं। MEA ने बताया कि भारत-नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा पहले ही सीमांकित किया जा चुका है।'

कुछ हिस्सों में समस्या गंडक नदी के रास्ता बदलने के कारण हुई है। तय हिस्सों में 'नो-मैन्स लैंड' पर अतिक्रमण के मामले भी सामने आए हैं, जिनकी संयुक्त मैपिंग चल रही है।

क्या है पूरा विवाद ?

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने संसद में कहा था कि सीमा मुद्दों पर चर्चा न केवल भारत और चीन के साथ, बल्कि ब्रिटेन के साथ भी हो रही है। उन्होंने सुझाव दिया कि ब्रिटेन को भी इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए क्योंकि मुद्दा 'ब्रिटिश इंडिया' के समय का है। शाह ने यह भी स्वीकार किया कि दोनों तरफ अतिक्रमण हुए हैं और दोनों पक्षों को बैठकर समाधान निकालना चाहिए।

भारत का आंतरिक मामला: जायसवाल

इसके साथ ही जायसवाल ने कहा, 'जम्मू-कश्मीर के जिक्र के संबंध में, हम यह कहना चाहेंगे कि हम भारत के आंतरिक मामलों पर संयुक्त प्रेस बयान में ऐसे बेवजह के जिक्र को पूरी तरह से खारिज करते हैं।'

प्रवक्ता ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि जिन संस्थाओं या देशों का इस मुद्दे पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, उन्हें ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए।

ट्विशा शर्मा केस : गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

एजेंसी ■ भोपाल

ट्विशा शर्मा केस में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत में कई अहम घटनाक्रम सामने आए। सीबीआई ने गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह की रिमांड अवधि समाप्त होने पर उनके लिए आगे की पुलिस रिमांड की मांग नहीं की। इसके बाद अदालत ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

सुनवाई के दौरान गिरिबाला सिंह ने अदालत में मीडिया ट्रायल को लेकर गंभीर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वे जहां भी जा रहे हैं, मीडिया उनके पीछे पहुंच रही है। गिरिबाला ने अदालत से अनुरोध किया कि इस तरह की कवरेज पर रोक लगाई जाए, क्योंकि इससे उनके परिवार की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा है।

गिरिबाला ने हाल ही में हुए सीन-रीक्रिएशन को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने अदालत को बताया कि उस दौरान उन्हें उनके घर से करीब तीन मकान पहले उतारा गया और मीडिया को इसकी फुटेज उपलब्ध कराई गई। उनका कहना था कि यदि जांच एजेंसी को उनके घर तक जाना था तो वाहन सीधे उनके घर के सामने भी रोका जा सकता था। वहीं, सीबीआई की ओर से अदालत को बताया गया कि फिलहाल एजेंसी न्यायिक रिमांड की मांग कर रही है। जांच एजेंसी ने कहा कि यदि आगे जांच के दौरान आवश्यकता महसूस हुई तो पुलिस रिमांड की मांग की जा सकती है।

कांग्रेस ने ममता बनर्जी के धरने को अधिकार बताया तो भाजपा ने 'जनता के गुस्से का आईना'

नई दिल्ली। कांग्रेस ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख ममता बनर्जी के धरने का समर्थन किया। यह धरना उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर कथित हमलों और रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले फेरीवालों को हटाए जाने के विरोध में था।

कांग्रेस ने इसे ममता बनर्जी का 'संवैधानिक अधिकार' बताया। वहीं, भाजपा ने कहा कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन का पश्चिम बंगाल के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो टीएमसी से नाराज हो चुके हैं।

कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि अगर लोकतंत्र में कहीं भी अन्याय होता है तो संविधान उसके खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देता है और ममता बनर्जी भी यही कर रही हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि सबने देखा है कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला किया गया। वह टीएमसी में दूसरे नंबर के नेता हैं और सांसद हैं। अगर वह भाजपा सरकार के राज में सुरक्षित नहीं हैं तो मैं कहूंगा कि यह भाजपा द्वारा सोची-समझी साजिश के तहत उनके खिलाफ किया गया हमला है।

प्रमोद तिवारी ने तृणमूल कांग्रेस के एक और सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि वह पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन इस हमले में उनके सिर पर चोट लगी। तृणमूल कांग्रेस के दर्जनों दफ्तरों में तोड़फोड़ की गई और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया।

कांग्रेस सांसद ने आगे कहा कि आजाद भारत में अब तक ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई थीं। यह भारतीय जनता पार्टी का तानाशाही वाला चेहरा है।

उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों से अपील की कि वे एक साथ आएं और भाजपा की कथित गुंडागर्दी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें।

दूसरी ओर, भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। उन्होंने कहा कि वह हताश, परेशान और निराश हैं। तृणमूल के सदस्य, चाहे वह सांसद कल्याण बनर्जी हों या सांसद अभिषेक बनर्जी, सब के सब राजनीतिक नौटंकी में लगे हुए हैं। ममता बनर्जी आज जिस विरोध प्रदर्शन की योजना बना रही हैं, उसका कोई असर नहीं होगा। उन्हें अपनी पार्टी पर ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जनता राज्य में तृणमूल कांग्रेस के कुशासन के लिए उनसे जवाब मांग रही है। भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि एक महीने के अंदर ही हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। ममता बनर्जी ने कभी नहीं सोचा था कि लोगों के लिए उन्होंने जो मुश्किलें खड़ी की थीं, वे इतनी जल्दी जनता के गुस्से के रूप में उनकी पार्टी के सामने वापस आ जाएंगी। आज, वह एक विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही हैं।

अगर उनकी पार्टी ने इतने सालों तक लोगों के लिए काम किया होता तो शायद आज ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होती।

रक्षा मंत्री से मिले नए सीडीएस और नौसेना प्रमुख, सैन्य नेतृत्व के नए दौर की शुरुआत

नई दिल्ली। हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) का दायित्व संभालने वाले जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की है।

गौरतलब है कि यह दोनों शीर्ष सैन्य नियुक्तियां ऐसे समय में हुई है जब भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बनाने, तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता बढ़ाने और आत्मनिर्भर रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी ने 31 मई को देश के सर्वोच्च सैन्य पदों में से एक, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यभार संभाला है। यह पद तीनों सेनाओं यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और संयुक्त सैन्य रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

सीडीएस के पास चार दशक से अधिक का सैन्य अनुभव है और उन्होंने देश के विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई हैं। सीडीएस बनने के बाद मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से यह उनकी पहली औपचारिक मुलाकात रही। सीडीएस के रूप में जनरल एन. एस. राजा सुब्रमणी की प्राथमिकताओं में सैन्य आधुनिकीकरण, नई तकनीकों का समावेश, भविष्य के युद्धक्षेत्रों के अनुरूप तैयारी, संयुक्त थिएटर कमांड की दिशा में प्रगति तथा स्वदेशी रक्षा प्रणालियों को बढ़ावा देना शामिल माना जा रहा है। ऐसे में रक्षा मंत्री के साथ उनकी यह पहली मुलाकात आने वाले समय की रणनीतिक प्राथमिकताओं को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

दूसरी ओर, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने भी मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने भी 31 मई को नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला है। नौसेना में लंबे और विविध अनुभव के साथ, उन्होंने कई महत्वपूर्ण समुद्री अभियानों, परिचालन जिम्मेदारियों और रणनीतिक नियुक्तियों में अपनी भूमिका निभाई है।

वह भारतीय नौसेना के 27वें नौसेना प्रमुख बने हैं। बतौर नौसेना प्रमुख, उनकी भी रक्षा मंत्री से यह पहली आधिकारिक मुलाकात है।

संक्षिप्त खबरें

बांका में सर्वे अमीन रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार

पटना। बिहार में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रखा है। इस बीच, विभाग की एक टीम ने मंगलवार को बांका जिले के चांदन अंचल कार्यालय में एक सर्वे अमीन को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। निगरानी विभाग के मुताबिक, बांका जिले के दिग्घिवारी गांव के रहने वाले दिनेश मंडल ने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि सर्वे अमीन आदित्य कुमार जमीन के सर्वे करने के समय रुपये की मांग की थी। जब राशि नहीं दी गई, तब उन्होंने जमीन के कागजात, पर्चा में नाम, जाति, चौहदी, रकबा एवं खेसरा में जानबूझकर त्रुटि अंकित कर दी थी। इन अशुद्धियों को सुधारने के एवज में अब फिर से रिश्वत की मांग की जा रही है। ब्यूरो द्वारा प्राप्त शिकायत का सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम में आरोपी द्वारा रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया।

'सलमान खान को कोर्ट में ही जवाब देंगे', 'काला हिरण' विवाद पर निर्माता अमित जानी का पलटवार

मुंबई। फिल्म 'काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी' को लेकर छिड़ा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान द्वारा फिल्म के मेकर्स को भेजे गए लीगल नोटिस के बाद अब निर्माता अमित जानी ने खुलकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आईएएनएस से बातचीत में अमित जानी ने कहा कि यदि सलमान खान इस मामले को अदालत तक ले जाना चाहते हैं, तो वह उन्हें कोर्ट में ही जवाब देंगे। उन्होंने दावा किया कि उनकी फिल्म न तो सलमान खान पर आधारित है और न ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर, बल्कि यह बिश्नोई समाज के उन लोगों की कहानी है, जिन्होंने अपने अधिकारों और न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। आईएएनएस से बात करते हुए अमित जानी ने कहा, 'फिल्म का अभी तक न तो टीजर रिलीज हुआ है और न ही ट्रेलर सामने आया है। जब किसी ने फिल्म देखी ही नहीं है, तो उसके कंटेंट को लेकर आपत्ति कैसे जताई जा सकती है? अगर सलमान खान सीधे उनसे बातचीत करते और फिल्म की कहानी के बारे में पूछते, तो मैं विस्तार से समझा देता कि फिल्म का वास्तविक विषय क्या है।'

नोएडा सेक्टर-16 मेट्रो स्टेशन पर बड़ा हादसा टला, मेट्रो के सामने कूदा व्यक्ति

नोएडा। नोएडा के सेक्टर-16 मेट्रो स्टेशन पर मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक व्यक्ति अचानक मेट्रो के सामने ट्रैक पर पहुंच गया। समय रहते मेट्रो स्टाफ और पुलिस की सतर्कता के चलते एक बड़ा हादसा टल गया और व्यक्ति की जान बचा ली गई।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली की ओर जा रही मेट्रो संख्या 7449 जैसे ही सेक्टर-16 मेट्रो स्टेशन पर पहुंचने वाली थी, तभी एक व्यक्ति अचानक ट्रैक पर कूद गया। घटना को देखते ही मेट्रो के चालक और स्टेशन पर मौजूद कर्मचारियों ने तत्काल कार्रवाई की। ट्रेन को तुरंत रोका गया और आपातकालीन सुरक्षा प्रक्रिया लागू कर दी गई।

घटना के बाद स्टेशन परिसर में कुछ समय के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो को खाली कराया गया और स्टेशन पर मौजूद लोगों को बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद मेट्रो स्टाफ और स्थानीय पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से ट्रैक पर पहुंचे व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि संबंधित व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रहा है। उसकी उम्र लगभग 50 से 60 वर्ष के बीच बताई जा रही है।

फिलहाल, पुलिस व्यक्ति की पहचान करने और घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। उससे पूछताछ की जा रही है तथा उसके परिजनों का पता लगाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस घटना के कारण कुछ समय के लिए मेट्रो सेवाएं प्रभावित रहीं। हालांकि, सुरक्षा जांच और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद मेट्रो संचालन को सामान्य कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्टेशन पर निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा।

यह पूरा मामला नोएडा के थाना फेज-1 क्षेत्र स्थित सेक्टर-16 मेट्रो स्टेशन का है। समय रहते की गई कार्रवाई के चलते एक संभावित बड़ा हादसा टल गया, जिससे यात्रियों और मेट्रो प्रशासन ने राहत की सांस ली।

गुजरात सरकार का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 6 अधिकारियों को मिला अतिरिक्त प्रभार

गांधीनगर। गुजरात सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने तत्काल प्रभाव से एक आदेश जारी कर छह वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी हैं। यह निर्णय उन पदों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लिया गया है, जहां संबंधित आईएएस अधिकारी हाल ही में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जारी आदेश के अनुसार, वर्तमान में गांधीनगर स्थित गुजरात स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसायटी (जीएसटीडीआरईआईएस) के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजय के. मोदी को गुजरात ट्राइबल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, गांधीनगर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे यह जिम्मेदारी सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सीबी बलात के स्थान पर संभालेंगे। इसी तरह, अतिरिक्त विकास आयुक्त योगेश बी. निरगुडे (आईएएस) को गांधीनगर के जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। यह पद बीजे पटेल के सेवानिवृत्त होने के बाद खाली हुआ था। रचित राज, निदेशक अनुसूचित जाति कल्याण, गांधीनगर को गुजरात अनरिजर्व्ड एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (जीयूईडीसी) के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। वे पीडी पलसाना के स्थान पर यह जिम्मेदारी निभाएंगे।

स्किल इंडिया मिशन से महिलाओं को मिल रही सशक्त पहचान, आरसेटी के प्रशिक्षण से बन रहीं आत्मनिर्भर

प्रयागराज। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने का काम ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) द्वारा किया जा रहा है, जहां महिलाओं को विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है।

आरसेटी में महिलाओं और युवतियों को न केवल विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि प्रशिक्षण के बाद उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए मार्गदर्शन और आर्थिक सहायता की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है। संस्थान का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षुओं को इस योग्य बनाना है कि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें। प्रधानमंत्री के 'स्किल इंडिया' विजन के तहत आरसेटी का प्रमुख फोकस स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एंप्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। संगम नगरी प्रयागराज स्थित आरसेटी केंद्र में वर्तमान समय में 35 दिवसीय 'जूनियर ब्यूटी प्रैक्टिशनर' (लघु उद्यमी) प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में 33 महिला अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद महिलाएं अपने घर से ही ब्यूटी सेवाएं प्रदान कर सकती हैं या स्वयं का ब्यूटी पार्लर खोलकर रोजगार शुरू कर सकती हैं। इस केंद्र की एक विशेषता यह भी है कि यहां बाहर से आने वाली प्रशिक्षुओं के लिए रहने की व्यवस्था उपलब्ध है।

झारखंड में नशे के खिलाफ अभियान तेज, गोड्डा और चतरा में लाखों रुपए की ब्राउन शुगर के साथ चार तस्कर गिरफ्तार

चतरा/गोड्डा। झारखंड में नशीले पदार्थों के कारोबार के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। गोड्डा और चतरा जिलों में अलग-अलग कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लाखों रुपए की ब्राउन शुगर के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया।

चतरा के डीएसपी मुख्यालय सुनील कुमार सिंह ने मंगलवार को बताया कि जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के जपुआ मैदान के समीप ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री की गुप्त सूचना मिली थी। इसके बाद अंचल अधिकारी अनंत शयनम विश्वकर्मा और थाना प्रभारी पुरुषोत्तम अग्निहोत्री के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान जपुआ निवासी दीपक कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से 44 ग्राम ब्राउन शुगर और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस के अनुसार, जब्त ब्राउन शुगर की कीमत करीब नौ लाख रुपए है। जांच के दौरान मोबाइल से मिले व्हाट्सएप चैट और तस्वीरों को भी साक्ष्य के रूप में संकलित किया गया है। इधर, गोड्डा जिले में पुलिस ने प्रतापपुर हटिया के पास छापेमारी कर 2.78 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान खटनई निवासी सत्यजीत पासवान (19), गौरव कुमार (22) और बालमुकुंद साह (40) के रूप में हुई है।

पत्नी की पीठ पर बैठकर सीएम से मिलने पहुंचा दिव्यांग

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी ने कोलकाता में भाजपा कार्यालय में जनता दरबार लगाया। इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस दौरान एक मार्मिक तस्वीर देखने को मिली, जहां चलने-फिरने में असमर्थ एक दिव्यांग व्यक्ति अपनी पत्नी की पीठ पर बैठकर मुख्यमंत्री तक अपनी फरियाद लेकर पहुंचा।

संघर्ष और बेबसी की इस तस्वीर ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया। दिव्यांग शख्स सीएम से मुलाकात करने पहुंचा। सीएम ने उससे मुलाकात की और सात दिन के भीतर मदद करने का भरोसा दिया।

भाजपा पार्टी ऑफिस में आयोजित इस जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। जिनकी समस्याओं को सीधे सीएम सुवेंदु अधिकारी ने खुद सुना। इस जनता दरबार में एक दिव्यांग शख्स भी पहुंचा था, जो चलने में असमर्थ था। उसने पूर्व की ममता सरकार पर कोई भी सुविधा न देने का आरोप लगाते हुए सीएम से मदद की गुहार लगाई।

दिव्यांग शख्स अपनी पत्नी की मदद से जनता दरबार में पहुंचा था। उसने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं एक बेसहारा व्यक्ति हूं। मुझे बैटरी से चलने वाले वाहन की जरूरत है। मैं दिव्यांग हूं। हमें 'लक्ष्मी भंडार' योजना के तहत भी कोई लाभ नहीं मिला है, और मुझे एक घर की भी जरूरत है। मैं सीएम के पास मदद की गुजारिश लेकर आया था। सीएम ने कहा कि यह काम हो जाएगा और सात दिन के भीतर मेरी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। जनता दरबार में कलाकार रिद्धि बंदोपाध्याय नाम की महिला भी पहुंची थी। उन्होंने कहा कि पहले कुछ बोलना भी ठीक नहीं लगता था, लेकिन अब हम सीएम से मिले और उनसे मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि मैं पूरे विश्व में गाना जाती हूं। हम लोगों की आवाज उठाते हैं। मैं मुख्यमंत्री के पास मदद के लिए आई थी, उन्होंने मुझे मदद करने का आश्वासन दिया है। अब हम खुलकर बोल पा रहे हैं, पहले हम नहीं बोल सकते थे। मैंने 15 साल तक परेशानी को झेला है। एक अन्य बुजुर्ग महिला ने कहा कि मैं एक मामले की सीबीआई जांच में तेजी की मांग को लेकर आई थी। सीएम ने कहा कि मैं इस मामले में डायरेक्ट कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस मामले पर विचार करूंगा और जो भी संभव होगा, जरूर किया जाएगा।

प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर: वैश्विक प्रतिभाओं को भारतीय शोध से जोड़ने की पहल

नई दिल्ली। भारत सरकार ने देश में विज्ञान, रिसर्च और नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर (पीएमआरसी) योजना 2026 शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य दुनिया के अलग-अलग देशों में काम कर रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों और रिसर्च संस्थानों से जोड़ना है।

प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर योजना के अंतर्गत अनुसंधान और नवाचार को देश की रणनीतिक आवश्यकताओं से जोड़ते हुए 13 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें उन्नत कंप्यूटिंग (एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सुपरकंप्यूटिंग), सेमीकंडक्टर, ऊर्जा एवं जलवायु परिवर्तन को शामिल किया गया है। इनके अलावा, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं मेडिकल प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, उन्नत सामग्री एवं महत्वपूर्ण खनिज, अंतरिक्ष एवं रक्षा भी इसका हिस्सा हैं। वहीं, इसमें अगली पीढ़ी की संचार तकनीक, मैन्युफैक्चरिंग एवं इंडस्ट्री 4.0, कृषि एवं खाद्य प्रौद्योगिकी, ब्लू इकोनॉमी तथा परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्र भी शामिल हैं। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए देश के सात प्रतिष्ठित संस्थानों को लीड संस्थान के रूप में चुना गया है। इनमें आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी धनबाद तथा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शामिल हैं।

संक्षिप्त खबरें

युवा उद्यमियों को मार्गदर्शन देने माहेश्वरी बिजनेस कनेक्ट का सेमिनार संपन्न

रायपुर। माहेश्वरी समाज के युवा उद्यमियों एवं व्यापारियों को मार्गदर्शन देने आज राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित विमतारा में सेमिनार का आयोजन किया गया है, उक्त जानकारी देते हुए कार्यक्रम आयोजक निलेश मुंदडा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आर.आर. केबल के चेयरमैन त्रिभुवन प्रसाद काबरा उपस्थित हुए। वही अखिल भारतवर्षीय युवा संगठन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार काल्या एवं पूर्व युवा राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण सोमानी सहित कमल ऑयल के सुनील मुंदडा,आरती ग्रुप के चेयरमैन छगन मुंदडा, श्रीराम फाइनेंस कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर गणेश भट्टड़, आनंद इंफ्रास्ट्रक्चर के एमडी चतुर्भुज राठी, इन्लैंड वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स के एमडी प्रवीण सोमानी व शुभम पॉलिस्पिन के फाउंडर अनिल सोमानी युवा व्यापारियों को बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हो रही चुनौतियों से निपटने के रास्ते एवं सफल उद्योग संचालित करने हेतु विशेष मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु प्रमुख रूप से राजीव मुंदडा,अशोक मुंदडा,राज बागड़ी, सीए अमित राठी, गौरव दम्मानी, कृष्णा लखोटिया, राकेश सोमानी, ललित सोमानी,रमेश झांवर, ऋषभ चांडक, शरद सारडा,कृतिका नत्थानी, विद्या काबरा, प्रदीप माहेश्वरी, सिद्धांत डागा, देवेश बागड़ी का विदेश योगदान रहा। कार्यक्रम में तकरीबन 300 से अधिक माहेश्वरी युवाओं उद्यमी शामिल हुए, जहां बड़ी संख्या में महिला उद्यमी भी उपस्थित रही। कार्यक्रम का उद्देश्य माहेश्वरी समाज के युवाओं को व्यापार में सफलता प्राप्त करने में मदद करना एवं कठिनाइयों को बारीकी से समझ उसका हल निकाल अपने ब्रांड को बड़ा बनाना है।

पत्रकारिता विश्वविद्यालय में अभाविप का प्रदर्शन, कुलपति कार्यालय का घेराव

बर्खास्त प्राध्यापक की कथित 'बैकडोर एंट्री', ऑडिटोरियम निर्माण में भ्रष्टाचार एवं छात्र समस्याओं पर जताई नाराजगी

रायपुर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर में व्याप्त प्रशासनिक अनियमितताओं, छात्र विरोधी नीतियों एवं भ्रष्टाचार के आरोपों के विरोध में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में प्रदर्शन एवं कुलपति कार्यालय का घेराव किया गया। अभाविप ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सेवा समाप्ति की कार्यवाही के बावजूद पूर्व एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. शाहिद अली को बिना किसी वैधानिक आदेश के पुन: विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया गया है। साथ ही वर्ष 2019 में डॉ. शैलेन्द्र खण्डेलवाल की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी प्रश्न उठाते हुए इसकी जांच की मांग की गई। परिसर में लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित नए ऑडिटोरियम की जड़ जड़ हालत हो चुकी है संभवत: निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार की आशंका व्यक्त की तथा इसकी उच्च स्तरीय तकनीकी जांच की मांग की। प्रदर्शन के दौरान अभाविप कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय में कोर्सों के नाम परिवर्तित किए जाने से उत्पन्न भ्रम, परीक्षा अवधि में लगातार विद्युत बाधित होने, छात्रावास में दूषित पेयजल, मेस की निम्न गुणवत्ता, खेल सुविधाओं के अभाव, बस परिवहन की अव्यवस्था एवं विद्यार्थियों के लिए स्टूडियो सुविधाओं के उपयोग न होने जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया।

बोरियाखुर्द में आरसीसी नाली निर्माण कार्य शीघ्र होगा प्रारंभ

रायपुर। रायपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) की बोरियाखुर्द स्थित डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना के रहवासियों की वर्षों पुरानी मांग अब पूरी होने जा रही है। योजना क्षेत्र में आरसीसी नाली निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होगा, जिसके लिए आरडीए द्वारा निविदा (टेंडर) जारी कर दी गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2009 में निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए इस योजना के अंतर्गत लगभग 1800 आवासों का निर्माण किया गया था। उस समय निर्मित नालियां समय के साथ जर्जर एवं क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण क्षेत्र में जल निकासी की समस्या उत्पन्न होने लगी। योजना के रहवासियों एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा नालियों के पुनर्निर्माण की मांग लगातार उठाई जा रही थी। हालांकि संबंधित मद में राशि बकाया होने के कारण आरडीए द्वारा लंबे समय तक यह कार्य नहीं कराया जा सका। अब प्रदेश के आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चैधरी तथा आरडीए अध्यक्ष नंदकुमार साहू के प्रयासों से प्राधिकरण ने अपने स्वयं के व्यय से नाली निर्माण कार्य कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और प्रक्रिया पूर्ण होते ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।

नाली निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद योजना क्षेत्र के हजारों रहवासियों को गंदगी एवं दुर्गंध की समस्या से राहत मिलेगी। साथ ही जल निकासी व्यवस्था में सुधार होने से क्षेत्र की स्वच्छता एवं नागरिक सुविधाओं में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

मानसून से पहले 333 करोड़ के धान पर संकट

चार महीने बाद भी खरीदी केंद्रों में पड़ा 10.76 लाख क्विंटल अनाज

रायपुर (संवाददाता)। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी समाप्त हुए चार महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन प्रदेश के सैकड़ों खरीदी केंद्रों में अब भी 10.76 लाख क्विंटल से अधिक धान पड़ा हुआ है। मानसून की दस्तक के बीच यह स्थिति चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि समय रहते उठाव नहीं होने पर करोड़ों रुपए मूल्य का धान खराब होने का खतरा बढ़ गया है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार खरीदी केंद्रों में अभी भी 7,48,310 क्विंटल मोटा धान, 1,21,020 क्विंटल पतला धान और 2,07,250 क्विंटल सरना धान परिवहन की प्रतीक्षा में है। समर्थन मूल्य के आधार पर इस धान की कुल कीमत 333.74 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। बारिश शुरू होने के बाद खुले में रखे धान की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका है, जिससे शासन को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।

प्रदेश में वर्ष 2025-26 के दौरान रिकॉर्ड 14.10 करोड़ क्विंटल धान की खरीदी की गई थी। इसमें से 12.34 करोड़ क्विंटल धान राइस मिलर्स को और 1.65 करोड़ क्विंटल धान संग्रहण केंद्रों में भेजा गया। नियमानुसार 31 मार्च तक खरीदी केंद्रों से धान का पूरा उठाव हो जाना चाहिए था, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने समय सीमा बढ़ाकर 31 मई कर दी। इसके बावजूद लाखों क्विंटल धान अब भी केंद्रों में जमा है।

राजनांदगांव जिले की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। जिले की 96 समितियों में से 79 समितियों में अब भी करीब 56 हजार क्विंटल धान का उठाव नहीं हो पाया है। इस धान की अनुमानित कीमत 17 करोड़ रुपए बताई जा रही है। फरवरी से खुले में रखा धान लगातार धूप, नमी और बेमौसम बारिश का सामना कर रहा है, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है।

वहीं बस्तर संभाग में स्थिति और भी गंभीर है। प्रशासन ने धान उठाव की जिम्मेदारी 165 राइस मिलर्स को सौंपी थी, लेकिन निर्धारित अवधि बीतने के बाद भी लगभग 200 खरीदी केंद्रों में 4 लाख 56 हजार क्विंटल धान पड़ा हुआ है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से इसकी कीमत लगभग 141 करोड़ रुपए है। स्थानीय स्तर पर मिलर्स की धीमी कार्यप्रणाली और परिवहन व्यवस्था की चुनौतियों को इसके लिए जिम्मेदार माना जा रहा है।

छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स एसोसिएशन का कहना है कि शेष धान के लिए डिलीवरी ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं। बस्तर क्षेत्र में एक साथ बड़ी मात्रा में डिलीवरी ऑर्डर जारी होने के कारण परिवहन वाहनों की कमी महसूस की जा रही है। इसके अलावा लंबी दूरी तक धान परिवहन करने के लिए पर्याप्त ट्रकों की उपलब्धता भी चुनौती बनी हुई है। उन्होंने दावा किया कि 15 जून तक सभी केंद्रों से धान का उठाव पूरा कर लिया जाएगा।

हालांकि मानसून के नजदीक आते ही किसानों, समितियों और प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। यदि समय रहते धान का उठाव नहीं हुआ तो करोड़ों रुपए मूल्य की उपज को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में अब सभी की नजरें प्रशासन और राइस मिलर्स पर टिकी हैं कि वे बारिश से पहले इस बड़ी चुनौती का समाधान किस तरह करते हैं।

स्टील प्लांट का बॉयलर फटा, मची अफरा-तफरी

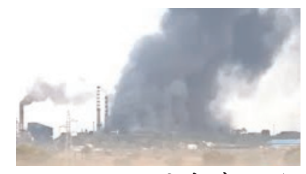

रायपुर। रायपुर जिले के आरंग स्थित मिवान (मोनेट) स्टील प्लांट में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। सुबह करीब 5 बजे प्लांट का बॉयलर अचानक फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास के गांवों तक इसकी आवाज सुनाई दी और लोग दहशत में आ गए। धमाके के कुछ ही मिनटों में प्लांट के अंदर भीषण आग भड़क उठी। देखते ही देखते आसमान में काले धुएं का बड़ा गुबार छा गया। घटना की खबर फैलते ही इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां और पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। जिला प्रशासन के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। राहत की बात यह है कि फिलहाल किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं मिली है। हालांकि बॉयलर फटने की वजह क्या थी, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया।

समितियों और निजी विक्रेताओं के पास खाद का पर्याप्त भंडार, किसानों को निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित

रायपुर। खरीफ सीजन 2026 के मद्देनजर बिलासपुर जिले में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कलेक्टर संजय अग्रवाल द्वारा प्रतिदिन खाद-बीज की उपलब्धता, भंडारण एवं वितरण की समीक्षा की जा रही है। जिले की 114 सहकारी समितियों तथा निजी उर्वरक विक्रेताओं के माध्यम से किसानों को खाद उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि विभाग के अनुसार जिले में वर्तमान में खाद का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और मांग के अनुरूप निरंतर वितरण किया जा रहा है।

उप संचालक कृषि से प्राप्त जानकारी के अनुसार खरीफ 2026 के लिए जिले को 68,950 टन रासायनिक उर्वरकों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके विरुद्ध अब तक 46,780 टन से अधिक उर्वरकों का भंडारण किया जा चुका है, जो लक्ष्य का लगभग 60.28 प्रतिशत है। वहीं किसानों को अब तक 19,912 टन से अधिक उर्वरकों का वितरण किया जा चुका है। जिले में वर्तमान में कुल 41,560 टन उर्वरक का भंडार उपलब्ध है। इनमें यूरिया 22,996 टन, डीएपी 5,621 टन, एनपीके 6,808 टन, एसएसपी 4,981 टन तथा एमओपी 1,155 टन शामिल है।

विधायक पर एफआईआर, गिरफ्तारी की मांग पर अड़े प्रदेशभर के तहसीलदार, तूता में किया प्रदर्शन

रायपुर (संवाददाता)। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। नायब तहसीलदार से कथित मारपीट के मामले में विधायक समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार हड़ताल पर हैं। सरकार और प्रशासनिक संघ के बीच हुई वार्ता भी बेनतीजा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया गया है।

सरगुजा जिले के सीतापुर मे 27 मई को नायब तहसीलदार तुषार मानिक के साथ कथित मारपीट के मामले में बीजेपी विधायक रामकुमार टोप्पो और उनके 10 समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस घटना के विरोध में प्रदेशभर के तहसीलदार और नायब तहसीलदार आंदोलन पर उतर आए हैं। वहीं कनिष्ठ प्रशासनिक संघ के प्रांत अध्यक्ष कृष्ण कुमार लहरे ने बताया कि मंत्री और राजस्व सचिव के साथ हुई चर्चा में कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इधर, विधायक रामकुमार टोप्पो ने शुक्रवार को सरगुजा आईजी के समक्ष गिरफ्तारी देने की बात कही थी। इसके लिए वे समर्थकों के काफिले के साथ अंबिकापुर के लिए रवाना हुए, लेकिन मंगारी में समर्थकों द्वारा रोके जाने के बाद वापस सीतापुर लौट गए। विधायक देर रात तक रेस्ट हाउस में समर्थकों के साथ मौजूद रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया भी सीतापुर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बताया कि मामला मुख्यमंत्री और प्रदेश नेतृत्व तक पहुंच चुका है और आगे का फैसला शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा। इसके बाद विधायक और समर्थकों ने फिलहाल किसी भी शक्ति प्रदर्शन कार्यक्रम से दूरी बना ली है। नायब तहसीलदार से मारपीट के आरोपों को लेकर शुरू हुआ यह विवाद अब प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर बड़ा मुद्दा बन गया है। एक ओर प्रशासनिक अधिकारी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं, तो दूसरी ओर सभी की नजरें सरकार और पार्टी नेतृत्व की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

164 दिनों से धरने पर बैठे सीएएफ अभ्यर्थी

बोले- अब आश्वासन नहीं नियुक्ति आदेश चाहिए

रायपुर (संवाददाता)। सीएएफ भर्ती 2018 के वेटिंग सूची में शामिल अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 164 दिनों से राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। सात वर्षों से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकारें बदल गईं, लेकिन उनकी किस्मत नहीं बदली।

धरनारत अभ्यर्थियों ने बताया कि वर्ष 2018 में भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी वेटिंग सूची के 417 अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी है। उनका आरोप है कि चुनावों के दौरान युवाओं को न्याय और रोजगार देने के वादे किए गए, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।

अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कई बार शासन और प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला। अब वे किसी भी प्रकार के आश्वासन के बजाय लिखित नियुक्ति आदेश की मांग कर रहे हैं। धरना स्थल पर मौजूद अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने राज्य सरकार से जल्द निर्णय लेकर लंबित नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने की मांग की है।

कलेक्ट्रेट में जनदर्शन के दौरान शख्स ने की आत्मदाह की कोशिश

मचा हड़कंप, इच्छामृत्यु की मांग कर रहा था

रायपुर। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिला कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब जनदर्शन कार्यक्रम में पत्नी और दो बच्चो के साथ अपनी शिकायत लेकर पहुंचे एक शख्स ने मिट्टी तेल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। युवक को तत्काल रोककर सुरक्षित किया गया।

जानकारी के अनुसार, युवक की पहचान रोहित सोनी के रूप में हुई है, जो धमतरी शहर के पोस्ट ऑफिस वार्ड स्थित साई बाबा मंदिर के पास का निवासी है। रोहित ने कलेक्टर को सौंपे गए आवेदन में परिवार सहित इच्छा मृत्यु की अनुमति मांगी है। उसका आरोप है कि वह और उसका परिवार पिछले करीब 60 वर्षों से बढ़ेश्वर महादेव मंदिर के समीप अपने मकान में निवास कर रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में मंदिर से जुड़े कुछ लोगों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा उसे लगातार परेशान किया जा रहा है। रोहित सोनी ने आवेदन में आरोप लगाया है कि जब वह अपने मकान का निर्माण कार्य करा रहा था, तब 10 से 20 लोगों का समूह उसके निर्माणाधीन घर में घुस आया और काम बंद करा दिया। आरोप है कि उसे घर छोड़कर कहीं और चले जाने के लिए दबाव बनाया गया। युवक का कहना है कि उसे धमकी दी गई कि यदि उसने मकान नहीं छोड़ा तो उसके लिए स्थिति ठीक नहीं होगी।आवेदन में रोहित ने भाजपा पार्षद निलेश लुनिया और उनके कुछ साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

लिंगो मुदियाल कृषि महा. नारायणपुर को मिला 'पर्यावरण चैंपियन अवार्ड 2026'

100 से अधिक नामांकनों में देश की चुनिंदा 9 संस्थाओं में बनाया स्थान, छत्तीसगढ़ को मिला राष्ट्रीय गौरव

रायपुर। पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन, जैव विविधता संरक्षण, जैविक कृषि, वृक्षारोपण, नशामुक्ति जागरूकता एवं जनसहभागिता आधारित पर्यावरणीय अभियानों में उत्कृष्ट एवं नवाचारपूर्ण कार्यों के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के अधीनस्थ लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, नारायणपुर को कल देहरादून में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित 'पर्यावरण चैंपियन अवार्ड 2026' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित नमामि गंगे परियोजना तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में प्रदान किया गया। देशभर से प्राप्त 100 से अधिक नामांकनों में से कठोर मूल्यांकन एवं बहुस्तरीय चयन प्रक्रिया के पश्चात केवल 9 संस्थाओं को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया, जिनमें एक विश्वविद्यालय, पांच विद्यालय एवं तीन महाविद्यालय शामिल थे।

सम्मानित संस्थाओं में बिहार, झारखंड, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि शामिल थे। चयनित संस्थाओं में उत्तराखंड का सुप्रसिद्ध सामुदायिक रेडियो 'रेडियो केदार' भी सम्मिलित रहा। ऐसे राष्ट्रीय स्तर के प्रतिस्पर्धी मंच पर नारायणपुर महाविद्यालय का चयन संस्था के उत्कृष्ट पर्यावरणीय कार्यों की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। समारोह के दौरान सभी चयनित प्रतिभागियों एवं संस्थाओं द्वारा पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, जैव विविधता संवर्धन, वृक्षारोपण एवं जनजागरूकता के क्षेत्र में किए गए कार्यों की वीडियो प्रस्तुति प्रदर्शित की गई। लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय, नारायणपुर द्वारा प्रस्तुत गतिविधियों एवं उपलब्धियों को उपस्थित विशेषज्ञों, पर्यावरणविदों एवं प्रतिभागियों द्वारा विशेष सराहना प्राप्त हुई। लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय को यह सम्मान ट्रॉफी एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर दिया गया। यह सम्मान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री कल्याण सिंह रावत, प्रख्यात पर्यावरणविद्, मैती आंदोलन के प्रणेता एवं जल-जंगल-जमीन संरक्षण के राष्ट्रीय प्रेरणास्रोत, तथा विशिष्ट अतिथि पद्मश्री मधुरी बर्थवाल, सुप्रसिद्ध लोकगायिका, लोकसंस्कृति संवाहक एवं उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत की सशक्त प्रतिनिधि के करकमलों से प्रदान किया गया।

छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बालिकाओं के लापता होने की स्थिति बेहद चिंताजनक : अमित जोगी

रायपुर (संवाददाता)। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के अध्यक्ष अमित जोगी ने राज्य में महिलाओं और बच्चियों के लापता होने के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बालिकाओं के लापता होने की स्थिति बेहद चिंताजनक है और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए।

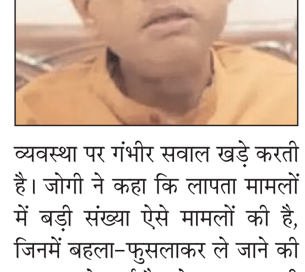

अमित जोगी ने जारी बयान में दावा किया कि राज्य में 96 हजार से अधिक महिलाएं और बालिकाएं लापता हुई हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन करीब 30 महिलाएं और 10 से 12 नाबालिग बच्चियां लापता हो रही हैं। उनके अनुसार, हर दो घंटे में एक बच्ची के गायब होने की स्थिति प्रदेश की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जोगी ने कहा कि लापता मामलों में बड़ी संख्या ऐसे मामलों की है, जिनमें बहला-फुसलाकर ले जाने की बात सामने आई है, जो मानव तस्करी की आशंका को मजबूत करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि हजारों परिवार आज भी अपने परिजनों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने बेटा बचाओ आंदोलन शुरू किया है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे को नजरअंदाज किया जाए। उन्होंने कहा कि बेटों के साथ-साथ बेटियों की सुरक्षा भी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अमित जोगी ने सरकार से मांग की कि लापता महिलाओं और बच्चों के मामलों पर श्वेत पत्र जारी किया जाए, 90 दिनों के भीतर सभी मामलों की अनिवार्य समीक्षा और जांच कराई जाए, प्रत्येक जिले की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट को सक्रिय किया जाए तथा पुराने अनट्रेस्ड मामलों की विशेष टास्क फोर्स के माध्यम से समीक्षा की जाए। इसके अलावा पीड़ित परिवारों को मुआवजा, सहायता और न्याय उपलब्ध कराने की भी मांग की।

संपादकीय

कमजोर मानसून तो महंगाई का लगेगा तड़का, अर्थव्यवस्था होगी प्रभावित

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

मौसम विभाग द्वारा 29 मई को जून से सितंबर मानसून के दौरान 10 प्रतिशत कम बरसात का पूर्वानुमान बेहद चिंताजनक का कारण बन गया है। इससे पहले जारी पूर्वानुमान में 8 प्रतिशत कम बरसात की संभावना व्यक्त की गई थी। लगभग दस साल बाद देश में कमजोर मानसून के हालात रहने की संभावना है। अर्थव्यवस्था के लिए यह इसलिए और भी अधिक चिंतनीय हो जाता है कि एक और अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच सीजफायर के आसार नहीं दिख रहे हैं और इसके कारण भारत सहित दुनिया के अधिकांश देश कच्चे तेल और गैस की समस्या से दो चार हो रहे हैं और इसका सीधा असर महंगाई बढ़ना हो रहा है। दूसरी और अब अलनीनों के प्रभाव से इस साल कमजोर मानसून के कारण 10 प्रतिशत कम बरसात होने से हालात ओर भी गंभीर होने की संभावना बनती जा रही है। करीब दस साल बाद ऐसे हालात बनने जा रहे हैं। खास बात यह है कि उत्तर पूर्व को छोड़कर समूचे देश में कम बरसात की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को इसलिए भी नहीं नकारा जा सकता है कि पिछले सालों में भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान लगभग सटीक रहने लगे हैं। मजे की बात यह है कि इस साल गर्मी भी भीषण पड़ रही है और पिछले एक माह में ही जलाशयों में उपलब्ध पानी में तेजी से कमी आई है। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश

के प्रमुख 166 जलाशयों में कुल भराव क्षमता का 24 प्रतिशत के आसपास ही पानी रह गया है और तेजी से पानी कम होता जा रहा है। दक्षिण भारत के हालात अधिक गंभीर है और वहां लगभग 17 प्रतिशत ही पानी रह गया है। उत्तरी भारत के जलाशयों में 26 तो पश्चिमी भारत के जलाशयों में 28 प्रतिशत के आसपास ही पानी रह गया है। मानसून भी तय समय से विलंबित हो रहा है।

एक बात साफ हो जानी चाहिए कि हमारी अर्थव्यवस्था मानसूनी बरसात पर बहुत कुछ निर्भर करती है। देश में मानसून सीजन में 87 सेमी बरसात होती है। पूर्वानुमानों को माने तो 2018 में 91 प्रतिशत बरसात हुई थी उसके बाद के सालों में मानसून लगभग अच्छा ही रहा है। पिछले सालों में मानसून की स्थिति देखें तो 2023 में मानसून अवश्य कमजोर रहा है अन्यथा देश में मानसूनी वर्षा 100 प्रतिशत के आसपास व इससे अधिक ही रही है। कमजोर मानसून के कारण भूजल स्तर में गिरावट, अधिक पानी पर निर्भर धान, तिलहन और दलहन की फसल प्रभावित होगी और इस कारण से खाद्य महंगाई बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इससे आम आदमी की थाली पर असर पड़ेगा और सब्जी, दाल और अनाज सभी के भाव बढ़ने का असर दिखाई देगा। इसी तरह से देश के अनेक हिस्सों में पीने के पानी की दिक्कत आम है। बांधों में तेजी से पानी की कमी और मानसून कमजोर रहने से पानी की कम आवक रहती है तो निश्चित रुप से सिंचाई व पेयजल दोनों के लिए पानी की दिक्कत होगी। जल विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन पर असर होगा तो कुल मिलाकर अर्थ व्यवस्था को प्रभावित होने से कोई नहीं रोक सकता।

दरअसल देश में एक समय था जब सूखा आम होता था और व्यापक स्तर पर अकाल राहत कार्य संचालित होते थे। हांलाकि देश के हालातों में काफी सुधार हुआ है और अकाल को तो लगभग भूल ही चुके हैं। पर सवाल वहीं का वहीं है कि जल संचयन के जो प्रयास होने चाहिए थे और उनका जिस तरह का प्रभाव पड़ना चाहिए था वह अभी तक सामने नहीं आया है। सरकार के सामने कमजोर मानसून के हालात से निपटने की बड़ी चुनौती आने वाली है। सबसे अधिक तो जल संग्रहण की चुनौती होगी क्योंकि प्राकृतिक जल संग्रहण के रास्ते शहरीकरण की भेंट चढ़ चुके हैं। दीर्घकालीन सोच के साथ ठोस प्रयास नहीं होने से बरसात के पानी का सही तरीके से संग्रहण भी नहीं हो पा रहा है। जितने पानी की साल भर आवश्यकता होती है उससे अधिक बरसाती पानी तो बह जाता है। इसके अलावा पानी का उपयोग और दुरुपयोग दोनों ही बढ़ गए हैं। कम पानी से तैयार होने वाली फसलों की क्षेत्रीय विकसित करने में हम अभी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाये हैं। पांच नदियों के प्रदेश पंजाब तक में पानी का संकट होने लगा है। खेती ही नहीं घरेलू जरुरतों में भी पानी का उपयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। टायलेट और कूलरों में पानी की खपत बहुत अधिक बढ़ गई है। जल बचाओ मात्र स्लोगन ही रह गया है और इसका असर दिखाई नहीं देता। इसी तरह से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार तो बहुत किये गये हैं पर उनके निर्माण में जिस तरह की लापरवाही बरती गई है वह किसी से छिपी नहीं हैं। क्योंकि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम कितना सफल रहा है वह सामने है। बाहरमासी नदी नालें तो अब कल्पना की बात हो गए हैं बल्कि बरसाती नदियां भी बरसात में एकाध बार ही पूरे वेग से बहती दिखती है। ऐसे में गंभीरता को तो समझा ही जा सकता है।

कानून, नैतिकता और जीवन के बीच चिकित्सक की दुविधा

डॉ. सत्यवान सौरभ

आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने मानव जीवन की रक्षा, उपचार और संवर्धन के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियाँ हासिल की हैं। आज ऐसे अनेक रोगों का उपचार संभव है जिन्हें कभी असाध्य माना जाता था। गर्भस्थ शिशु की स्वास्थ्य स्थिति का सूक्ष्म परीक्षण, जन्मजात विकृतियों की पहचान तथा मातृ स्वास्थ्य की निगरानी जैसी तकनीकों ने चिकित्सा को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया है। किंतु विज्ञान की इस प्रगति के साथ कुछ जटिल नैतिक और कानूनी प्रश्न भी सामने आए हैं। विशेष रूप से तब, जब चिकित्सकों के सामने ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ कानून की सीमाएँ और जीवन बचाने का उनका मूल कर्तव्य एक-दूसरे से टकराते प्रतीत होते हैं। व्यवहार्य भ्रूणों वाली गर्भावस्थाओं के देर से चिकित्सकीय समापन से जुड़े मामले इसी प्रकार की चुनौतीपूर्ण स्थिति प्रस्तुत करते हैं।

चिकित्सा व्यवसाय का मूल सिद्धांत जीवन की रक्षा करना है। प्राचीन हिप्पोक्रेटिक शपथ से लेकर आधुनिक चिकित्सा नैतिकता तक, चिकित्सकों को रोगी के हित को सर्वोपरि रखने की शिक्षा दी जाती है। 'किसी को हानि न पहुँचाना' और 'रोगी के सर्वोत्तम हित में कार्य करना' चिकित्सा आचारशास्त्र के आधारभूत सिद्धांत हैं। दूसरी ओर, चिकित्सक किसी लोकतांत्रिक समाज में कानून से ऊपर नहीं हो सकते। उन्हें विधिक प्रावधानों, न्यायालयों के आदेशों और राज्य द्वारा निर्धारित मानकों का पालन भी करना पड़ता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब किसी विशेष मामले में कानूनी आदेश और चिकित्सकीय नैतिकता अलग-अलग दिशा में संकेत देने लगते हैं।

भारत में गर्भसमापन से संबंधित कानूनी ढाँचा मुख्य रूप से चिकित्सा गर्भसमापन अधिनियम (Medical Termination of Pregnancy Act) पर आधारित है। समय-समय पर इसमें संशोधन कर महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, स्वास्थ्य सुरक्षा और बदलती चिकित्सकीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। इसके बावजूद अनेक ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें गर्भावस्था उन्नत अवस्था में पहुँच चुकी होती है और भ्रूण व्यवहार्य अर्थात गर्भ के बाहर भी जीवित रहने में सक्षम माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि भ्रूण में गंभीर विकृतियाँ पाई जाएँ, या गर्भवती महिला का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा हो, तो गर्भसमापन का प्रश्न केवल कानूनी नहीं बल्कि गहरे नैतिक विमर्श का विषय बन जाता है।

व्यवहार्य भ्रूणों के संदर्भ में सबसे बड़ी नैतिक चुनौती यह है कि चिकित्सक एक साथ दो जीवनों से संबंधित निर्णय का सामना कर रहे होते हैं। एक ओर गर्भवती महिला की स्वायत्तता, स्वास्थ्य और गरिमा का प्रश्न है, वहीं दूसरी ओर उस भ्रूण का संभावित जीवन है जो चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से जीवित रहने में सक्षम हो सकता है। यदि कानून गर्भसमापन की अनुमति देता है, तब भी चिकित्सक के सामने यह प्रश्न बना रहता है कि क्या वे उस प्रक्रिया में भाग लें जो एक संभावित जीवन का अंत कर सकती है। इसके विपरीत, यदि कानून अनुमति नहीं देता लेकिन महिला का जीवन या मानसिक स्वास्थ्य गंभीर खतरे में है, तो चिकित्सक स्वयं को नैतिक रूप से हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य महसूस कर सकते हैं।

चिकित्सा नैतिकता में रोगी की स्वायत्तता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। प्रत्येक सक्षम वयस्क व्यक्ति को अपने शरीर और स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेने का अधिकार है। गर्भावस्था के मामलों में यह अधिकार विशेष महत्व रखता है क्योंकि गर्भधारण और प्रसव का प्रत्यक्ष प्रभाव महिला के शरीर, स्वास्थ्य और जीवन पर पड़ता है। किंतु व्यवहार्य भ्रूणों की स्थिति में यह अधिकार पूर्णतः निरपेक्ष नहीं रह जाता। समाज और कानून दोनों भ्रूण के संभावित जीवन को भी एक नैतिक मूल्य के रूप में स्वीकार करते हैं। परिणामस्वरूप चिकित्सक महिला की इच्छा और भ्रूण के हितों के बीच

संतुलन बनाने की कठिन जिम्मेदारी का सामना करते हैं।

देर से गर्भसमापन के मामलों में भ्रूण संबंधी गंभीर विकृतियाँ अक्सर निर्णय को और जटिल बना देती हैं। कई बार चिकित्सकीय परीक्षणों से पता चलता है कि भ्रूण ऐसे रोग या विकार से ग्रस्त है जो जन्म के बाद जीवन को अत्यंत कष्टदायक बना देगा अथवा जीवित रहने की संभावना नगण्य होगी। ऐसे मामलों में गर्भावस्था जारी रखना माता-पिता और भावी बच्चे, दोनों के लिए गंभीर मानसिक, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकता है। चिकित्सक यदि गर्भसमापन का समर्थन करते हैं तो वे पीड़ा को कम करने के सिद्धांत का पालन कर रहे होते हैं। लेकिन यदि भ्रूण व्यवहार्य अवस्था में पहुँच चुका है, तो वही निर्णय जीवन समाप्त करने की नैतिक आलोचना का कारण भी बन सकता है।

न्यायालयों द्वारा दिए जाने वाले आदेश भी चिकित्सकों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकते हैं। अनेक मामलों में अदालतें विशेषज्ञ चिकित्सा बोर्डों की राय के आधार पर गर्भसमापन की अनुमति देती हैं या उसे अस्वीकार करती हैं। हालांकि अंतिम आदेश कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है, फिर भी प्रक्रिया को अंजाम देने वाले चिकित्सकों को अपने नैतिक विवेक से जूझना पड़ता है। वे जानते हैं कि कानून ने अनुमति दी है, लेकिन व्यक्तिगत और पेशेवर स्तर पर वे उस निर्णय को लेकर असहज हो सकते हैं। दूसरी ओर यदि अदालत अनुमति नहीं देती और चिकित्सक को लगता है कि महिला का स्वास्थ्य गंभीर संकट में है, तो वे स्वयं को नैतिक रूप से विवश अनुभव कर सकते हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू चिकित्सा उत्तरदायित्व का है। चिकित्सकों को न केवल नैतिक बल्कि कानूनी परिणामों का भी सामना करना पड़ सकता है। यदि वे कानूनी प्रावधानों से बाहर जाकर निर्णय लेते हैं तो उन पर आपराधिक या व्यावसायिक कार्रवाई हो सकती है। वहीं यदि वे केवल कानूनी सुरक्षा के लिए ऐसा निर्णय लेते हैं जो रोगी के हित में नहीं है, तो चिकित्सा नैतिकता के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन हो सकता है। इस प्रकार वे दोहरी जवाबदेही के बीच फँस जाते हैं—एक कानून के प्रति और दूसरी अपने पेशे के नैतिक आदर्शों के प्रति।

ऐसे मामलों में चिकित्सा बोर्डों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुविषयक विशेषज्ञ समितियाँ विभिन्न चिकित्सा, नैतिक और सामाजिक पहलुओं का समग्र मूल्यांकन कर सकती हैं। इससे निर्णय किसी एक चिकित्सक की व्यक्तिगत धारणा पर आधारित न होकर सामूहिक विशेषज्ञता पर आधारित होता है। फिर भी अंतिम निर्णय का नैतिक भार अक्सर उन चिकित्सकों पर ही रहता है जो प्रक्रिया को क्रियान्वित करते हैं। इसलिए, संस्थागत समर्थन और स्पष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता बनी रहती है।

समाज की बदलती संवेदनाएँ भी इस बहस को प्रभावित करती हैं। एक ओर महिलाओं के प्रजनन अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर विकलांगता अधिकारों और भ्रूण जीवन के संरक्षण की वकालत करने वाले समूह भी सक्रिय हैं। चिकित्सक इन परस्पर विरोधी सामाजिक अपेक्षाओं के बीच कार्य करते हैं। उनके निर्णयों का मूल्यांकन केवल चिकित्सा मानकों से नहीं बल्कि नैतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोणों से भी किया जाता है। इससे उन पर अतिरिक्त मानसिक दबाव पड़ता है।

मानसिक स्वास्थ्य का प्रश्न भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। देर से गर्भसमापन से जुड़े मामलों में चिकित्सक, माता-पिता और स्वास्थ्यकर्मी सभी भावनात्मक तनाव का अनुभव कर सकते हैं। जीवन और मृत्यु से जुड़े निर्णय केवल तकनीकी प्रक्रिया नहीं होते; वे गहरे मानवीय अनुभव होते हैं। कई चिकित्सक नैतिक संकट, अपराधबोध या भावनात्मक थकान का सामना करते हैं। इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था को उनके लिए भी मनोवैज्ञानिक और नैतिक परामर्श की व्यवस्था करनी चाहिए।

इस पूरे विमर्श में यह समझना आवश्यक है कि कानून और नैतिकता हमेशा विरोधी नहीं होते। दोनों का उद्देश्य अंततः मानव कल्याण और न्याय की स्थापना ही है। लेकिन वास्तविक जीवन की जटिल परिस्थितियों में उनके बीच तनाव उत्पन्न हो सकता है। व्यवहार्य भ्रूणों वाली गर्भावस्थाओं के देर से चिकित्सकीय समापन के मामले यही दर्शाते हैं कि किसी भी नियम या सिद्धांत को यांत्रिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। प्रत्येक मामले की अपनी विशिष्ट परिस्थितियाँ होती हैं जिनका संवेदनशील और विवेकपूर्ण मूल्यांकन आवश्यक है।

आगे बढ़ते हुए आवश्यकता इस बात की है कि कानून अधिक स्पष्ट, वैज्ञानिक और मानवीय बने। न्यायालयों, चिकित्सा संस्थानों और नीति-निर्माताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए। चिकित्सकों को नैतिक निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षण और संस्थागत समर्थन उपलब्ध कराया जाए।

साथ ही महिला की गरिमा, स्वायत्तता और स्वास्थ्य के साथ-साथ भ्रूण जीवन के नैतिक महत्व को भी संतुलित रूप से स्वीकार किया जाए। केवल कानूनी औपचारिकताओं या भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के आधार पर ऐसे मामलों का समाधान संभव नहीं है।

क्या नए राजनीतिक युग की शुरुआत करेंगे अन्नामलाई?

महेन्द्र तिवारी

तमिलनाडु की राजनीतिक भूमि हमेशा से भारतीय राजनीति के मानचित्र पर अपनी एक विशिष्ट और पृथक पहचान बनाए हुए है। देश के अन्य राज्यों के विपरीत यहाँ राष्ट्रीय विचारधारा वाले दलों की तुलना में क्षेत्रीय अस्मिता और क्षेत्रीय संगठनों का प्रभाव कहीं अधिक गहरा रहा है। बीते अनेक दशकों से द्रविड़ आंदोलन की कोख से निकली राजनीति ने ही इस राज्य की सत्ता की दिशा और दशा को पूरी तरह नियंत्रित और संचालित किया है। ऐसे सुदृढ़ और पारंपरिक राजनीतिक परिवेश में जब कोई नया चेहरा अत्यंत तीव्रता के साथ उभरता है, तो उसकी छोटी से छोटी गतिविधि भी राजनीतिक गलियारों में गहरी हलचल और विमर्श का कारण बन जाती है। इस समय तमिलनाडु के राजनीतिक आकाश में जिस एक नाम को लेकर सबसे अधिक चर्चाएँ और कयास लगाए जा रहे हैं, वे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई। पिछले कुछ समय से राज्य के समाचारों और राजनीतिक चर्चाओं में इस बात ने अत्यधिक जोर पकड़ लिया है कि वे अपने वर्तमान दल से नाता तोड़कर एक नए क्षेत्रीय राजनीतिक दल का गठन कर सकते हैं। यद्यपि उन्होंने अभी तक इस विषय में कोई आधिकारिक या स्पष्ट घोषणा नहीं की है, परंतु उनके हालिया वक्तव्य, उनके समर्थकों द्वारा लगाए गए विज्ञापन पत्र, महत्वपूर्ण बैठकों से उनकी दूरी और जमीनी स्तर पर चल रही संगठनात्मक गतिविधियों ने राज्य की राजनीति को एक नए विमर्श की ओर मोड़ दिया है।

इस नए राजनीतिक घटनाक्रम की सुगबुगाहट तब और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी जब कोयंबटूर शहर में अचानक कई प्रमुख स्थानों पर उनके समर्थकों द्वारा बड़े-बड़े विज्ञापन पत्र लगाए गए। सामान्य राजनीतिक विज्ञापनों से सर्वथा भिन्न इन पत्रों पर अंकित संदेश ने सभी का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें लिखा था कि निडर सोच की कोई सीमा नहीं होती। इस वाक्य को राजनीतिक विश्लेषकों और जनता द्वारा एक बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा गया। इसके तुरंत बाद जनसंचार के आधुनिक माध्यमों और मुख्यधारा की राजनीति में यह बात तेजी से फैल गई कि वे किसी नए और स्वतंत्र राजनीतिक मंच की आधारशिला रखने की तैयारी कर रहे हैं। उनके इस संभावित कदम को तब और बल मिला जब उनके प्रशंसकों और समर्थकों के संगठन, जिसका नाम अन्नामलाई अन्बु कूट्टम है, उसने अचानक अपनी गतिविधियों को तेज करते हुए नए सदस्यों और पदाधिकारियों को जोड़ना आरंभ कर दिया। इसके साथ ही भीतरखाने से यह समाचार भी आ रहा है कि मक्कल शक्ति इयक्कम नाम से एक विशाल जनआंदोलन या सामाजिक संगठन की रूपरेखा तैयार की जा रही है, जो आने वाले समय में एक पूर्ण राजनीतिक दल का रूप धारण कर सकता है।

के. अन्नामलाई की पूर्व पृष्ठभूमि और उनकी अब तक की राजनीतिक यात्रा भी अत्यंत रोचक और असाधारण रही है। वे भारतीय पुलिस सेवा के एक प्रतिष्ठित अधिकारी रहे हैं और प्रशासनिक सेवा में रहते हुए अपनी कर्तव्यनिष्ठ तथा सख्त छवि के कारण वे आम जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय हुए थे। अपनी सेवा से त्यागपत्र देकर राजनीति के मैदान में उतरने के बाद उन्होंने अपने दल को तमिलनाडु में एक नई ऊर्जा और आक्रामकता प्रदान करने का अथक प्रयास किया। उनकी इसी कार्यशैली को देखते हुए वर्ष 2021 में उन्हें तमिलनाडु में दल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। बहुत ही अल्प समय में वे राज्य की राजनीति का एक अपरिहार्य और चर्चित चेहरा बनकर उभरे। उनकी संवाद शैली अत्यंत सीधी और सीधे प्रहार करने वाली रही है।

बोध कथा

जीवन की सीख- जब एक छिपकली कर सकती है, तो हम क्यों नहीं?

यह जापान में घटी, एक सच्ची घटना है। अपने घर का नवीनीकरण करने के लिये, एक जापानी अपने मकान की दीवारों को तोड़ रहा था। जापान में लकड़ी की दीवारों के बीच ख़ाली जगह होती है, यानी दीवारें अंदर से पोली होती हैं। जब वह लकड़ी की दीवारों को चीर-तोड़ रहा था, तभी उसने देखा कि दीवार के अंदर की तरफ लकड़ी पर एक छिपकली, बाहर से उसके पैर पर ठुकी कील के कारण, एक ही जगह पर जमी पड़ी है। जब उसने यह दृश्य देखा तो उसे बहुत दया आई पर साथ ही वह जिज्ञासु भी हो गया। जब उसने आगे जाँच की तो पाया कि वह कील तो उसके मकान बनते समय पाँच साल पहले ठोंका गई थी! एक छिपकली इस स्थिति में पाँच साल तक जीवित थी! दीवार के अँधेरे पार्टीशन के बीच, बिना हिले-डुले ? यह अविश्वसनीय, असंभव और चौंका देने वाला था! उसकी समझ से यह परे था कि एक छिपकली, जिसका एक पैर, एक ही स्थान पर पिछले पाँच साल से कील के कारण चिपका हुआ था और जो अपनी जगह से एक इंच भी न हिली थी, वह कैसे जीवित रह सकती है ? अब उसने यह देखने के लिये कि वह छिपकली अब तक क्या करती रही है और कैसे अपने भोजन की जरुरत को पूरा करती रही है, अपना काम रोक दिया। थोड़ी ही देर बाद, पता नहीं कहाँ से, एक दूसरी छिपकली प्रकट हुई, वह अपने मुँह में भोजन दबाये हुये थी – उस फँसी हुई छिपकली को खिलाने के लिये! उफ़्फ़! वह सन्न रह गया! यह दृश्य उसके दिल को अंदर तक छू गया! एक छिपकली, जिसका एक पैर कील से ठुका हुआ था, को एक दूसरी छिपकली पिछले पाँच साल से भोजन खिला रही थी!

अद्भुत! दूसरी छिपकली ने अपने साथी के बचने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी।

तीर तेवर —सागर कुमार

व्यंग्य केसरी

मौलिकता के महर्षि

डॉ मुकेश असीमित

मूलचंद जी इन दिनों मौलिकता की लंगोट बाँधे ऐसे कसमसा रहे थे जैसे साहित्य का सारा भविष्य उनके कंधों पर टिका हो।

सुना था कि लिखने में मौलिकता से रत्ती भर भी छेड़छाड़ न करने के संकल्प के कारण वे अब तक कुछ विशेष लिख नहीं पाए थे। हाँ, दूसरे रचनाकारों की मूल रचना उखाड़ने में उनकी दक्षता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी। साहित्य में यह भी एक प्रतिभा ही मानी जाएगी, सो उन्होंने स्वयं को आलोचक घोषित कर रखा था।

उस दिन कुछ नाराज़ दिखे।

बोले, 'आप बड़े लेखक बन गए शायद ..! आप हमारे पड़ोसी होकर एक बार भी हमारे घर आकर चरण-दर्शन नहीं किए, आशीर्वाद नहीं लिया।'

मैं समझ गया कि स्थिति गंभीर है। इससे पहले कि वे मुझे भी किसी रचना की तरह मूल समेत उखाड़ फेंकें, उनकी शरण में जाना ही श्रेयस्कर है।

मैं पहुँचा तो आश्चर्य हुआ। उनके मुख से 'अहो! अहो!' की ध्वनियाँ निकल रही थीं।

मैंने मन ही मन सोचा,यह कैसा आलोचक है? आलोचना की मूल ध्वनि तो 'लानत! धिक्कार! अरे वाहियात!' होती है। यहाँ तो अहो-अहो का कीर्तन चल रहा है।

उन्होंने मुझे बैठने का संकेत किया और बड़ी श्रद्धा से एक कागज़ आगे बढ़ाया।

'देखिए,' उन्होंने कहा, 'इसे कहते हैं मौलिक रचना। आप जानते हैं न ,रचनाकार को । अरे हमारा बच्चा है यह हमने तराशा है इसे द्य'

मैंने रचना देखी।

पूछा, 'गुरुजी, यह किस विधा की है?'

वे चौंके, 'अरे! दिखाई नहीं देता? ऊपर साफ लिखा है,व्यंग्य!'

मैंने फिर पढ़ा।

रचना में व्यंग्य कम, सीधी-सपाट गालियाँ अधिक थीं। कुंठा इतनी थी कि शब्द भी खाँसते हुए निकल रहे थे। भाषा को मौलिक बनाए रखने के लिए शायद उसे नहाने-धोने से भी बचाया गया था। अशुद्धियाँ नमक में आटे के बराबर भरी हुई ।

मैंने साहस करके पूछा,

'गुरुजी, इसमें तो सपाट बयानबाजी है, सीधे-सीधे गालियाँ हैं...'

वे मुस्कुराए।

'यही तो मौलिकता है!'

'जी?'

'देखिए, रचना मौलिक हो तो अशुद्धियाँ, कुंठाएँ, गालियाँ,सब क्षम्य हैं। बल्कि जितनी अधिक हों, उतनी अधिक मौलिक मानी जाती है।'

मैंने प्रतिवाद करने का विचार किया, फिर अपने भीतर बैठे विवेक ने मेरा हाथ पकड़ लिया।

चुपचाप अपनी रचना, जो मैं उन्हें दिखाने लाया था, वापस खींसे में दबाई और बाहर निकल आया।

रास्ते भर सोचता रहा,

ऐसी मौलिकता लाना मेरे बस की बात नहीं।

कहीं अपनी रचना दिखाकर उनका दिल दुखा बैठता, और फिर वे मुझे भी किसी दिन साहित्य की भूमि से मूल समेत उखाड़ने का अभियान शुरू कर देते।

इतिहास

2 जून (आज के दिन) की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं में, 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का राज्याभिषेक और 1946 में इटली का राजतंत्र समाप्त होकर गणतंत्र बनना शामिल है??? विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं1946: इटली में हुए जनमत संग्रह के बाद राजशाही समाप्त हुई और देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया?1953: ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का लंदन के वेस्टमिंस्टर एब्बे में राज्याभिषेक हुआ?1966: अमेरिका ने अपना पहला मानवरहित अंतरिक्ष यान 'सर्वेयर 1' चंद्रमा की सतह पर उतारा। भारत से जुड़ी घटनाएं1979: भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में 'विजयनगरम जिले' की स्थापना की गई।

संक्षिप्त खबरें

मरवाही में जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे लोग

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। मरवाही तहसील में जाति, आय एवं निवास प्रमाण पत्र निर्माण में हो रही देरी से आमजन में भारी नाराजगी देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में प्रमाण पत्र जारी नहीं होने के कारण छात्र-छात्राओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों के महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि मरवाही लोक सेवा केंद्र एवं संबंधित राजस्व कार्यालयों में जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों की लापरवाही और मनमानी के चलते बड़ी संख्या में आवेदन लंबे समय से लंबित पड़े हैं। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को बार-बार तहसील और लोक सेवा केंद्र के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे उनका समय और आर्थिक संसाधन दोनों प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले आवेदकों को विशेष रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

जहां लगती थी नक्सलियों की जन अदालत वहीं सीएम साय की लगी जनचौपाल

बीजापुर। छत्तीसगढ़ में साय सरकार का सुशासन तिहार 2026 जारी है. जहां कभी लाल आतंक का दहशत था, लेकिन आज सुशासन का उजियारा पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का हेलीकॉप्टर मंगलवार को बीजापुर के कोंडपल्ली गांव में उतरा। जहां वह सुशासन तिहार कार्यक्रम में शामिल हुए और इमली पेड़ के नीचे जनचौपाल लगाकर ग्रामीणों से उनकी मांगे और समस्याएं सुनी। इस दौरान सड़क, बिजली जैसी समस्याओं पर भी सार्थक संवाद किया गया।

सुशासन तिहार कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जनचौपाल में ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह पहले नक्सलियों के डर के साया में जीवन-यापन करते थे। लेकिन अब सरकार हमारे गांवों स्कूल, आंगनबाड़ी,सड़क,पीने का पानी पहुंच रही है। यह देखकर क्षेत्र में सकारात्मकता का माहौल है।

बता दें कि मुख्यमंत्री साय ने आज उसी गांव में जनचौपाल लगाई, जहां कभी नक्सलियों की जनअदालत लगा करती थी। नक्सलवाद के खात्मे के बाद यहां की तस्वीर बदल रही है। इलाके में तेजी से विकास पहुंचाया जा रहा है। सरकार आवागमन के लिए सड़क, अस्पताल और स्कूल बनाने का काम कर रही है।

ओएससीसीएल में बेरोजगारों की मांग को लेकर अप्रेंटिस संघ ने जताई नाराजगी

कोरबा। भारतीय आईटीआई अप्रेंटिस संघ ने नामांकन के नाम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि एससीआई सीएल में अप्रेंटिसों को रोजगार की मांग की जा रही है। स्पेशलिटी यूनियन ने कहा है कि 23 सितंबर 2022 को 4855 एससीसीएल अप्रेंटिस को रोजगार देने का समझौता हो गया है, लेकिन एससीसीएल प्रबंधन ने अभी तक एक भी अप्रेंटिस को रोजगार नहीं देने का समझौता किया है। जबकि समझौता लगभग 3 साल तक चलता रहा। समझौते के बाद एससी सीएल प्रबंधन में हजारों की संख्या में अन्य कर्मचारियों की भर्ती की गई है। कंपनी में लगभग 2 लाख से अधिक नियमित कर्मचारी हो गए हैं। वर्तमान में लगभग 35,000 से अधिक नियमित कर्मचारी कर्मचारी हैं और आउटसोर्सिंग के अंतर्गत लगभग 40 से 50 हजार श्रमिक कर्मचारी हैं। बिलासपुर मुख्यालय के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय महाप्रबंधकों से संघ के लिए बैठक की बात कही गई थी। जिस पर संघ द्वारा कई बार उन्हें अवैध साइंटिस्टों द्वारा फिर भी अप्रेंटिस को रोजगार नहीं दिया गया। मुख्यालय के अधिकारी की घोषणा पर इतने दिन का इंतजार किया गया। उन्होंने कहा कि रोजगार प्रस्ताव में और भी ज्यादा देर होने के कारण 10 दिनों के बाद एजीएम, सीएमडी कार्यालय बिलासपुर एवं कोल इंडिया के प्रमुख कार्यालय कोलकाता के साथ हड़ताल करेंगे। एटी: मांग है कि एकांत के अनुसार अप्रेंटिस को रोजगार की व्यवस्था की जाए।

कार के दरवाजे में गुप्त चेंबर बनाकर छिपाया था गांजा, दो तस्कर गिरफ्तार

नशा तस्करी का 'हाईटेक' तरीका फेल

दुर्ग। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट (एसीसीयू) ने उड़ीसा से छत्तीसगढ़ में गांजा सप्लाई करने वाले और दुर्ग जिले में खपाने वाले दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से करीब 7 लाख 25 हजार रुपए का 14 .5 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपियों ने गांजे को कार के दरवाजे में गुप्त चेंबर बनाकर छिपाया था, लेकिन गांजे की खुशबू ने पूरा राज खोल दिया।

क्या है पूरा मामला ?

कुम्हारी थाना पुलिस और एसीसीयू दुर्ग की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी ओडिशा से एक क्रेटा कार में अवैध गांजा परिवहन कर महासमुंद, रायपुर होते हुए दुर्ग-भिलाई क्षेत्र में खपाने के लिए ला रहे हैं, जिसके बाद टीम ने कुम्हारी ओवरब्रिज के नीचे घेराबंदी कर रायपुर की ओर से आ रही संदिग्ध क्रेटा कार को रोक लिया।

कार से गंध आने पर खुला राज

टीम ने जब कार की जांच की, तो उसके अंदर से गांजे की तेज गंध आ रही थी। गंध आते ही पुलिस का शक यकीन में बदल गया। गाड़ी की बारीकी से तलाशी लेते हुए दरवाजों के फाइबर को हटाया गया, तो अंदर छिपे गांजे के पैकेट देखकर पुलिस भी हैरान रह गई।

आरोपियों ने किए चौंकाने वाले खुलासे

टीम ने मौके से कार सवार मुख्य तस्कर तीरथा ठेला (निवासी राजा खरियार, ओडिशा) को हिरासत में लिया। उससे कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने दुर्ग-भिलाई में गांजे के खरीदार किशन जगत (निवासी कुम्हारी) का नाम उगला, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खरीदार को भी धर दबोचा। आरोपियों ने कबूल किया कि वे ओडिशा के कंधमाल क्षेत्र से सस्ते दामों में गांजा खरीदकर दुर्ग-भिलाई क्षेत्र में महंगे दामों में अवैध बिक्री के लिए ला रहे थे।

दोनों आरोपी पहुंचे जेल

पुलिस ने आरोपियों के पास से 14.5 किलो गांजा, क्रेटा कार, 22 हजार रुपये नगद और मोबाइल फोन जब्त किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ कुम्हारी थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) और 29 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया गया है।

वन भूमि की सुरक्षा के लिए बलौदाबाजार वनमंडल में विशेष अभियान शुरू

रायपुर। वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार वन भूमि पर अतिक्रमण रोकने और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बलौदाबाजार वनमंडल में 1 जून से 15 जून 2026 तक विशेष एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू किया गया है। वर्षा ऋतु से पहले वन भूमि पर संभावित अतिक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से वनमंडल स्तर पर अंतर-परिक्षेत्रीय संयुक्त निरीक्षण दलों का गठन किया गया है। ये दल विभिन्न वन क्षेत्रों का भ्रमण कर वन भूमि की स्थिति का आकलन करेंगे और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधियों पर नजर रखेंगे।

अभियान के तहत वन सीमाओं, वनखंडों और बीट क्षेत्रों का निरीक्षण किया जाएगा। विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा जिनकी सीमाएं गांवों और कृषि भूमि से लगी हुई हैं। निरीक्षण के दौरान वन सीमांकन, मुनारों की स्थिति, संभावित अतिक्रमण, अवैध कटाई, अवैध उत्खनन तथा अन्य अनधिकृत गतिविधियों की जांच की जाएगी।

निष्पक्ष मूल्यांकन के लिए बने संयुक्त निरीक्षण दल

अभियान को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न वन परिक्षेत्रों के अधिकारियों को अन्य परिक्षेत्रों में निरीक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निरीक्षण के दौरान संबंधित अभिलेख, नक्शे, कक्ष इतिहास और अन्य आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण भी किया जाएगा। स्थानीय वन समितियों की सहभागिता से निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाएगा।

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर

एमसीबी। जिले के युवाओं के लिए रोजगारपरक एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने का सुनहरा अवसर उपलब्ध हुआ है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) जनकपुर में सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 29 मई 2026 से 15 जून 2026 तक प्रवेश के लिए निर्धारित वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जनकपुर ने जानकारी देते हुए बताया कि संस्थान में कोपा (एससीवीटी) एक वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 48 सीटें, विद्युतकार (एससीवीटी) द्विवर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 20 सीटें तथा सिलाई टेक्नोलॉजी (एससीवीटी) एक वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए 40 सीटें उपलब्ध हैं। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को आधुनिक तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

पेंड्रा सर्राफा व्यापारी हत्याकांड, मास्टरमाइंड समेत 3 गिरफ्तार

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में सर्राफा व्यापारी प्रदीप सोनी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि घटना को अंजाम देने वाले बिहार-झारखंड के 3 शूटर अभी फरार हैं।

पुलिस के मुताबिक, इस वारदात का मास्टरमाइंड बिलासपुर जिले के बिटकुला गांव का रहने वाला खुशीराम साहू है। उसने बाजार में सोना-चांदी व्यापारियों की रेकी कर पूरी साजिश रची थी। इस काम में उसके भतीजे राजाराम साहू ने भी मदद की।

खुशीराम ने बिहार और झारखंड में अपने परिचित राहुल के जरिए शूटर बुलाए थे। राहुल अपने साथी संजय और राजू के साथ बिहार से आया और सभी ने मिलकर लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद आरोपी देवरीखुर्द स्थित गया प्रसाद रजक के घर पहुंचे, जहां लूटे गए सोने-चांदी के आभूषणों का बंटवारा किया गया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर खुशीराम साहू, राजाराम साहू और गया प्रसाद रजक को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक देसी कट्टा, दो जिंदा कारतूस, लूटे गए आभूषण और तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। वहीं, फरार शूटर राहुल, संजय और राजू की तलाश जारी है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को दूसरे राज्यों में भेजा गया है।

बिलासपुर का खुशीराम निकला मास्टरमाइंड

पुलिस जांच में सामने आया है कि, बिलासपुर जिले के बिटकुला निवासी खुशीराम सही पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर कोटमी बाजार स्थित ज्वेलरी कारोबारियों की पहले रेकी की और फिर लूट की योजना बनाई। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि, खुशीराम ने वारदात को अंजाम देने के लिए बिहार से तीन शूटर बुलाए थे। इन्हीं शूटरों ने सराफा व्यापारी प्रदीप सोनी की गोली मारकर हत्या की और लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद सभी आरोपी अलग-अलग दिशाओं में फरार हो गए थे।

लूट के सामान का किया गया बंटवारा

पुलिस के अनुसार, वारदात के बाद आरोपी देवरीकला निवासी गया प्रसाद रजक के घर पहुंचे थे, जहां लूटे गए जेवर और अन्य सामान का आपस में बंटवारा किया।

19 प्रशिक्षु उपनिरीक्षक और 2 सूबेदार व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए जांजगीर-चांपा में पदस्थ

जांजगीर-चांपा। राज्य पुलिस अकादमी रायपुर से बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद 19 प्रशिक्षु उपनिरीक्षक और 2 प्रशिक्षु सूबेदारों को 10 महीने के व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए जांजगीर-चांपा जिले में पदस्थ किया गया है। प्रशिक्षु अधिकारियों की तैनाती से जिला पुलिस बल को नई ऊर्जा और अतिरिक्त कार्यक्षमता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय ने सभी प्रशिक्षु अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें जिला पुलिस की कार्यप्रणाली, कानून-व्यवस्था संधारण और पुलिसिंग के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। बैठक के दौरान एसपी ने कहा, पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी आम नागरिकों को न्याय दिलाना और उनकी समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान करना है। उन्होंने प्रशिक्षुओं को अपराध विवेचना, मर्ग जांच, शिकायत एवं आवेदन जांच की प्रक्रिया को गंभीरता और निष्पक्षता के साथ संपादित करने के निर्देश दिए। साथ ही फरियादियों और आवेदकों के साथ सम्मानजनक, सौहार्दपूर्ण और मानवीय व्यवहार बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। प्रशिक्षु अधिकारियों को जिले के विभिन्न थाना और चौकियों में पदस्थ किया गया है, जहां उन्हें अपराध विवेचना, मर्ग जांच, शिकायत जांच और कानून-व्यवस्था ड्यूटी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा प्रधान आरक्षक मोहर्रिर कार्य, प्रधान आरक्षक गस्ती, रात्रि गश्त, पेट्रोलिंग, सीसीटीएनएस संचालन, संत्री ड्यूटी, मददगार कार्य, मुलजिम पेशी, न्यायालयीन कार्यवाही और बीट आरक्षक की जिम्मेदारियों की भी व्यावहारिक जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों और अनुभवी पुलिसकर्मियों द्वारा दी जाएगी।

24वें मेगा मेडिकल कैंप : 650 से मरीज हुए लाभान्वित

भिलाई। सामुदायिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने और जमीनी स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) - भिलाई इस्पात संयंत्र के राजहरा माइंस हॉस्पिटल में 24वें मेगा मेडिकल कैंप का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस बहु-विषयक (मल्टी-डिसिप्लिनरी) शिविर का मुख्य उद्देश्य राजहरा एवं इसके आसपास के क्षेत्रों के निवासियों को विशेषज्ञ चिकित्सा परामर्श, व्यापक स्वास्थ्य जांच तथा आवश्यक उपचार सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना था।

इस चिकित्सा शिविर में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ देखी गई, जिसके तहत क्षेत्र के 650 से अधिक मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें विशेषज्ञ चिकित्सा मार्गदर्शन प्रदान किया गया। शिविर के दौरान हृदय रोग, मेडिसिन, अस्थि रोग, बाल रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग, नेत्र रोग, कान-नाक-गला (ईएनटी), त्वचा रोग, दंत चिकित्सा, सामान्य शल्य चिकित्सा तथा दर्द प्रबंधन सहित विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में विशेषज्ञ परामर्श और उपचार सेवाएं दी गईं।

ऑन-साइट चिकित्सा हस्तक्षेप के उच्च स्तर का प्रदर्शन करते हुए, क्लिनिकल टीम ने जोड़ों में दर्द से पीड़ित मरीजों को 25 इंट्रा-आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाए और ऑर्थोपेडिक सहायता की आवश्यकता वाले 6 मरीजों को मौके पर ही प्लास्टर की सुविधा भी उपलब्ध कराई। इस मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ. विनीता द्विवेदी के कुशल नेतृत्व में किया गया। विशेषज्ञ चिकित्सकों, डीएनबी रेजिडेंट्स, पैरामेडिकल कर्मियों एवं सहयोगी स्टाफ की एक अत्यंत योग्य बहु-विषयक टीम ने शिविर में सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं दीं।

विशेषज्ञ चिकित्सा दल में डॉ. कौशलेंद्र ठाकुर (सर्जिकल ट्रॉमा), डॉ. चंदन दास (हृदय रोग), डॉ. प्रमोद बिनयके (मेडिसिन), डॉ. इमैनुअल मैसी (अस्थि रोग), डॉ. कौशिक किशोर (बाल रोग), डॉ. प्रभदीप कौर (प्रसूति एवं स्त्री रोग), डॉ. वनिता शर्मा (दंत चिकित्सा), डॉ. धीरज शर्मा (सामान्य शल्य चिकित्सा) आदि शामिल थे।

अनुकंपा नियुक्ति के मामले में सख्त हुआ उच्च न्यायालय

बिलासपुर। मंगलवार को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की युगलपीठ ने अनुकंपा नियुक्ति को लेकर अंबिकापुर नगर निगम के सफाई कर्मचारी की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति पर उच्च न्यायालय की एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए निगम की याचिका को खारिज कर दिया। जिससे याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति दिये जाने का रास्ता साफ हो गया।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल ने अपने इस फैसले में सपाट शब्दों में कहा कि यदि परिवार का कोई एक सदस्य पहले से सरकारी नौकरी में है तो इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि अनुकंपा नियुक्ति का दावा स्वमेव खत्म हो गया। अगर हकीकत में परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है तो उसकी असली स्थिति जाने बिना केवल नियमों का हवाला देकर आवेदन को खारिज करना सही नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की युगल पीठ ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई की करते हुए अंबिकापुर नगर निगम की अपील को खारिज कर दिया और सिंगल बेंच के पुराने आदेश को सही माना। पीठ ने कहा कि सरकार की अनुकंपा नियुक्ति योजना का असली मकसद मृतक कर्मचारी के परिवार को अचानक आए भारी आर्थिक संकट से बचाना है। अधिकारियों को इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर जमीनी और मानवीय फैसला लेना चाहिए।

यह पूरा मामला अंबिकापुर नगर निगम का है। याचिकाकर्ता के पिता वहां सफाई कर्मचारी के पद पर काम करते थे। नौकरी के दरम्यान अचानक उनका निधन हो गया। इससे उनके परिवार पर आर्थिक बोझ बढ गया। उनके परिवार में पत्नी तीन बेटे और एक बेटी हैं। पूरा परिवार उनकी कमाई पर ही निर्भर था। पिता की मौत के बाद उनके बेटे ने सरकार की अनुकंपा नियुक्ति नीति के तहत नौकरी के लिए आवेदन किया। लेकिन नगर निगम ने यह कहते हुए उसके आवेदन को निरस्त कर दिया कि उसकी मां पहले से ही निगम में सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रही हैं। आवेदन निरस्त होने के बाद याचिकाकर्ता ने दुबारा फिर से निगम में उसके आवेदन पर पुर्नविचार करने को कहा और इसके लिये ऐसे ही एक प्रकरण का हवाला देते हुए बताया कि ठीक ऐसी ही स्थिति वाले दूसरे लोगों को पहले नौकरी दी जा चुकी है। निगम ने जब उसकी नहीं सुनी तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो सिंगल बेंच ने नगर निगम के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने निगम को आदेश दिया कि वह याचिकाकर्ता को नौकरी दे। इस फैसले के खिलाफ नगर निगम कमिश्नर ने डबल बेंच में अपील कर दी थी।

निगम की तरफ से दलील दी गई कि 2013 की नीति के अनुसार अगर परिवार में कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में है तो अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल सकती। वहीं याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि उसकी मां की तनख्वाह बहुत कम है और उससे इतने बड़े परिवार का खर्च नहीं चल सकता। हाईकोर्ट की बेंच ने अपने फैसले में साफ कहा कि अधिकारियों ने यह जानने की थोड़ी भी कोशिश नहीं की कि परिवार की असली आर्थिक स्थिति क्या है? मुख्य कमाने वाले की मौत के बाद परिवार किन परेशानियों का सामना कर रहा है यह बिल्कुल नहीं देखा गया। अदालत ने कहा कि किसी परिवार के एक सदस्य का कम तनख्वाह वाले पद पर काम करना यह साबित नहीं करता कि परिवार गरीबी से बाहर आ गया है।

मधुमक्खियों के हमले में सास की मौत, दामाद घायल

धमतरी। सराई बिनने के लिए सास और दामाद गए हुए थे कि उन पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया जिसमें सास की मौत हो गई और दामाद घायल हो गया है, फिलहाल दामाद का इलाज अस्पताल में जारी है। घटना दुगली थाना क्षेत्र की है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक पाल गांव में रहने वाली रामवती आज अपने दामाद के साथ सराई बिनने के लिए जंगल की ओर गई थी। इसी दौरान दोनों पर मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। घटना के बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां रामवती की मौत हो गई और उसका दामाद घायल बताया जा रहा है जिसका आज धमतरी जिला अस्पताल में चल रहा है।

सरकार बदलने जा रही होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष, लॉन्च करेगी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स

नई दिल्ली। सरकार थोक मूल्य सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स (डब्ल्यूपीआई) के आधार वर्ष को बदलकर 2022-23 करने जा रही है। इसके साथ ही उत्पादक मूल्य सूचकांक यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (पीपीआई) भी लॉन्च करने जा रही है, जिसे भारत की महंगाई मापने की प्रणाली को आधुनिक और अधिक सटीक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

इसके अलावा, सरकार ने इस विषय पर मंगलवार को मीडिया को ब्रीफिंग के लिए आमंत्रित किया है, जिसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के प्रधान आर्थिक सलाहकार प्रवीण महतो संबोधित करेंगे।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा, 'हमने डब्ल्यूपीआई 2022-23 के आंकड़ों का उपयोग किया है, जो हमें आंतरिक रूप से उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि अप्रैल के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के आंकड़ों में कोई संशोधन न करना पड़े। हमें उम्मीद है कि ये आंकड़े अगले कुछ सप्ताह में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हो जाएंगे।'

उन्होंने बताया कि वर्तमान डब्ल्यूपीआई शृंखला का आधार वर्ष 2011-12 है, जबकि संशोधित शृंखला में इसे बदलकर 2022-23 कर दिया जाएगा।

सौरभ गर्ग ने कहा कि नया सूचकांक शुरू होने के बाद भी डब्ल्यूपीआई से आउटपुट पीपीआई में बदलाव तुरंत नहीं किया जाएगा। सरकार पहले नई शृंखला की स्थिरता और विश्वसनीयता का अध्ययन करेगी, उसके बाद ही इसे व्यापक स्तर पर अपनाने का निर्णय लिया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत में डब्ल्यूपीआई और आउटपुट पीपीआई के बीच बहुत अधिक अंतर होने की संभावना नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूपीआई की गणना के लिए पहले से ही ऐसी पद्धति अपनाई जाती है जो दोनों के बीच अंतर को सीमित रखती है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले ही सांख्यिकी मंत्रालय ने 2022-23 आधार वर्ष के साथ संशोधित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) जारी किया था।

मंत्रालय ने बताया था कि मूल्य आधारित वस्तुओं की गणना के लिए नए आधार वर्ष वाले अद्यतन डब्ल्यूपीआई डिफ्लेटर का पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है।

इस साल फरवरी में सरकार ने कहा था कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का आधार वर्ष 2022-23 किया जा रहा है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) का आधार वर्ष 2024 किया जा रहा है और आईआईपी का आधार वर्ष भी 2022-23 किया जा रहा है। इसके साथ ही भारत की सांख्यिकीय प्रणाली का व्यापक आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

सरकार के अनुसार, 'डब्ल्यूपीआई के आधार वर्ष में संशोधन का काम भी जारी है। जब तक नया डब्ल्यूपीआई उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक मौजूदा डब्ल्यूपीआई का उपयोग डिफ्लेटर के रूप में किया जाता रहेगा। इसके अलावा, मंत्रालय निकट भविष्य में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स (पीपीआई) को भी शामिल करने की योजना बना रहा है।

आरबीआई जून एमपीसी में रेपो रेट को रख सकता है स्थिर, आउटलुक और आक्रामक होने की उम्मीद : एचएसबीसी

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) आने वाली जून मौद्रिक नीति कमेटी (एमसीसी) में रेपो रेट को स्थिर रख सकता है। वहीं, कमजोर रुपया और कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के कारण महंगाई में इजाफा होने की संभावना के चलते आउटलुक और अधिक आक्रामक होने की उम्मीद है। यह बयान एचएसबीसी में एक अर्थशास्त्री की ओर से दिया गया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एचएसबीसी की चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट और मैक्रो स्ट्रैटजिस्ट प्रांजुल भंडारी का कहा कि इस मौद्रिक नीति में आरबीआई का महंगाई और अर्थव्यवस्था की विकास दर को लेकर आने वाला अनुमान बताएगा कि नीति निर्माता कैसे इस ऊर्जा संकट को देख रहे हैं।

पिछले रिव्यू में केंद्रीय बैंक ने तेल की आधारभूत कीमत लगभग 85 डॉलर प्रति बैरल और वैकल्पिक परिदृश्य के रूप में 95 डॉलर का उपयोग किया था।

एचएसबीसी की अर्थशास्त्री का मानना ??है कि तेल की ऊंची कीमतों का अनुमान अब आरबीआई का आधार होगा, जिससे महंगाई का अनुमान पहले के 4.6 प्रतिशत के अनुमान से बढ़कर 5 प्रतिशत के करीब पहुंच जाएगा।

भंडारी ने कहा, 'महंगाई बढ़ रही है, जो ब्याज दरों में वृद्धि का समर्थन करती है, जबकि विकास धीमा हो रहा है, जो ब्याज दरों में वृद्धि के खिलाफ तर्क देता है।'

उन्होंने इसे 'किसी भी केंद्रीय बैंक के लिए सबसे कठिन स्थिति' भी बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि तेल की ऊंची कीमतें और संभावित अल नीनो डेवलपमेंट, महंगाई नियंत्रण, राजकोषीय घाटे और चालू खाते के लिए बाधा बन सकते हैं। केयरएज रेटिंग्स की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि सामान्य से कम मानसून के पूर्वानुमान और हाल ही में खुदरा ईंधन की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के कारण मुद्रास्फीति संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि थोक महंगाई में तीव्र वृद्धि से उपभोक्ता कीमतों पर इसका प्रभाव के तेजी से बढ़ने का खतरा है। महंगाई में मौजूदा उछाल आपूर्ति में अचानक आई कमी के कारण है।

एनपीसीआई इंटरनेशनल ने केएचक्यूआर के माध्यम से कंबोडिया में शुरू की यूपीआई भुगतान सुविधा

नई दिल्ली। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की अंतरराष्ट्रीय शाखा एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने मंगलवार को एसीएलईडीए बैंक पीएलसी के साथ साझेदारी में कंबोडिया में वहां की राष्ट्रीय क्यूआर कोड प्रणाली केएचक्यूआर के माध्यम से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) भुगतान सुविधा शुरू की।

इस सेवा की शुरुआत कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह में आयोजित एक औपचारिक समारोह के दौरान की गई। इस कार्यक्रम में कंबोडिया के नेशनल बैंक (एनबीसी) की गवर्नर डॉ. चिया सेरेई और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।

यह पहल भारत और कंबोडिया के बीच सीमा-पार क्यूआर भुगतान प्रणाली को जोड़ने की पहली चरण की परियोजना है। इसके तहत भारतीय यात्री अब यूपीआई-आधारित मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए कंबोडिया के 45 लाख से अधिक व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर आसानी से भुगतान कर सकेंगे।

इनमें पर्यटन स्थल, रेस्तरां, होटल और रिटेल स्टोर सहित कई स्थान शामिल हैं।

परियोजना के अगले चरण में कंबोडिया के नागरिक भी अपने घरेलू बैंकिंग या भुगतान एप्लिकेशन का उपयोग करके भारत में लाखों यूपीआई क्यूआर कोड वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर भुगतान कर सकेंगे। इससे दोनों देशों के बीच दो-तरफा और आपस में जुड़ी डिजिटल भुगतान प्रणाली विकसित होगी। नपीसीआई इंटरनेशनल ने कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य रियल-टाइम, सुरक्षित और इंटरऑपरेबल डिजिटल लेनदेन उपलब्ध कराना है। इससे भुगतान प्रक्रिया अधिक आसान होगी, ' को सुविधा मिलेगी और भारत तथा कंबोडिया के बीच पर्यटन एवं व्यापारिक संबंधों को भी मजबूती मिलेगी। पहले चरण में कंबोडिया के व्यापारियों को भारत के करोड़ों डिजिटल भुगतान उपयोगकर्ताओं तक पहुंच मिलेगी। इसके अलावा, उन्हें नकदी प्रबंधन में आसानी, नकद लेनदेन पर कम निर्भरता और बेहतर परिचालन दक्षता जैसे लाभ भी प्राप्त होंगे।

आईटी शेयरों के दम पर सेंसेक्स 382 अंक उछलकर बंद, टीसीएस टॉप गेनर रहा

मुंबई। आईटी शेयरों में बड़ी रैली के कारण भारतीय शेयर बाजार मंगलवार के कारोबारी सत्र में तेजी के साथ बंद हुआ। दिन के अंत में सेंसेक्स 382.50 अंक या 0.52 प्रतिशत की तेजी के साथ 74,649.84 और निफ्टी 100.95 अंक या 0.43 प्रतिशत की मजबूती के साथ 23,483.55 पर था।

बाजार की तेजी का नेतृत्व आईटी शेयरों ने किया। इस दौरान निफ्टी आईटी में 4.23 प्रतिशत की बढ़त के साथ सूचकांकों में टॉप गेनर था। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 1.30 प्रतिशत, निफ्टी एफएमसीजी 0.76 प्रतिशत, निफ्टी कंजप्शन 0.75 प्रतिशत, निफ्टी इंडिया डिफेंस 0.74 प्रतिशत, निफ्टी ऑटो 0.72 प्रतिशत और निफ्टी रियल्टी 0.67 प्रतिशत की मजबूती के साथ हरे निशान में बंद हुआ।

दूसरी तरफ निफ्टी फार्मा 0.86 प्रतिशत, निफ्टी पीएसई 0.68 प्रतिशत, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 0.59 प्रतिशत और निफ्टी हेल्थकेयर 0.52 प्रतिशत की मजबूती के साथ लाल निशान में था।

सेंसेक्स पैक में टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, अदाणी पोर्ट्स, टेक महिंद्रा औप टाइटन टॉप गेनर्स थे। वहीं, आईटीसी, एशियन पेंट्स, इटरनल, ट्रेंट, एमएंडएम, एचडीएफसी बैंक, मारुति सुजुकी, इंडिगो, एचयूएल, बीईएल और कोटक महिंद्रा बैंक भी हरे निशान में बंद हुए।

दूसरी तरफ, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व टॉप लूजर्स थे।

लार्जकैप के साथ मिडकैप और स्मॉलकैप में भी खरीदारी देखी गई। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 114.05 अंक या 0.19 प्रतिशत की मजबूती के साथ 60,942.00 और निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 72.50 अंक या 0.40 प्रतिशत की तेजी के साथ 18,052.30 पर था।

बाजार में तेजी की वजह एनवीडिया के संस्थापक जेन्सेन हुआंग के बयान को माना जा रहा है।

सोमवार को हुए जीटीसी ताइपे 2026 इवेंट में हुआंग ने कहा था कि एआई के आने से सॉफ्टवेयर कंपनियों की जरूरत समाप्त नहीं हो जाएगी। बल्कि एआई के चलते इन कंपनियों को अपनी नियुक्तियों को बढ़ाना होगा।

हुआंग की इस बयान से वह डिबेट समाप्त हो गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि एआई के आने से सॉफ्टवेयर कंपनियों का काम समाप्त हो जाएगा। इससे निवेशकों के सेंटीमेंट में सुधार हुआ।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर आज से शुरू हो रही नई वार्ता, दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के बीच मंगलवार से नई व्यापार वार्ता शुरू होने जा रही है। दोनों देश लंबे समय से प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों को नई दिशा दे सकता है।

2 जून से 4 जून तक होने वाली इन वार्ताओं में प्रस्तावित अंतरिम समझौते के कानूनी मसौदे को अंतिम रूप देने और बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने पर चर्चा होने की उम्मीद है। इस समझौते का व्यापक ढांचा पहले ही दोनों पक्षों के बीच तय किया जा चुका है।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि बातचीत का लगभग 99 प्रतिशत हिस्सा पूरा हो चुका है और अब केवल कुछ मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है।

उन्होंने कहा, 'बहुत जल्द हम अमेरिका के साथ पहले द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा करेंगे और इसके बाद दूसरे चरण की बातचीत भी जारी रहेगी।' हालांकि, मौजूदा बातचीत मुख्य रूप से व्यापक बीटीए के पहले चरण पर केंद्रित रहेगी। इसमें बाजार पहुंच, गैर-टैरिफ बाधाएं, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को आसान बनाना, निवेश को बढ़ावा देना और आर्थिक सुरक्षा सहयोग जैसे प्रमुख विषय शामिल हैं।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, चर्चा में अमेरिकी व्यापार कानून की धारा 301 के तहत लगाए गए शुल्क भी शामिल हो सकते हैं। भारत इन मामलों में राहत चाहता है और व्यापार से जुड़े विवाद भी एजेंडे का महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहेंगे।

यदि यह व्यापार समझौता सफलतापूर्वक लागू होता है, तो भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर और प्राथमिकता वाली पहुंच मिल सकती है।

अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मुख्य वार्ताकार ब्रेंडन लिंच करेंगे, जबकि भारतीय पक्ष का नेतृत्व वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव दर्पण जैन करेंगे।

अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश मुद्दों पर बातचीत पहले ही पूरी हो चुकी है और अब दोनों देश तकनीकी पहलुओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, ताकि समझौते के पहले चरण की औपचारिक घोषणा की जा सके।

गौरतलब है कि इससे पहले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस पारस्परिक टैरिफ व्यवस्था के खिलाफ फैसला सुनाया था, जिसे 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (आईईईपीए) के तहत लागू किया गया था।

इस फैसले के बाद अमेरिकी प्रशासन ने 24 फरवरी से 150 दिनों के लिए सभी देशों से आने वाले आयात पर समान रूप से 10 प्रतिशत शुल्क लागू कर दिया था। इसी कारण मुख्य वार्ताकारों की पहले प्रस्तावित बैठक को भी टालना पड़ा था।

अमेरिका-ईरान युद्ध का असर! बीते एक महीने में पेट्रोल और डीजल करीब 7.5 रुपए महंगा हुआ, कमर्शियल एलपीजी के दाम भी बढ़े

नई दिल्ली। अमेरिका-ईरान युद्ध का असर देश की आम जनता पर भी देखने को मिल रहा है। इससे बीते एक महीने में पेट्रोल का दाम 7.35 रुपए प्रति लीटर और डीजल का दाम 7.53 रुपए प्रति तक बढ़ गया है।

इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से चार बार 15, 19, 23 और 25 मई को ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की गई, जिससे नई दिल्ली में पेट्रोल का दाम 94.77 रुपए प्रति लीटर से 7.35 रुपए रुपए बढ़कर 102.12 रुपए प्रति लीटर हो गया है।

पेट्रोल की कीमत में 15 मई को 3 रुपए प्रति लीटर, 19 मई को 0.87 रुपए प्रति लीटर, 23 मई को 0.87 रुपए प्रति लीटर और 25 मई को 2.61 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी गई थी। बीते महीने डीजल की कीमतों में भी चार बार वृद्धि की गई, जिससे डीजल का दाम नई दिल्ली में 87.67 रुपए प्रतिशत लीटर से 7.53 रुपए बढ़कर 95.20 रुपए प्रति लीटर हो गया है। डीजल के दाम में 15 मई को 3 रुपए प्रति लीटर, 19 मई को 0.91 रुपए प्रति लीटर, 23 मई को 0.91 रुपए प्रति लीटर और 25 मई को 2.71 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी गई थी। इस दौरान कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी वृद्धि देखी गई है।

युद्ध के चलते नई दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़कर 3,113.50 रुपए पहुंच गया है। एक जून को कमर्शियल एलपीडी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। जून में हुई बढ़ोतरी को मिलाकर बीते पांच महीनों के अंदर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 1,400 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है। जनवरी में, दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1,691.50 रुपए थी। घरेलू स्तर पर बढ़ोतरी के बाद भी देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें अन्य देशों की तुलना में कम हैं। दुनिया की प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्था में पेट्रोल की खुदरा कीमत 150 रुपए प्रति लीटर से अधिक है और अधिकतर देशों में 180 रुपए प्रति लीटर से अधिक है; यूरोपीय संघ के 27 देशों में औसत पेट्रोल की कीमत 179 रुपए और डीजल की कीमत 184 रुपए है।

देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतें बढ़ने से इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग बढ़ी

नई दिल्ली । भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के पंजीकरण में इस साल मई में बढ़ोतरी देखी गई है। इसकी वजह अमेरिका-ईरान युद्ध के कारण ईंधन की कीमतों में इजाफा होने के चलते लोगों का इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर शिफ्ट होना है। यह जानकारी नोमुरा और एचएसबीसी की ओर से जारी रिपोर्ट्स में दी गई।

नोमुरा के अनुसार, मई में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री यात्री वाहनों की कुल बिक्री का 6.4 प्रतिशत रही, जबकि वित्त वर्ष 2026 में यह 4 प्रतिशत थी। वहीं, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री 8.9 प्रतिशत रही, जो पिछले वर्ष के लगभग 6.5 प्रतिशत से अधिक है।

ब्रोकरेज फर्म ने कहा, यह दिखाता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में तेजी से वृद्धि हो रही है।

इसी तरह, एचएसबीसी की एक रिपोर्ट में कहा गया, 'ईंधन की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी के कारण ग्राहकों की इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की ओर रुझान बढ़ा है।'

ब्रोकरेज फर्म ने मई में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की हिस्सेदारी 9.3 प्रतिशत और इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की कुल हिस्सेदारी 6.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

कार निर्माताओं में, इलेक्ट्रिक कारों की बढ़ती मांग के कारण टाटा मोटर्स को सबसे अधिक लाभ हुआ है। कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर 85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जबकि पिछले दो महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बुकिंग में 2.5 गुना वृद्धि हुई है।

नोमुरा के अनुसार, टाटा मोटर्स को 15 लाख रुपए से कम कीमत वाले सेगमेंट में विशेष रूप से मजबूत मांग दिख रही है और कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों की उत्पादन क्षमता को 10,000 यूनिट प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 यूनिट करने की योजना बना रही है।

दोपहिया वाहन सेगमेंट में यह बदलाव और भी अधिक स्पष्ट था। मई में लगभग 42,000 इलेक्ट्रिक स्कूटरों के पंजीकरण के साथ टीवीएस मोटर बाजार में अग्रणी बनी रही, उसके बाद बजाज ऑटो और एथर एनर्जी का स्थान रहा।

नोमुरा की रिपोर्ट के अनुसार, एथर की बिक्री में साल-दर-साल दोगुनी से अधिक वृद्धि हुई, जिससे कंपनी को 16.5 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में मदद मिली। दोनों ब्रोकरेज फर्मों का मानना ??है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग में तेजी आ रही है। हालांकि बढ़ती कमोडिटी लागत निर्माताओं के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।

नोमुरा का मानना ??है कि अनुकूल नीतिगत उपायों और बढ़ती उपभोक्ता स्वीकृति के कारण भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं।

तेल विपणन कंपनियों ने अप्रैल में दो सप्ताह की अवधि में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगभग 8 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की।

हार्ट डिजीज से बचने के लिए कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए? रिसर्च में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

हार्ट हेल्थ को बेहतर बनाए रखने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी माना जाता है. एक हालिया स्टडी के अनुसार हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का खतरा कम करने के लिए रोज कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करना जरूरी है. सप्ताह में 560 से 610 मिनट तक की एरोबिक एक्टिविटी हार्ट डिजीज का रिस्क 30% तक कम हो सकता है.

शरीर को हेल्दी और फिट रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए. एक्सरसाइज करने से फिटनेस बेहतर होती है और कई बीमारियों का खतरा कम हो सकता है. खासतौर से हार्ट हेल्थ को बूस्ट करने के लिए नियमित एक्सरसाइज करनी चाहिए. हेल्थ एक्सपर्ट्स सप्ताह में कम से कम 150 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं. अब एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि हार्ट डिजीज से ज्यादा सुरक्षा पाने के लिए लोगों को 150 मिनट से कहीं ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ सकती है. वैज्ञानिकों का कहना है कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम करने के लिए सप्ताह में 560 से 610 मिनट तक एरोबिक एक्सरसाइज बेहद फायदेमंद हो सकती है।

सेहत से जुड़ी प्रामाणिक जानकारी देने वाली वेबसाइट हेल्थलाइन की रिपोर्ट के मुताबिक एक नई रिसर्च में पता चला है कि जो लोग सप्ताह में 150 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, उनमें हार्ट डिजीज का खतरा लगभग 8 से 9 प्रतिशत तक कम हो सकता है. हार्ट डिजीज का खतरा 20 प्रतिशत कम करने के लिए लोगों को हर सप्ताह करीब 370 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज करना पड़ेगा. जिन लोगों की फिटनेस अच्छी है, उन्हें हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करने के लिए हर सप्ताह करीब 340 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए. कुल मिलाकर आप जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, उतना हार्ट डिजीज का खतरा कम हो सकता है.

रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर हार्ट डिजीज का जोखिम 30 प्रतिशत से ज्यादा कम करना है, तो आपको सप्ताह में 560 से 610 मिनट तक मॉडरेट या हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. यह 150 मिनट की सिफारिश से लगभग 4 गुना अधिक है. हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो सप्ताह में 600 मिनट एक्सरसाइज करने का मतलब है, रोजाना लगभग 85 मिनट की शारीरिक गतिविधि. ऐसा सभी लोगों के लिए करना मुमकिन नहीं है, लेकिन आप जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, उतना ज्यादा फायदा दिल को होगा. इसका मैसेज बस इतना है कि आप ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करें.

यह अध्ययन 19 मई को ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में प्रकाशित हुआ है. शोधकर्ताओं के अनुसार 150 मिनट प्रति सप्ताह एक्सरसाइज करने से हार्ट डिजीज के जोखिम में कुछ हद तक कम करने में मदद मिलती है, लेकिन ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी से ज्यादा फायदा होता है।

बुद्धिमान, मिलनसार और इकोसिस्टम के मददगार रंग-बिरंगे तोते, जानें 'मिट्ठू' से जुड़े मजेदार तथ्य

नई दिल्ली। दुनियाभर में आज (31 मई) के दिन बुद्धिमान, मिलनसार और इकोसिस्टम के मददगार रंग-बिरंगे तोते का जश्न विश्व तोता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तोते सिर्फ सुंदर और बोलने वाले पक्षी नहीं हैं, बल्कि प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। आज हम बात करेंगे भारत में आमतौर पर देखे जाने वाले तीन खास तोतों की रोज-रिंग्ड तोता, एलेक्जेंड्रिन तोता और प्लम-हेडेड पैरेट। ये तीनों तोते बुद्धिमान, सामाजिक और बेहद सक्रिय होते हैं। आमतौर पर भारतीय घरों में तोतों को मिट्ठू पुकारा जाता है। वहीं, जंगलों या बाग-बगीचों में इन्हें अक्सर जोड़ों में या छोटे-छोटे झुंड में देखा जाता है। इनकी मुड़ी हुई मजबूत चोंच खाने के लिए बेहद उपयोगी है, जबकि पैरों की खास बनावट इन्हें पेड़ की डालियों को अच्छी तरह पकड़ने और भोजन चुनने में मदद करती है। ये पक्षी जहां जाते हैं, बीजों को फैलाते हैं और इस तरह प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं।

गुलाबी छल्ले वाला तोता (रोज-रिंग्ड पैरेट) :- यह भारत का सबसे प्रसिद्ध और आम तोता है। खासकर राजस्थान के साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में इसे बहुत आसानी से देखा जा सकता है। शहरों के बगीचों, खेतों, पेड़ों और यहां तक कि बालकनियों पर भी ये चहचहाते नजर आते हैं। तोते के बारे में मजेदार तथ्य है कि इस तोते की याददाश्त बहुत तेज होती है। यह पुरानी जगहों और आवाजों को आसानी से याद रख लेता है। ये होशियार, मिलनसार और हमेशा ऊर्जा से भरे रहते हैं। इनकी वजह से बीज फैलते हैं और पर्यावरण स्वस्थ रहता है।

एलेक्जेंड्रिन तोता :- यह रोज-रिंग्ड तोते से थोड़ा बड़ा होता है। इसकी चोंच गहरे लाल रंग की और काफी ताकतवर होती है। इसके कंधे पर एक खास मैरून रंग का पैच होता है, जो इसे देखने में और आकर्षक बनाता है। इसकी मजबूत चोंच इसे सख्त बीज, मेवे और कठोर फलों को आसानी से तोड़ने में सक्षम बनाती है। यही वजह है कि यह अन्य तोतों की तुलना में ज्यादा बड़े-बड़े खाद्य पदार्थ खा सकता है। यह तोता अपनी ताकत और सुंदरता के लिए जाना जाता है।

प्लम-हेडेड पैरेट या बेर के सिर वाला तोता :- यह तोता अपने खूबसूरत सिर के रंग के लिए मशहूर है। नर तोते का सिर गहरे बेर (प्लम) रंग का होता है, जो देखने में बेहद आकर्षक लगता है। मादा का सिर हल्का भूरा होता है। दोनों में साफ अंतर दिखता है। ये तोते अपनी सुंदर चाल और रंगों के कारण पक्षी प्रेमियों के बीच खास पसंद किए जाते हैं। ये भी अन्य तोतों की तरह सामाजिक हैं और झुंड में रहना पसंद करते हैं।

पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि तोते सिर्फ मनोरंजन के साधन नहीं हैं। ये पर्यावरण के संकेतक भी हैं। अगर तोते स्वस्थ हैं तो इसका मतलब है कि पर्यावरण भी स्वस्थ है। लेकिन शहरीकरण, पेड़ कटाई और अवैध व्यापार के कारण इनकी संख्या पर असर पड़ रहा है।

दुनिया में घट रहा तंबाकू सेवन, लेकिन किशोरों में वेपिंग बनी नई चुनौती

नई दिल्ली। इस दौर में स्मोकिंग से ज्यादा वेपिंग एक चुनौती के तौर पर उभर रही है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर डब्ल्यूएचओ ने ऐसी तस्वीर पेश की जो भयावह है। बताया है कि कैसे युवा तंबाकू से दूरी बना रहे हैं, लेकिन वहीं किशोर इसके मकड़जाल में फंसते जा रहे हैं। '2000-2024 के बीच तंबाकू उपयोग की व्यापकता के रुझानों और 2025-2030 के अनुमानों पर वैश्विक रिपोर्ट' पिछले दो वर्षों पहले प्रकाशित संस्करण का एक अपडेट है। ये हाल ही में जारी 'डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट ऑन द ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक, 2025/ का एक महत्वपूर्ण पूरक भी है।

ये दोनों रिपोर्ट्स मिलकर यह दर्शाती हैं कि लगभग सभी देश प्रभावी तंबाकू नियंत्रण उपायों को अपनाने और लागू करने में आगे बढ़ रहे हैं। कई देश पहले से ही इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें तंबाकू उपयोग में उल्लेखनीय कमी शामिल है, और इसके परिणामस्वरूप सीधे स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ भी देखे जा रहे हैं।

रिपोर्ट कहती है कि दुनिया भर में तंबाकू सेवन को कम करने के प्रयासों का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2000 में जहां 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 1.379 अरब लोग किसी न किसी तंबाकू उत्पाद का उपयोग करते थे, वहीं 2024 में यह संख्या घटकर 1.202 अरब रह गई। अनुमान है कि 2025 तक यह आंकड़ा और घटकर 1.196 अरब हो जाएगा। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

हालांकि, तंबाकू उपयोग में यह गिरावट एक नई चुनौती के साथ सामने आई है। दुनिया भर में लगभग 1.5 करोड़ किशोर, जिनकी आयु 13 से 15 वर्ष के बीच है, ई-सिगरेट या वेपिंग का उपयोग कर रहे हैं। जिन देशों में इस संबंध में आंकड़े उपलब्ध हैं, वहां किशोर, वयस्कों की तुलना में औसतन नौ गुना अधिक वेपिंग करते पाए गए हैं। इसके अलावा, करीब 4 करोड़ किशोर पारंपरिक तंबाकू उत्पादों का भी सेवन कर रहे हैं।

लिंग के आधार पर देखें तो 2024 में कुल तंबाकू उपयोगकर्ताओं में 83 प्रतिशत पुरुष हैं। इस वर्ष पुरुष उपयोगकर्ताओं की संख्या 99.7 करोड़ और महिला उपयोगकर्ताओं की संख्या 20.6 करोड़ दर्ज की गई। महिलाओं में तंबाकू सेवन में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वर्ष 2000 में जहां 34.2 करोड़ महिलाएं तंबाकू का उपयोग करती थीं, वहीं 2024 में यह संख्या घटकर 20.6 करोड़ रह गई है। 2030 तक इसके 18.2 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।

क्षेत्रीय स्तर पर दक्षिण-पूर्व एशिया में सबसे अधिक सुधार देखने को मिला है। 2010 से 2025 के बीच इस क्षेत्र में लगभग 6.9 करोड़ तंबाकू उपयोगकर्ताओं की कमी आने का अनुमान है। इसके विपरीत, अफ्रीका और पूर्वी भूमध्यसागरीय क्षेत्रों में तंबाकू उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ने की आशंका बनी हुई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि तंबाकू उद्योग लगातार बदलती रणनीतियों के जरिए नई पीढ़ी को निकोटीन की लत की ओर धकेल रहा है। संस्था के स्वास्थ्य निर्धारक, संवर्धन और रोकथाम विभाग के निदेशक डॉ. एटियेन क्रुग के अनुसार, 'तंबाकू से हर साल लाखों लोगों की मौत होने के बावजूद बड़ी तंबाकू कंपनियां अपने व्यापार मॉडल को नया रूप दे रही हैं। वे एक ओर घातक सिगरेट से मुनाफा कमाना जारी रखे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर फ्लेवरयुक्त ई-सिगरेट, निकोटीन पाउच और अन्य निकोटीन उत्पादों को आक्रामक रूप से बढ़ावा दे रही हैं, जिनका लक्ष्य अगली पीढ़ी को अपनी गिरफ्त में लेना है। निकोटीन अत्यधिक नशे की लत पैदा करने वाला पदार्थ है और उच्च मात्रा में लेने पर यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। बच्चों, किशोरों और युवाओं के लिए इसका खतरा और अधिक है क्योंकि इस आयु वर्ग में मस्तिष्क का विकास अभी जारी रहता है। विशेषज्ञों के अनुसार, कम उम्र में निकोटीन के संपर्क में आने से लंबे समय तक लत लगने और मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने का जोखिम बढ़ जाता है।

सामाजिक मुद्दे, क्राइम और इमोशंस का दमदार मिश्रण, स्टारकास्ट ने बताया क्यों खास है 'द नर्मदा स्टोरी'

मुंबई। मध्य प्रदेश की पृष्ठभूमि पर बनी अपकमिंग क्राइम-ड्रामा फिल्म 'द नर्मदा स्टोरी' सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय और एक आदिवासी महिला के संघर्ष की कहानी को बड़े पर्दे पर पेश करने जा रही है। फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह एक आदिवासी महिला न्याय के लिए लड़ती है और व्यवस्था की सच्चाइयों का सामना करती है। फिल्म की टीम इश्तियाक खान, आईपीएस अधिकारी और अभिनेत्री सिमाला प्रसाद, अभिनेता मुकेश तिवारी, और निर्देशक जैगम इमाम ने फिल्म के विषय, किरदारों और सामाजिक संदेश पर समाचार एजेंसी आईएएनएस से खुलकर बात की।

निर्देशक जैगम इमाम से पूछा गया कि क्या यह फिल्म किसी सच्ची घटना पर आधारित है? इस विषय पर काम करना कितना भावुक अनुभव रहा? तो उन्होंने बताया, यह फिल्म पूरी तरह किसी एक सच्ची घटना पर आधारित नहीं है, बल्कि कई घटनाओं, खबरों और फाइलों का मिश्रण है। अलग-अलग इलाकों में होने वाली कई घटनाओं को जोड़कर इसकी कहानी बनाई गई है, इसलिए हम यह दावा नहीं करते हैं कि यह सिर्फ एक घटना की कहानी है।

फिल्म में आदिवासी महिला अग्नि धुर्वे और उसकी बेटी की कहानी बेहद भावुक है। कैसे वह एक पुलिस इंस्पेक्टर से मिलती है और उसकी जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं, यह दर्शकों को फिल्म देखकर समझ आएगा। अश्विनी कालसेकर ने आदिवासी महिला का किरदार बहुत ही भावनात्मक तरीके से निभाया है। कई दृश्यों की एडिटिंग और साउंड के दौरान हमारी आंखें भी नम हो गई थीं। मुझे विश्वास है कि दर्शक भी उस दर्द और संघर्ष को महसूस करेंगे।

मुकेश तिवारी से पूछा गया कि ट्रेलर में आप पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आ रहे हैं। यह किरदार आपको कितना प्रभावित करता है? तो उन्होंने बताया कि एक अभिनेता के तौर पर जरूरी नहीं कि कहानी मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करे, लेकिन दर्शकों तक उसका प्रभाव पहुंचना बहुत जरूरी है। कलाकार को कई बार तटस्थ रहना पड़ता है ताकि वह किरदार को सही तरीके से पेश कर सके। मेरे किरदार में एक व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण है। वह परिस्थितियों को अलग नजरिए से देखता है। उदाहरण के तौर पर उसके लिए एक ट्यूबलाइट बदलना भी जिंदगी का बड़ा काम बन जाता है। हमने इस किरदार में हल्की कॉमेडी डालने की कोशिश की है, ताकि गंभीर माहौल के बीच दर्शकों को अलग अनुभव मिल सके।

आईपीएस ऑफिसर-अभिनेत्री सिमाला प्रसाद से पूछा गया कि आप खुद आईपीएस अधिकारी हैं, और फिल्म भी पुलिस सिस्टम पर आधारित है। आपकी असल जिंदगी ने इस किरदार को कितना प्रभावित किया?

सिमाला ने बताया, 'लोगों को लगता है कि वर्दी पहनने वाले सभी लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति की जिम्मेदारी और संघर्ष अलग होते हैं। फिल्म में मेरा किरदार एक महिला सब-इंस्पेक्टर का है, जिसकी जिंदगी और संघर्ष मेरी वास्तविक जिंदगी से काफी अलग हैं। उस किरदार ने कठिन परिस्थितियों से निकलकर पुलिस में आने का फैसला किया है। महिला पुलिसकर्मियों के अपने अलग संघर्ष और चुनौतियां होती हैं, और फिल्म में उन्हीं पहलुओं को दिखाया गया है।'

सिमाला प्रसाद का मानना है कि सिनेमा समाज की सोच बदल सकता है, खासकर महिलाओं की सुरक्षा और न्याय जैसे मुद्दों पर। उन्होंने बताया कि सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जिसकी पहुंच बहुत व्यापक होती है।

जब लेखक के नाम पर चलती थीं फिल्में: पोस्टर्स पर लिखा होता था 'पंडित मुखराम शर्मा की फिल्म'

मुंबई। भारतीय सिनेमा में आज अभिनेता और निर्देशक सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं, लेकिन लेखक भी इसका एक मजबूत स्तम्भ होता है। एक दौर ऐसा भी था जब फिल्मों की सफलता का सबसे बड़ा आधार उनके लेखक हुए करते थे। उस दौर में एक नाम ऐसा था, जिसकी मौजूदगी ही फिल्म के सफल होने की गारंटी मानी जाती थी। यह नाम था पंडित मुखराम शर्मा का।

पंडित मुखराम शर्मा ने हिंदी सिनेमा में कहानी, पटकथा और संवाद लेखन को नई पहचान दिलाई। उन्होंने सिर्फ फिल्मों की स्क्रिप्ट नहीं लिखी, बल्कि लेखकों को वह सम्मान दिलाया जो पहले शायद ही किसी को मिला था। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फिल्म के पोस्टरों पर बड़े अक्षरों में 'पंडित मुखराम शर्मा की फिल्म' लिखा जाता था।

पंडित मुखराम शर्मा का जन्म 30 मई 1909 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के परीक्षितगढ़ क्षेत्र के गांव पूठी में हुआ था। वे हिंदी और संस्कृत के अच्छे जानकार थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने मेरठ में शिक्षक के रूप में काम शुरू किया। हालांकि, उनका मन फिल्मों और लेखन की दुनिया में ज्यादा लगता था। उन्हें कहानी और कविताएं लिखने का शौक था, और धीरे-धीरे उन्होंने फिल्मों के लिए लिखने का सपना देखना शुरू कर दिया।

साल 1939 में वह अपने परिवार के साथ मुंबई पहुंचे, लेकिन शुरुआती दिनों में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। काम न मिलने की वजह से वह पुणे चले गए, जहां मशहूर फिल्मकार वी. शांताराम की प्रभात फिल्म कंपनी में उन्होंने कलाकारों को हिंदी उच्चारण सिखाने का काम किया। इस काम के बदले उन्हें मामूली वेतन मिलता था, लेकिन यहीं से उनकी फिल्मी यात्रा ने दिशा पकड़ी।

मुखराम शर्मा को फिल्मों में पहला बड़ा मौका साल 1942 में मिला, जब उन्होंने फिल्म 'दस बजे' के लिए गीत और संवाद लिखे। फिल्म सफल रही, और इसके बाद उन्हें लगातार काम मिलने लगा। धीरे-धीरे उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली। 'विष्णु भगवान', 'नल-दमयंती', 'औलाद', 'एक ही रास्ता', 'साधना', 'धूल का फूल', 'वचन', 'संतान' और 'अभिमान' जैसी फिल्मों ने उन्हें हिंदी सिनेमा के शानदार लेखकों में शामिल कर दिया।

साल 1959 में रिलीज हुई 'धूल का फूल' खास तौर पर चर्चा में रही।

इंडोनेशिया और जापान जैसे देशों में क्यों आते हैं बार-बार भूकंप? रिंग ऑफ फायर के रेड जोन में स्थित हैं ये देश

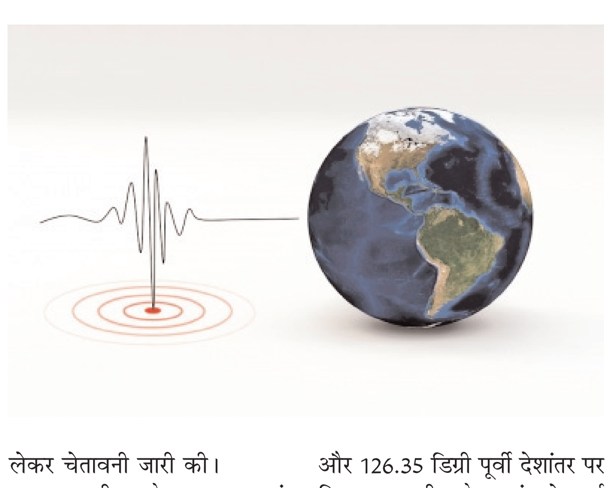

नई दिल्ली। इंडोनेशिया में गुरुवार को जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस हुए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.4 रही। अमेरिका के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) ने बताया कि गुरुवार तड़के पूर्वी इंडोनेशिया के तट से दूर समुद्र में 7.4 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस समेत कुछ ऐसे देश हैं, जहां अक्सर भूकंप के झटके महसूस होते हैं।

गुरुवार को झटके के बाद एक अमेरिकी निगरानी एजेंसी ने भूकंप के केंद्र से 1,000 किलोमीटर के दायरे में सुनामी की संभावना को लेकर चेतावनी जारी की।

यूएसजीएस के अनुसार, भूकंप का केंद्र 1.20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 126.35 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था। चीन के भूकंप नेटवर्क केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक, यह भूकंप लगभग 30 किलोमीटर की गहराई पर आया।

यूएसजीएस ने आगे बताया कि यह भूकंप, जिसकी तीव्रता शुरू में 7.8 मापी गई थी, स्थानीय समय के अनुसार सुबह लगभग 6:48 बजे मोलुक्का सागर में आया।

जापान, फिलीपींस और इंडोनेशिया में बार-बार भूकंप आने का मुख्य कारण इन देशों का 'पैसिफिक रिंग ऑफ फायर' में स्थित होना है। ये देश कई बड़ी टेक्टोनिक प्लेटों (जैसे प्रशांत, यूरेशियन और फिलीपीन प्लेट) के मिलन स्थल पर स्थित हैं।

इसी वजह से यहां प्लेटों के आपस में टकराने, रगड़ने या एक-दूसरे के नीचे धंसने से भारी ऊर्जा निकलती है, जो भूकंप का रूप लेती है। रिंग ऑफ फायर एक अति सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है, जहां 80 फीसदी भूकंप आते हैं।

जापान चार प्रमुख प्लेटों, पैसिफिक, फिलीपीन सी, यूरेशियन और उत्तरी अमेरिकी प्लेटों के मिलन बिंदु पर स्थित है। इंडोनेशिया इंडो-ऑस्ट्रेलियाई, यूरेशियन और प्रशांत प्लेटों की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा फिलीपींस फिलीपीन सागर प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच स्थित है।

टीवी इंडस्ट्री की कास्टिंग प्रक्रिया पर आंचल खुराना ने उठाए सवाल, बोलीं- खतरे में भविष्य

मुंबई। अभिनेत्री आंचल खुराना ने टेलीविजन इंडस्ट्री में चल रही कास्टिंग प्रक्रिया और कलाकारों को मिलने वाले पारिश्रमिक को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उनका मानना है कि गलत कास्टिंग और प्रतिभाशाली कलाकारों की अनदेखी के कारण टीवी इंडस्ट्री को भविष्य में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

मीडिया से बातचीत के दौरान आंचल ने कहा कि आजकल निर्माता और कास्टिंग टीम कम बजट में काम करने वाले कलाकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनके अनुसार, नए कलाकार कम पैसों में काम करने को तैयार हो जाते हैं, जबकि स्थापित कलाकारों की फीस अधिक होती है। ऐसे में उन कलाकारों को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है जिन्होंने सालों की मेहनत से इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन वे बहुत बड़े स्टार भी नहीं हैं।

आंचल का कहना है कि कई बार शो में केवल एक-दो अनुभवी कलाकारों को लिया जाता है और बाकी भूमिकाओं के लिए ऐसे लोगों को चुन लिया जाता है जिन्हें अभिनय का ज्यादा अनुभव नहीं होता। उनका मानना है कि केवल लोकप्रियता, सोशल मीडिया फॉलोअर्स या आकर्षक व्यक्तित्व के आधार पर कलाकारों का चयन किया जा रहा है, जबकि अभिनय क्षमता को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक अच्छा अभिनेता दर्शकों से बेहतर जुड़ाव बना सकता है और शो की गुणवत्ता को बढ़ाता है। लेकिन यदि किसी नए कलाकार को सिर्फ उसकी लोकप्रियता के कारण मुख्य भूमिका दी जाती है, तो उसे अभिनय सीखने में समय लगता है, जिसका असर शो की शुरुआत और उसकी सफलता पर पड़ता है।

15 सालों से अधिक समय से इंडस्ट्री में सक्रिय आंचल ने बताया कि उन्हें आज भी कई प्रोजेक्ट्स के लिए प्रतिदिन केवल 5 हजार से 7 हजार रुपए तक का भुगतान ऑफर किया जाता है। उनके अनुसार, यह राशि उनके अनुभव और उपलब्धियों के मुकाबले बेहद कम है। उन्होंने इसे निराशाजनक और अपमानजनक बताया।

आंचल ने यह भी कहा कि टीवी शो पहले की तरह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।

'मया मया' से रातोंरात बनीं स्टार, मौली दवे को बप्पी लहरी ने दिया था 'इंडियन शकीरा' का खिताब

मुंबई। सिंगर, अभिनेत्री और टीवी होस्ट मौली दवे ने अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर मनोरंजन जगत में खास पहचान बनाई है। 'सा रे गा मा पा चैलेंज 2007' में अपनी दमदार गायकी से दर्शकों का दिल जीतने वाली मौली आज भी अपनी सुरीली आवाज के लिए जानी जाती हैं। खासकर फिल्म 'गुरु' के मशहूर गीत 'मया मया' की प्रस्तुति ने उन्हें रातोंरात चर्चा में ला दिया था। उनकी इस शानदार परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर संगीतकार-गायक बप्पी लहरी ने उन्हें 'इंडियन शकीरा' का खिताब दिया था।

3 जून 1987 को अहमदाबाद में जन्मीं मौली दवे का संगीत से जुड़ाव बचपन से ही रहा है। शुरुआती शिक्षा गुजरात में पूरी करने के बाद उनका परिवार अमेरिका के टेक्सास में जाकर बस गया। वहीं, उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और टेक्सास यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने संगीत की शिक्षा भी जारी रखी और भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण लिया।

संगीत के प्रति अपने जुनून को करियर में बदलने के लिए मौली ने मात्र 19 वर्ष की उम्र में मुंबई का रुख किया। उस समय वह अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। इसी दौरान उन्हें 'सा रे गा मा पा चैलेंज 2007' में हिस्सा लेने का मौका मिला। इस शो के विदेशी ऑडिशन में चयनित होने के बाद उन्होंने अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया और अपनी गायकी से सभी को प्रभावित किया।

शो में मौली ने गुरु फिल्म के गाना 'मया मया' को गाया था, जिसे दर्शकों के साथ ही जजों ने भी खूब सराहा। उनकी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस, आत्मविश्वास और अलग अंदाज ने उन्हें प्रतियोगिता की सबसे चर्चित प्रतिभागियों में शामिल कर दिया। भले ही वह शो की विजेता नहीं बन सकीं, लेकिन फाइनलिस्ट के रूप में उन्होंने अपनी मजबूत पहचान बनाई। बप्पी लहरी द्वारा दिया गया 'इंडियन शकीरा' का खिताब उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाने वाला साबित हुआ।

गायकी के अलावा, मौली ने अभिनय और एंकरिंग की दुनिया में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। साल 2008 में उन्होंने जी टीवी के फैमिली शो 'रॉक एन रोल फैमिली' को होस्ट किया। इसके अलावा उन्होंने ज़ूम टीवी की टेलीफिल्म 'एक अनहोनी' में अभिनय किया। वह निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी के स्टंट बेस्ड एडवेंचर रियलिटी शो 'फियर फैक्टर: खतरों के खिलाड़ी' का भी हिस्सा रह चुकी हैं, जिसके जरिए मौली ने अपनी साहसिक छवि दर्शकों को दिखाई।

चंडीगढ़ में बादशाह के क्लब पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, नियमों के उल्लंघन पर किया गया सील

चंडीगढ़। चंडीगढ़ में प्रशासन ने नियमों के उल्लंघन को लेकर सख्त कदम उठाते हुए मशहूर सिंगर और रैपर बादशाह से जुड़े एक चर्चित क्लब को सील कर दिया है।

दरअसल, चंडीगढ़ प्रशासन की बिल्डिंग ब्रांच और एस्टेट ऑफिस की टीम ने सेक्टर-26 स्थित क्लब पर कार्रवाई की है। अधिकारियों ने क्लब के मुख्य द्वार पर सील लगाकर उसे बंद कर दिया है। प्रशासन का कहना है कि क्लब में नियमों का पालन नहीं किया गया था और निर्धारित दिशा-निर्देशों के विरूद्ध बदलाव किए गए थे। इसी कारण यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार, प्रशासन को काफी समय से क्लब में निर्माण संबंधी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की शिकायतें मिल रही थीं। जांच के दौरान पाया गया कि बिल्डिंग में कुछ ऐसे बदलाव किए गए थे जो नक्शे और निर्धारित बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप नहीं थे। अधिकारियों ने कई बार नोटिस जारी कर नियमों के अनुसार कमियां दूर करने और बिल्डिंग को स्वीकृत मानकों के अनुरूप करने के निर्देश दिए थे।

प्रशासन का दावा है कि बार-बार चेतावनी देने और पर्याप्त समय देने के बावजूद क्लब में पॉलिसी के अनुसार जरूरी बदलाव नहीं किए गए। ऐसे में नियमों के तहत कार्रवाई करना जरूरी हो गया। इसी के तहत टीम मौके पर पहुंची और क्लब के मुख्य दरवाजों को सील कर दिया गया।

रवीना टंडन की मां के 25 लाख के गहने और महंगी घड़ियां चोरी, आरोपी महिला गिरफ्तार

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन की मां के घर से करीब 25 लाख रुपए के गहने और महंगी घड़ियां चोरी होने के मामले में मुंबई पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी महिला कई सालों से परिवार के संपर्क में थी, और उसने धीरे-धीरे परिवार का विश्वास जीतकर इस वारदात को अंजाम दिया।

मुंबई पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार की गई महिला का नाम राशि छाबड़िया है और उसकी उम्र 47 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि राशि साल 2020 से टंडन परिवार के संपर्क में थी। वह अभिनेत्री की मां वीणा टंडन की देखभाल के लिए घर आती-जाती थी, जिसके चलते वह परिवार के भरोसेमंद लोगों में शामिल हो चुकी थी। वह खाना बनाने से लेकर वीणा टंडन की देखभाल तक सभी काम करती थी।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि समय के साथ आरोपी महिला ने परिवार का भरोसा जीता। इसी भरोसे का फायदा उठाते हुए उसने कथित तौर पर घर में रखे कीमती सामान पर नजर रखी और मौका पाकर गहनों के साथ दो महंगी घड़ियां भी चुरा लीं।

मामले का खुलासा तब हुआ, जब परिवार ने लॉकर की जांच की और पाया कि उसमें रखे गहने और घड़ियां गायब हैं। इसके बाद घर में आने-जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई और राशि छाबड़िया से भी पूछताछ की गई। हालांकि शुरुआती पूछताछ में उसने चोरी में किसी भी तरह की भूमिका होने से साफ इनकार कर दिया।

लेकिन जब उससे दोबारा पूछताछ की गई, तो उसने चोरी की गई महंगी घड़ियां वापस कर दीं और साथ ही बताया कि बाकी गहने उसने जगदीश नाम के एक व्यक्ति को दे दिए हैं और उन्हें भी वह जल्द लौटा देगी।

वहीं रवीना टंडन की बात करें तो, वह इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' को लेकर चर्चा में है। यह एक कॉमेडी-ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन अहमद खान ने किया है।

रवीना टंडन के अलावा फिल्म में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, दिशा पाटनी, लारा दत्ता समेत कई सितारे मौजूद हैं। इस फिल्म का म्यूजिक मीट ब्रदर्स ने तैयार किया है। यह फिल्म 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

'इंडियाज बेस्ट डांसर' में हुई बॉलीवुड डांस के इतिहास पर चर्चा, 'आलम आरा' का हुआ जिक्र

मुंबई। 'इंडियाज बेस्ट डांसर' शो भारतीय सिनेमा के सुनहरे इतिहास को याद करने का एक खास मंच बन गया है। शो के सेट पर जज जावेद जाफरी, टेरेंस लुईस और होस्ट हर्ष लिंबाचिया ने मिलकर बॉलीवुड डांस के डेवलपमेंट पर चर्चा की, जिसमें पुराने दौर की फिल्मों से लेकर आज के मॉडर्न डांस तक का सफर याद किया गया।

बातचीत के दौरान भारतीय सिनेमा की पहली टॉकी मूवी 'आलम आरा' का भी जिक्र हुआ, जिसे भारतीय फिल्म इतिहास की शुरुआत का एक बड़ा पड़ाव माना जाता है। शो के दौरान हर्ष लिंबाचिया ने पूछा कि बॉलीवुड में पहली बार डांस की झलक किस फिल्म में देखने को मिली थी।

उन्होंने आगे कहा, ''मैं बता देता हूं कि शुरुआती दौर में फिल्म 'आलम आरा' में डांस और प्रदर्शन की शुरुआती झलक सामने आई थी। उस समय के कलाकारों ने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि आने वाले समय में भारतीय सिनेमा में डांस इतनी बड़ी पहचान बन जाएगा। 'आलम आरा' में पृथ्वीराज कपूर थे और उसी परिवार की परपोती करिश्मा कपूर बॉलीवुड डांस की पहचान बनेंगी।''

जावेद जाफरी ने इस मौके पर दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर को याद किया और उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा, ''पृथ्वीराज कपूर की स्क्रीन प्रेजेंस बेहद मजबूत थी और उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। उनके बाद राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर जैसे महान कलाकार शामिल रहे। कपूर परिवार ने भारतीय सिनेमा को एक अलग तरह की ऊर्जा दी, जो आज भी याद की जाती है।''

इसके बाद टेरेंस लुईस ने बॉलीवुड डांस के बदलते स्वरूप पर बात की। उन्होंने कहा, 'हिंदी सिनेमा में डांस का स्तर धीरे-धीरे बदला और इसमें कई प्रशिक्षित कलाकारों का बड़ा योगदान रहा। अभिनेत्रियों ने क्लासिकल डांस की ट्रेनिंग के साथ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इनमें वैजयंतीमाला, हेमा मालिनी और श्रीदेवी जैसे नाम शामिल है। इन कलाकारों ने अपनी तकनीक और अनुशासन से बॉलीवुड डांस को एक नया स्तर दिया और उसे अधिक प्रभावशाली बनाया।''

टेरेंस लुईस ने आगे कहा, ''इसके बाद जब माधुरी दीक्षित का दौर आया, तो बॉलीवुड डांस में एक नई ऊर्जा देखने को मिली। उनके एक्सप्रेशन और डांस स्टाइल ने दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी। माधुरी के बाद करिश्मा कपूर ने भी डांस में एक अलग फिल्मी अंदाज़ जोड़ा।

'एक्सपायरी डेट के बाद दवा भी जहर बन जाती है', 'कॉकटेल 2' के ट्रेलर में दिखी दोस्ती, प्यार और रिश्तों की उलझनें

मुबंई। साल 2012 में आई फिल्म 'कॉकटेल' ने दोस्ती, प्यार और रिश्तों की कहानी को एक नए अंदाज में दर्शकों के सामने पेश किया था। सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी की तिकड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। अब करीब 14 साल बाद निर्देशक होमी अदजानिया 'कॉकटेल 2' लेकर लौटे हैं। इस बार फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर में रोमांस, दोस्ती, इमोशन्स, कॉमेडी और रिश्तों की उलझनें एक साथ देखने को मिलती हैं।

करीब तीन मिनट के ट्रेलर की शुरुआत शाहिद कपूर के किरदार कुणाल के एक दिलचस्प लाइन से होती है, जिसमें वह कहता है, 'रिश्ता जब नया होता है ना, तो एक्साइटिंग होता है, नए दोस्त मजेदार लगते हैं, क्योंकि उनकी कहानियां हमारे लिए नई लगती हैं, लेकिन प्यार उस फटी हुई टी-शर्ट की तरह होता है, जिसमें हम रोज रात सुकून से सोते हैं, और जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है, तो इससे बचने का एक ही सॉल्यूशन रह जाता है।'

इसके बाद ट्रेलर में सभी के किरदारों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। कुणाल के रोल में शाहिद कपूर, दीया के किरदार में रश्मिका मंदाना और एली की भूमिका में कृति सेनन हैं। तीनों अच्छे दोस्त हैं। तीनों साथ घूमते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, मस्ती करते हैं और जिंदगी को खुलकर जीते हैं।

शुरुआत में सब कुछ मजेदार दिखाई देता है, लेकिन धीरे-धीरे कहानी में मोड़ आना शुरू हो जाता है, जब दोस्ती के बीच प्यार की एंट्री होती है, और यहीं से रिश्तों की उलझनें शुरू हो जाती हैं।

ट्रेलर में लव ट्रायंगल देखने को मिलता है। कहानी में दिखाया गया है कि दीया और एली दोनों ही कुणाल के करीब आने लगती हैं। पहले जो रिश्ता केवल दोस्ती का था, वह धीरे-धीरे लव फीलिंग में बदल जाता है। शाहिद का किरदार खुद भी इन फीलिंग्स के बीच उलझता नजर आता है। डायलॉग्स की बात करें तो ट्रेलर में कई ऐसे डायलॉग हैं जो दर्शकों का ध्यान खींचते हैं।

ट्रंप ने लगाया ईरान पर बातचीत को लंबा खींचने का आरोप, कहा- वार्ता बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें इस बात की कोई खास चिंता नहीं है कि ईरान अमेरिका के साथ चल रही बातचीत रोक सकता है। उनका कहना था कि ईरान ने बातचीत में बहुत ज्यादा समय लिया है और उसे परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना ही ट्रंप प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।

सीएनबीसी के वरिष्ठ वाशिंगटन संवाददाता ईमोन जेवर्स के साथ फोन पर बातचीत में ट्रंप ने इस बात को खारिज कर दिया कि अगर बातचीत टूट जाती है तो उनकी रणनीति में कोई बड़ा बदलाव आएगा। यह बयान ऐसे समय आया जब तेल बाजारों में इस खबर के बाद तेज प्रतिक्रिया देखी गई कि ईरान अब बातचीत जारी रखने के लिए तैयार नहीं है।

जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान के साथ बातचीत खत्म हो गई है, तो ट्रंप ने कहा, 'सच कहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बातचीत खत्म हुई या नहीं। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है।'

उन्होंने आगे कहा, 'अगर खत्म हो गई है, तो हो गई है। अगर नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ज्यादा समय लिया। सच कहूं तो यह बातचीत अब काफी उबाऊ लगने लगी थी।'

ट्रंप ने ईरान पर बातचीत को जानबूझकर लंबा खींचने का आरोप लगाया। इसमें बहुत ज्यादा समय लग गया। मुझे लगा कि वे बस हमें टाल रहे थे।

जब उनसे सीधे पूछा गया कि क्या ईरान जानबूझकर समय बर्बाद कर रहा था, तो उन्होंने जवाब दिया, 'हां, मुझे ऐसा ही लगा।' यह इंटरव्यू ऐसे समय हुआ जब ऊर्जा बाजारों में इस आशंका के कारण हलचल थी कि कूटनीतिक प्रयास विफल हो सकते हैं। जेवर्स ने बताया कि ईरान के बातचीत से पीछे हटने की खबरों के बाद तेल की कीमतों में आठ प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई।

हालांकि ट्रंप ने बढ़ती तेल कीमतों को लेकर चिंता जताने से इनकार किया। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें तेल की कीमतों की चिंता है, तो उन्होंने कहा, 'नहीं, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है।' राष्ट्रपति ने तर्क दिया कि तेल की कीमतें जल्द ही कम हो जाएंगी, और इसके लिए उन्होंने वैश्विक बाजारों में पहले से ही मौजूद तेल की भारी मात्रा का हवाला दिया। उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि बहुत जल्द तेल की कीमतें तेजी से नीचे आएंगी। इस समय 1,700 जहाज तेल से भरे हुए हैं और यह किसी बड़े तेल प्रवाह की तरह बाजार में पहुंचेगा।'

विदेश मंत्री जयशंकर से मिले जर्मन राजनेता मारियो, व्यापार और तकनीक पर हुई बात

नई दिल्ली। जर्मनी के थ्यूरिंगिया राज्य के मिनिस्टर-प्रेसिडेंट मारियो वोग्ट ने मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। दोनों के बीच व्यापार और तकनीकी साझेदारी को लेकर अहम बातचीत हुई। विदेश मंत्री ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने इस मुलाकात को हर्ष का विषय बताया। लिखा, 'थ्यूरिंगिया के मिनिस्टर-प्रेसिडेंट मारियो वोग्ट और उनके प्रतिनिधिमंडल से मिलकर खुशी हुई।'

उन्होंने पोस्ट में मुलाकात के दौरान हुई चर्चा का उल्लेख किया। बताया कि भारत-जर्मनी और भारत-यूरोपीय संघ संबंधों के विस्तार के प्रति उनका मजबूत सहयोग स्वागतयोग्य है। दोनों की व्यापार और प्रौद्योगिकी साझेदारियों पर सार्थक चर्चा हुई।

मंगलवार को ही मारियो वोग्ट और उनके प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान स्मार्ट शहरी विकास, टिकाऊ बुनियादी ढांचा, डिजिटल प्रशासन, नवाचार, कौशल विकास और प्रतिभा आदान-प्रदान जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई।

बैठक में परिवहन, जल प्रबंधन, पर्यावरणीय तकनीकों, शिक्षा और कार्यबल विकास के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत और जर्मनी के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं, और दिल्ली इस साझेदारी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत और जर्मनी लंबे समय से घनिष्ठ रणनीतिक साझेदार रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, हरित ऊर्जा, कौशल विकास और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग है।

संक्षिप्त खबर

आयोवा में गोलीबारी, सात की मौत

न्यूयॉर्क। अमेरिका से एक बार फिर गोलीबारी की दहला देने वाली खबर आई। आयोवा के मस्कटाइन में अलग-अलग जगहों पर फायरिंग के बाद संदिग्ध बंदूकधारी समेत सात लोग मृत पाए गए। मस्कटाइन पुलिस ने बताया कि सोमवार को स्थानीय समयानुसार (1712 जीएमटी) के हिसाब से दोपहर करीब 12:12 बजे एक घर में गोलीबारी की खबर मिलने पर अधिकारी मौके पर पहुंचे। यहां घर के अंदर चार लोगों को घायलावस्था में पाया। चारों को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। जांच कर्मियों ने 52 साल के आदमी की पहचान संदिग्ध के तौर पर की, जो अधिकारियों के पहुंचने से पहले घर से निकल गया था और बाद में रिवरफ्रंट ट्रेल पर घायल हालत में मिला। उसने खुद को गोली मारी थी। सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, उसे भी मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों को दूसरे घर में एक और स्थानीय बाजार में एक और शव मिला। पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा, 'शुरुआती जांच से पता चलता है कि गोलीबारी घरेलू झगड़े की वजह से हुई थी। इस समय, माना जा रहा है कि सभी मृतक संदिग्ध के परिजन थे।' इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है।

अमेरिकी प्रतिबंधों से 'पिक्स' सिस्टम को खतरे की आशंका, ब्राजील ने जताई चिंता

साओ पाउलो। ब्राजील के वित्त मंत्री डारियो डुरिगन ने सोमवार को बताया कि वह इस हफ्ते अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में वे अपराधी संगठनों को 'अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी समूह' घोषित करने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि ऐसा कदम उठाने से भविष्य में ब्राजील की आर्थिक संप्रभुता के लिए खतरा पैदा हो सकता है।

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, डुरिगन का कहना है कि ब्राजील के दो बड़े अपराधी गिरोहों, 'प्राइमिरो कमांडो दा कैपिटल' और 'कमांडो वर्मेलहो' को आतंकवादी घोषित करने से नई मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ऐसा करने से देश पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकते हैं, जिसका बुरा असर ब्राजील की इंस्टेंट पेमेंट सर्विस यानी 'पिक्स' पर पड़ सकता है। इससे देश की आर्थिक संप्रभुता के लिए खतरा पैदा हो सकता है। सीबीएन रेडियो को दिए एक इंटरव्यू में डुरिगन ने चेतावनी दी कि अमेरिका के इस कदम का असर ब्राजील के वित्तीय संस्थानों पर पड़ सकता है और यहां तक कि 'पिक्स' के संचालन को भी खतरा हो सकता है। डुरिगन ने कहा कि ये अपराधी समूह 'सामाजिक आतंक' फैलाते हैं और देश के कई हिस्सों में सार्वजनिक सेवाओं को बाधित करते हैं। ले ?कि ?न ये अमेरिकी कानून में तय उन मानदंडों को पूरा नहीं करते, जिनके आधार पर किसी संगठन को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित किया जाता है।

लेबनान का दावा : हिज्बुल्लाह ने इजरायल के साथ आपसी हमले रोकने के अमेरिकी प्रस्ताव को माना

बेरूत। लेबनान के अधिकारियों ने पुष्टि करते हुए बताया कि हिज्बुल्लाह ने अमेरिका के एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस प्रस्ताव में इजरायल के साथ 'आपसी हमलों को रोकने' की बात कही गई है। यह जानकारी लेबनानी राष्ट्रपति कार्यालय के एक बयान में दी गई, जिसमें लेबनान के अमेरिका स्थित दूतावास का हवाला दिया गया है।

यह बयान सोमवार (स्थानीय समय) को जारी किया गया। इसमें कहा गया कि यह पुष्टि उस फोन कॉल के बाद हुई, जो लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के बीच हुई थी। इस बातचीत में लेबनान की स्थिति और तनाव कम करने के प्रयासों पर चर्चा हुई। दूतावास के अनुसार, अमेरिकी प्रस्ताव में कहा गया है कि दोनों पक्ष एक-दूसरे पर हमले रोकेंगे। इस प्रस्ताव के तहत, बेरूत के दक्षिणी इलाकों पर इजरायल के हवाई हमले रुक जाएंगे। बदले में हिज्बुल्लाह इजरायल पर अपने हमले बंद करेगा। बाद में इस समझौते को पूरे लेबनान तक लागू करने की योजना है।

दूतावास ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में अमेरिका में लेबनानी राजदूत नाडा हमदेह मौवाड को बताया कि उन्होंने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की इस प्रस्ताव पर सहमति ले ली है।

इसके बाद मौवाड ने यह जानकारी राष्ट्रपति आउन को दी, जिन्होंने आगे यह बात हिज्बुल्लाह तक पहुंचाई। बयान के अनुसार, मंगलवार और बुधवार को होने वाली बातचीत में इस समझौते को आगे बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी।

वहीं, ईरान की अर्ध-सरकारी तस्नीम समाचार एजेंसी ने सोमवार को रिपोर्ट किया कि ईरान ने इजरायल की लेबनान में कार्रवाई के विरोध में अमेरिका के साथ मध्यस्थों के जरिए होने वाली बातचीत रोक दी है। इसी दिन, इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने कहा कि उन्होंने बेरूत के दहिये इलाके पर हमले के आदेश दिए हैं। यह इलाका हिज्बुल्लाह का गढ़ माना जाता है। यह कदम हिज्बुल्लाह की ओर से इजरायली सैन्य ठिकानों पर बढ़ते रॉकेट और ड्रोन हमलों के बाद उठाया गया।

किम जोंग-उन ने पार्टी स्कूल को बताया 'रणनीतिक किला'

सोल। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन ने सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया (डब्ल्यूपीके) के एक अहम राजनीतिक स्कूल का दौरा किया। यह दौरा उस स्कूल की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर किया गया। उन्होंने इस स्कूल को पार्टी का 'रणनीतिक किला' बताया, जो पार्टी के अस्तित्व को बनाए रखने में मदद करता है।

कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी (केसीएनए) के अनुसार, किम जोंग-उन एक दिन पहले पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ डब्ल्यूपीके के 'सेंट्रल कैडर्स ट्रेनिंग स्कूल' में गए थे। यह उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा राजनीतिक शिक्षा संस्थान है, जहां पार्टी के अधिकारियों को तैयार और प्रशिक्षित किया जाता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि किम ने अपने भाषण में कहा कि यह स्कूल अब अपने 'पवित्र मूल नाम' को और मजबूत कर रहा है, जो पार्टी के अस्तित्व और विकास की गारंटी देने वाला अहम किला बन गया है। उन्होंने यह भी कहा कि युवा अधिकारियों को पार्टी की विचारधारा ठीक से सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नई पीढ़ी के कुछ लोगों में पार्टी के प्रति पूरी निष्ठा की कमी हो सकती है।

किम ने जोर दिया कि उत्तर कोरिया की 'जन-केंद्रित नीति' समय बदलने के बावजूद नहीं बदलेगी। लेकिन उन्होंने यह भी माना कि 'जन-विरोधी काम' जैसे सत्ता का दुरुपयोग, नौकरशाही और भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं भी सामने आई हैं।

इस्फहान में अमेरिका-इजरायल हमलों के बाद बचे विस्फोटकों को ईरान ने किया निष्क्रिय

तेहरान। ईरान ने इस्फहान में उन विस्फोटकों को निष्क्रिय (नष्ट) किया, जो हाल ही में अमेरिका-इजरायल हमलों के दौरान फटे नहीं थे। यह कार्रवाई क्षेत्र में विस्फोट की आशंका को रोकने के उद्देश्य से की गई।

मेहर न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, यह विस्फोटक सामग्री उस क्षेत्र में मिली थी, जिसे पहले हुए सैन्य हमलों में निशाना बनाया गया था। अधिकारियों ने बताया कि इन अवशेषों को नियंत्रित तरीके से नष्ट किया गया ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना या नुकसान से बचा जा सके।

इस दौरान इलाके में धमाके भी सुनाई दिए। प्रशासन ने लोगों को आश्वस्त किया कि इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। स्पष्ट किया कि अभियान के दौरान सुनाई देने वाली आवाजें योजनाबद्ध और नियंत्रित विस्फोटों के कारण थीं। नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सामान्य गतिविधियां जारी रखने की अपील की गई।

इस बीच, ईरान ने कहा है कि वह अपने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा उपायों को और मजबूत कर रहा है, खासकर ऐसे समय में जब क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ रहा है। इस्फहान क्षेत्र पहले भी कई बार सैन्य और रणनीतिक ठिकानों पर हमलों का केंद्र रहा है।

राजधानी तेहरान और मशहद के बाद इस्फहान देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और इसे ईरान का महत्वपूर्ण औद्योगिक व सैन्य केंद्र माना जाता है। यहां मिसाइल और रक्षा उत्पादन से जुड़े कई अहम प्रतिष्ठान मौजूद हैं। रणनीतिक महत्व के साथ-साथ इस्फहान सांस्कृतिक दृष्टि से भी बेहद समृद्ध शहर है।

शहर के आसपास ईरान के कई संवेदनशील प्रतिष्ठान मौजूद हैं, जिनमें परमाणु अनुसंधान केंद्र, मिसाइल उत्पादन सुविधाएं, एक प्रमुख तेल रिफाइनरी और वायुसेना के अड्डे शामिल हैं।

लाओस के उप-प्रधानमंत्री ने किया ताजमहल का दीदार

आगरा। लाओस के उप-प्रधानमंत्री थोंगसावन फोमविहाने और उनकी पत्नी वदस्ना फोमविहाने ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल का दीदार किया।

फोमविहाने सोमवार को तीन दिवसीय आधिकारिक भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे थे। वे बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भारत-लाओस संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनका स्वागत करते हुए लिखा, 'लाओ पीडीआर के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंगसावन फोमविहाने का भारत में प्रथम आगमन पर हार्दिक स्वागत है, वे विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ भारत-लाओस संयुक्त आयोग की 10वीं बैठक की सह-अध्यक्षता करेंगे।'

उन्होंने कहा कि भारत और लाओस अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे कर रहे हैं, और यह यात्रा दोनों देशों के लंबे समय से चले आ रहे साझेदारी संबंधों को और गति देगी तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगी।

फोमविहाने बुधवार को भारत-लाओस बिजनेस फोरम में भी भाग लेंगे और इसके बाद वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात करेंगे। पिछले वर्ष अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के दौरान लाओस के राष्ट्रपति थोंगलून सिसोलिथ से मुलाकात की थी और दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंधों के महत्व पर जोर दिया था। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, 'राष्ट्रपति सिसोलिथ से मिलकर हर्ष की अनुभूति हुई। दोनों देशों के बीच का गहरा रिश्ता हमारे लिए लाभदायी है, ये संबंध ट्रेड से लेकर कल्चर तक में परिलक्षित होता है।'

भारत और लाओस के बीच बौद्ध धर्म और रामायण (रामकियेन) जैसी सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1956 में स्थापित हुए थे और तब से यह साझेदारी मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक रूप से लाभकारी रही है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, संस्थागत परामर्श तंत्रों में विदेश कार्यालय परामर्श और संयुक्त आयोग बैठक शामिल हैं।

तालिबान के बाल विवाह कानून की संयुक्त राष्ट्र ने की निंदा, बताया मानवाधिकारों का उल्लंघन

जिनेवा। संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकार समिति (सीआरसी) ने अफगानिस्तान में तालिबान की ओर से जारी एक नए फरमान की सख्त शब्दों में निंदा की है। इस नए कानून में बाल विवाह को वैधता देने और विवाह के लिए लड़की की चुप्पी को सहमति मानने का प्रावधान शामिल है। समिति ने इसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का 'गंभीर और व्यवस्थित उल्लंघन' बताया है।

समिति ने कहा, '18 वर्ष से कम आयु में होने वाला विवाह बाल विवाह माना जाता है, जो एक हानिकारक प्रथा और जबरन विवाह का रूप है, क्योंकि बच्चों में विवाह के लिए पूर्ण, स्वतंत्र और जान-बूझकर सहमति देने की क्षमता नहीं होती।' यह प्रतिक्रिया 14 मई को तालिबान की ओर से जारी उस कानून पर आई है, जिसमें प्यूबर्टी के बाद लड़कियों के विवाह को वैध माना गया है और लड़की की चुप्पी को विवाह की सहमति के रूप में स्वीकार किया गया है। समिति ने स्पष्ट किया कि प्यूबर्टी को वयस्कता या विवाह की कानूनी क्षमता का आधार नहीं माना जा सकता।

जापान में तूफान जांगमी का कहर : 9 घायल 47 हजार से ज्यादा घरों की बिजली गुल

टोक्यो। जापान में उष्णकटिबंधीय तूफान जांगमी (जापान में टाइफून नंबर-6) से सामान्य जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसकी वजह से मंगलवार दोपहर नौ लोग घायल हो गए, जबकि ओकिनावा और कागोशिमा में 47,000 से अधिक घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। स्थानीय मीडिया आउटलेट्स ने इसकी जानकारी दी।

द जापान टाइम्स के अनुसार, तूफान के क्यूशू क्षेत्र की ओर बढ़ने से व्यापक असर देखने को मिला। मंगलवार सुबह 11:45 बजे (स्थानीय समयानुसार) तक यह तूफान कागोशिमा प्रांत के याकूशिमा द्वीप से लगभग 140 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित था और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पूर्व दिशा में बढ़ रहा था।

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, तूफान का केंद्रीय दबाव 975 हेक्टोपास्कल दर्ज किया गया, जबकि केंद्र के पास हवा की गति 25 मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच रही थी।

क्योडो न्यूज एजेंसी के अनुसार, जापान के मुख्य कैबिनेट सचिव मिनोरू किहारा ने बताया कि मंगलवार सुबह 6 बजे तक कागोशिमा और ओकिनावा प्रांतों में छह घरों को आंशिक नुकसान, सड़कों पर जलभराव, पेड़ों के गिरने और तेज हवाओं से वस्तुओं के उड़ने की घटनाएं सामने आई हैं। घायल हुए सभी नौ लोगों को मामूली चोटें आई हैं।

सुबह 5 बजे तक दोनों प्रांतों में लगभग 47,930 घरों की बिजली गुल थी। वहीं, परिवहन सेवाएं भी प्रभावित हुईं। एहतियात के तौर पर 15 खंडों वाले दो एक्सप्रेसवे मार्ग बंद कर दिए गए और एक रेल लाइन पर सेवाएं निलंबित कर दी गईं। इसके अलावा, छह अन्य रेल ऑपरेटरों ने दिन में बाद में 19 लाइनों पर सेवाएं रोकने की योजना बनाई।

मंगलवार को मुख्य रूप से क्यूशू क्षेत्र से आने-जाने वाली 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं। समुद्री परिवहन भी प्रभावित हुआ है, जहां किंकी, शिकोकू, क्यूशू और ओकिनावा क्षेत्रों में 57 कंपनियों के 64 नौवहन मार्गों पर सेवाएं स्थगित कर दी गईं।

रक्षाबंधन पर महिलाओं को तोहफा, राज्य सरकार शुरू करेगी 'मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा'

भोपाल। रक्षाबंधन से पहले मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और भरोसेमंद यात्रा की सौगात देने जा रही है। राज्य सरकार आगामी रक्षाबंधन के अवसर पर 'मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' (मुख्यमंत्री सुगम बस सेवा) शुरू करने की तैयारी में है, जिसका विशेष उद्देश्य महिलाओं को राज्य संचालित बसों में सुरक्षित और आरामदायक यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना है।

इस योजना का उद्देश्य खासतौर पर ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की कमी को दूर करना है, जहां लोगों को अक्सर क्षमता से अधिक भरे निजी वाहनों में सफर करने को मजबूर होना पड़ता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर इस सेवा का प्रतीकात्मक शुभारंभ किया जाएगा, जबकि इसके चरणबद्ध विस्तार के लिए व्यापक रणनीति तैयार की जा रही है।

उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था कमजोर हुई थी। अब गांवों में सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार के बाद प्रभावी बस सेवा को फिर से मजबूत करने का समय आ गया है। यह योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। पहले चरण में अधिक मांग वाले मार्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा और केंद्र सरकार की पीएम ई बस सेवा के तहत बसों का संचालन जुलाई से सबसे पहले इंदौर संभाग में शुरू होगा। इंदौर संभाग में बस संचालन की जिम्मेदारी अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड को सौंपी गई है। प्रारंभिक चरण में इंदौर से तीन श्रेणियों की बसें संचालित होंगी। इनमें मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों को जोड़ने वाले 121 अंतरजिला मार्गों पर 608 बसें, इंदौर शहर और उपनगरीय क्षेत्रों के 28 मार्गों पर बसें तथा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाले 101 अंतरराज्यीय मार्गों पर 276 बसें शामिल हैं। इसके अलावा, पीएम ई-बस सेवा के तहत जुलाई से इंदौर शहर में 150 इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी। राज्य स्तर पर सात संभागीय मुख्यालयों और जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाले 620 मार्गों की पहचान की गई है, जहां 2,432 बसों का संचालन होगा। वहीं पूरी योजना के तहत सातों संभागों में कुल 1,164 मार्गों पर 5,206 बसें चलाने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि यह पहल महिलाओं की आवाजाही को आसान बनाएगी, प्रदेश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करेगी और संगठित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देगी।

अमित शाह भारत-बांग्लादेश सीमा सुरक्षा की समीक्षा के लिए त्रिपुरा का दौरा करेंगे

अगरतला। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 4-5 जून को त्रिपुरा का दौरा करेंगे। इस दौरान वह भारत-बांग्लादेश सीमा पर विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और अन्य एजेंसियों की तैयारियों का जायजा लेंगे।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 4 जून को मेघालय की राजधानी शिलांग में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल (एनईसी) के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करने के बाद, गृह मंत्री शाह गुरुवार शाम को अगरतला पहुंचेंगे।

अधिकारी ने कहा कि त्रिपुरा प्रवास के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारत-बांग्लादेश सीमा से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए बीएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक करेंगे।

बैठक से पहले वे पश्चिम त्रिपुरा जिले में सीमा के कुछ चुनिंदा स्थानों का दौरा कर वहां की मौजूदा स्थिति का स्वयं जायजा लेंगे। बांग्लादेश सीमा के दौरे के दौरान गृह मंत्री शाह कुछ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। पौधरोपण अभियान में हिस्सा लेंगे और एक सैनिक सम्मेलन में शामिल होंगे।

गृह मंत्री एक होटल परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे और उसके भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। इस परियोजना को त्रिपुरा सरकार और एक निजी संस्था मिलकर विकसित करेंगे।

त्रिपुरा सरकार, बीएसएफ और पश्चिम त्रिपुरा जिला प्रशासन, गृह मंत्री के राज्य के दो-दिवसीय दौरे के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहे हैं।

त्रिपुरा भारत का एक राज्य है, जो बांग्लादेश के साथ बहुत लंबी सीमा (856 किलोमीटर) साझा करता है। यह राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इसलिए यहां सुरक्षा की दृष्टि से काफी संवेदनशील स्थिति है। लगभग 21 किलोमीटर के दुर्गम इलाके को छोड़कर, अंतरराष्ट्रीय सीमा के अधिकांश हिस्से पर बाड़ लगा दी गई है, ताकि तस्करी, घुसपैठ, सीमापार अपराधों और अन्य शत्रुतापूर्ण तत्वों की आवाजाही को रोका जा सके।

संक्षिप्त खबर

अमर कॉलोनी में हुई फायरिंग मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली की अमर कॉलोनी फायरिंग केस में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान यश बिधूड़ी और जय कुमार के रूप में हुई।

बताया जा रहा है कि चौथे आरोपी की कार से ही नाबालिग ने पिस्टल निकालकर गोली चलाई थी। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। जानकारी के अनुसार, यश बिधूड़ी और जय को 30 मई की रात दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले, इस घटना में शामिल एक नबालिग आरोपी को बुधवार रात ही पकड़ लिया गया था। वहीं, इस मामले में चौथा आरोपी अभी भी फरार है। बता दें कि दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में एक रेस्टोरेंट में 17 साल के एक छात्र को गोली मारी गई थी। गोली लगने से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। बताया जा रहा है कि उसने कुछ युवकों के एक समूह द्वारा अपनी कुर्सी से सटकर निकलने पर कथित तौर पर आपत्ति जताई थी। घटना को लेकर अधिकारियों ने बताया कि फायरिंग की घटना के संबंध में अमर कॉलोनी पुलिस स्टेशन को पीसीआर कॉल मिली थी। पुलिस ने बताया कि पीड़ित, जिसकी पहचान साहिल के रूप में हुई है, अपने दोस्तों के साथ खाना खाने गया था, तभी लड़कों का एक समूह उनकी मेज के पास से गुजरा। इस दौरान, एक ने कथित तौर पर साहिल की कुर्सी को छू दिया, जिस पर उस किशोर ने आपत्ति जताई और उनसे ठीक से चलने को कहा।

युवती पांच दिन से लापता, दादी की प्रशासन से गुहार-हमारी पोती को खोज लाओ

रामनगर। उत्तराखंड में दयारा बुग्याल ट्रैकिंग के दौरान लापता हुई 24 वर्षीय बबीता पांडे की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। परिवार ने उसकी सुरक्षित वापसी की प्रशासन से गुहार लगाई है।

बबीता पांडे की दादी लक्ष्मी पांडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी मांग है कि हमारी पोती को सकुशल खोज कर लाया जाए। हम लोग काफी परेशान हैं। बबीता वहां घूमने गई थी और अब लापता हो गई है। लापता हुए पांच दिन हो गए हैं।हमारे बच्चे बबीता की तलाश करने गए हैं, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है। लक्ष्मी पांडे ने कहा कि बबीता की तलाश करने के लिए टीम आई है। हमारी पोती को कोई तो ढूंढकर ला दो। वो तो घूमने गई थी। हमको क्या पता था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। बबीता के पिता गोपाल पांडे ने कहा कि पांच दिन हो गए हैं, उसकी कोई खबर नहीं मिली है। हमारा प्रशासन से कहना है कि जल्द से जल्द उसकी तलाश की जाए। बबीता की मां और भाई उसकी तलाश में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि मेरे पैरों में दिक्कत है। मैं चल-फिर नहीं पाता हूं। प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द मेरी लड़की का पता लगाया जाए।

पिता गोपाल ने बताया कि बबीता एमबीए फाइनल ईयर में थी। पढ़ने में तेज थी और जॉब भी करती थी। नैनीताल जिले के रामनगर की रहने वाली 24 वर्षीय बबीता उत्तरकाशी में दयारा बुग्याल ट्रेक मार्ग पर लापता हो गई है। युवती का पांच दिन से कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। जिला प्रशासन, वन विभाग और पुलिस लगातार एजेंसियों के साथ मिलकर सर्च अभियान चला रहा है।

सीबीआई ने उत्तराखंड एलयूसीसी चिट फंड घोटाले में दो मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। उत्तराखंड एलयूसीसी चिट फंड घोटाला मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई से दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी जांच दल के निरंतर और गहन प्रयासों के बाद हुई, जिसमें भारी मात्रा में वित्तीय रिकॉर्ड का विश्लेषण, बैंक लेनदेन की जांच, मौखिक साक्ष्य का संग्रह और देश के विभिन्न राज्यों में व्यापक क्षेत्र जांच शामिल थी।

उत्तराखंड के नैनीताल स्थित हाई कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2025 को पारित आदेश के अनुपालन में सीबीआई, एसीबी, देहरादून ने 26 नवंबर 2025 को मेसर्स लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (एलयूसीसी) के विभिन्न पदाधिकारियों और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

यह मामला उत्तराखंड राज्य के कई जिलों में बड़ी संख्या में निवेशकों को प्रभावित करने वाले एलयूसीसी द्वारा सार्वजनिक जमा की अवैध वसूली, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक साजिश, अनियमित जमा योजनाओं के संचालन और धन के दुरुपयोग आदि के आरोपों से संबंधित है।

अब तक की जांच से उत्तराखंड में जनता के साथ हुए अभूतपूर्व उत्पीड़न का खुलासा हुआ है, जिसमें लगभग एक लाख से अधिक निवेशकों को एलयूसीसी की विभिन्न अनियमित जमा योजनाओं में निवेश करने के लिए लुभाया गया था। इन जमाकर्ताओं द्वारा किए गए कुल निवेश/जमा की राशि लगभग 800 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। जांच से पता चला है कि मुंबई से गिरफ्तार किए गए दोनों व्यक्ति मुख्य आरोपियों में शामिल हैं और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर एलयूसीसी द्वारा संचालित विभिन्न अनियमित जमा योजनाओं के तहत जमाकर्ताओं से एकत्रित धन के संग्रह, प्रबंधन, हेराफेरी और गबन में सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्य लाखों निवेशकों से जुटाए गए धन की हेराफेरी, प्रबंधन और उपयोग से संबंधित एक बड़ी साजिश में उनकी संलिप्तता को दर्शाते हैं। रिमांड प्राप्त करने के बाद दोनों आरोपियों को देहरादून स्थित न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।

सीबीआई ने इससे पहले 12 और 13 मई 2026 को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें उत्तराखंड में एलयूसीसी के 3 वरिष्ठ सहकारी प्रवर्तक शामिल थे, जो उत्तराखंड में जनता से सक्रिय रूप से जमा राशि एकत्रित कर रहे थे और नकद जमा शाखाओं का प्रबंधन कर रहे थे।

निजी स्कूलों को आदेश, 5 जून तक सार्वजनिक करें स्वीकृत ट्यूशन फीस का विवरण

चेन्नई। स्कूल फीस वसूली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु के निजी स्कूल निदेशालय ने राज्य के सभी निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे 5 जून तक अपनी स्वीकृत ट्यूशन फीस की जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड और आधिकारिक वेबसाइट पर साफ तौर पर प्रदर्शित करें।

यह निर्देश तमिलनाडु में चल रहे नर्सरी, प्राइमरी, मैट्रिकुलेशन, सीबीएसई और अन्य प्राइवेट बोर्ड स्कूलों पर लागू होता है।

यह आदेश तमिलनाडु सूचना आयोग के हालिया फैसले के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि स्कूल का फीस ढांचा भी अपनी तरह की एक सार्वजनिक जानकारी है और इसे अभिभावकों और आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

सूचना आयोग ने 29 मई को जारी अपने आदेश में प्राइवेट स्कूल निदेशालय को निर्देश दिया कि वह इस आदेश का पालन सुनिश्चित करे और 15 जून तक एक रिपोर्ट जमा करे।

हिमाचल प्रदेश : सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डिजिटल जनगणना के तहत दी पूरी जानकारी

शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डिजिटल जनगणना की दिशा में मंगलवार को महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। उन्होंने डिजिटल जनगणना के तहत अपनी सारी जानकारी दी। इस खास मौके पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, विधायक कमलेश ठाकुर तथा मुख्यमंत्री के सचिव आशीष सिंहमार भी उपस्थित रहे।

इस दौरान मुख्यमंत्री को जनगणना संचालन निदेशक दीप शिखा शर्मा और विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने जनगणना के संबंध में पूरी जानकारी दी। साथ ही, यह भी बताया कि जनगणना के संबंध में इस तरह की तैयारी की गई है, ताकि आम लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो।

वहीं, मुख्यमंत्री ने आगामी 15 जून तक लोगों से डिजिटल जनगणना के तहत सभी जानकारी देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि जब आप लोग अपने बारे में जानकारी नहीं देंगे, तब तक प्रदेश की असल तस्वीर सामने नहीं आएगी और अगर असल तस्वीर सामने नहीं आएगी, तो हम विकास का खाका तैयार नहीं कर पाएंगे। हम लोगों के लिए जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर आप चाहते हैं कि हम प्रदेश के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं शुरू करें, तो इसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि आप लोग इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में जनगणना-2027 का आयोजन दो चरणों में किया जाएगा। पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई 2026 तक चलेगा, जिसमें गृह सूचीकरण और आवास जनगणना की जाएगी।

राजस्थान में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू भाजपा और कांग्रेस के अभी तक उम्मीदवार घोषित

जयपुर। राजस्थान में राज्यसभा चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया सोमवार को शुरू हो गई, लेकिन भाजपा और कांग्रेस ने अभी तक राज्य से खाली हो रही तीन सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है।

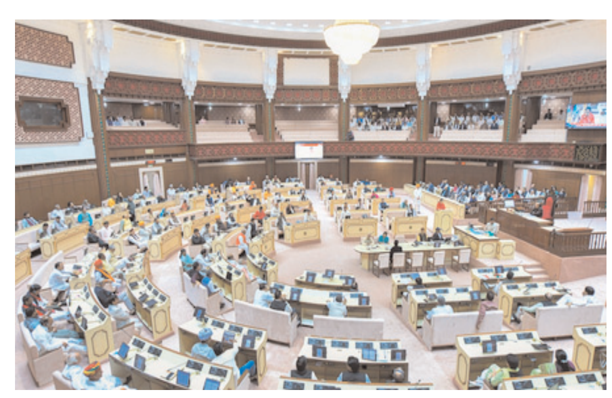

नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया। उम्मीदवार 8 जून तक अपने नामांकन जमा कर सकते हैं, जबकि कागजों की जांच 9 जून को की जाएगी। वहीं, नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 11 जून है और मतदान 18 जून को होगा।

विधानसभा के प्रधान सचिव भरत भूषण शर्मा को इन चुनावों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है।

नामांकन पत्र राजस्थान विधानसभा के कमरा नंबर 106 में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच उम्मीदवार या उनके किसी एक प्रस्तावक द्वारा दाखिल किए जा सकते हैं।

इस चुनाव का राजनीतिक महत्व बढ़ गया है, क्योंकि राजस्थान से राज्यसभा के तीन सदस्यों, राजेंद्र गहलोत, रवनीत सिंह बिट्टू और नीरज डांगी, का कार्यकाल 20 जून को समाप्त होने वाला है। इनमें से दो सांसद भाजपा के हैं, जबकि डांगी कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। नामांकन प्रक्रिया जारी होने के साथ ही, भाजपा ने अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप देने के लिए विचार-विमर्श तेज कर दिया है। सोमवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष ने उन राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के साथ चर्चा की, जहां राज्यसभा चुनाव होने हैं।

लोकल से ग्लोबल की सशक्त उड़ान, गुजरात सरकार की हस्तकला सेतु योजना कारिगरों के लिए वरदान

गांधीनगर। गुजरात की समृद्ध हस्तकला परंपरा की सदियों से देश-विदेश में अपनी विशिष्ट पहचान है। बदलते आर्थिक परिप्रेक्ष्य तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धा के समय में इन कारीगरों को सशक्त बनाना समय की बड़ी आवश्यकता बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 'विकास भी, विरासत भी', 'आत्मनिर्भर भारत', 'वोकल फॉर लोकल' जैसे मंत्रों द्वारा परंपरागत कला विरासत को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने का विजन दिया है और गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल इस विजन को भली-भांति आगे बढ़ा रहे हैं।

प्रधानमंत्री के इसी विजन तथा परंपरागत कला विरासत की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में गुजरात सरकार ने वर्ष 2020 में 'हस्तकला सेतु योजना' (एचएसवाई) शुरू की थी, जो आज कला-कारीगरों के लिए मजबूत आर्थिक प्रोत्साहन का सेतु सिद्ध हुई है।

दिल्ली के एलजी ने रिज मैनेजमेंट बोर्ड के पुनर्गठन को दी मंजूरी, पर्यावरण संरक्षण को मिलेगी मजबूती

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उपराज्यपाल टीएस संधू ने दिल्ली रिज मैनेजमेंट बोर्ड (डीआरएमबी) के पुनर्गठन को मंजूरी दी। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के टी.एन. गोदावरमन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ मामले में दिए गए निर्देशों और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत लिया गया है।

दिल्ली का रिज क्षेत्र राजधानी के 'ग्रीन लंग्स' यानी हरे फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। यह क्षेत्र शहर के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने, जैव विविधता की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नए ढांचे का उद्देश्य रिज क्षेत्र के संरक्षण, निगरानी और प्रबंधन को अधिक प्रभावी और समन्वित बनाना है।

पुनर्गठित दिल्ली रिज मैनेजमेंट बोर्ड की अध्यक्षता दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव करेंगे, जबकि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के उपाध्यक्ष इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी बोर्ड में शामिल रहेंगे। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के आयुक्त, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के अध्यक्ष, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के महानिदेशक, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, राजस्व विभाग के प्रधान सचिव और पर्यावरण एवं वन विभाग के प्रधान सचिव भी बोर्ड का हिस्सा होंगे। जमीनी स्तर पर कार्यों की निगरानी के लिए दिल्ली सरकार के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) का प्रतिनिधित्व करने के लिए चंद्र प्रकाश गोयल को विशेषज्ञ सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

विश्व केसरी

एआई बदल रहा है विज्ञापन उद्योग की तस्वीर, भारत बन सकता है वैश्विक एडटेक हबः रिपोर्ट

नई दिल्ली। मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) वैश्विक विज्ञापन उद्योग के हर स्तर को तेजी से बदल रहा है और भारत को दुनिया की अग्रणी एडटेक (विज्ञापन प्रौद्योगिकी) कंपनियों का केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ा रहा है।

कंसल्टिंग फर्म रेडसीर की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 27 लाख इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी छात्रों का नामांकन होता है। इसके अलावा देश में 2 करोड़ से 2.4 करोड़ गिटहब डेवलपर्स और लगभग 1,900 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) मौजूद हैं, जो 65 से 75 अरब डॉलर का निर्यात राजस्व पैदा कर रहे हैं। यह मजबूत आधार एआई-आधारित उत्पाद विकास को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभा रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक विज्ञापन बाजार 1 ट्रिलियन डॉलर के स्तर को पार कर चुका है। ऐसे में एआई विज्ञापन क्षेत्र को अधिक स्वचालित, डेटा-आधारित और परिणाम-केंद्रित मॉडल की ओर तेजी से ले जा रहा है, जिसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है।

रिपोर्ट के मुताबिक, एआई मीडिया खरीद, क्रिएटिव कंटेंट निर्माण, प्रदर्शन मापन, ई-कॉमर्स और ग्राहकों को लक्षित करने जैसी विज्ञापन उद्योग की लगभग हर प्रमुख प्रक्रिया को बदलना शुरू कर चुका है।

फर्म का अनुमान है कि भारत का डिजिटल विज्ञापन बाजार वर्ष 2025 में लगभग 21 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 33 अरब डॉलर से 42 अरब डॉलर के बीच पहुंच सकता है। इससे एआई आधारित विज्ञापन नवाचार को देश में और अधिक गति मिलेगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक विज्ञापन खर्च में डिजिटल माध्यमों की हिस्सेदारी अब लगभग 75 से 80 प्रतिशत हो चुकी है। वहीं, डिजिटल विज्ञापनों का 80 से 85 प्रतिशत हिस्सा पहले से ही प्रोग्रामेटिक तकनीक के जरिए संचालित हो रहा है।

रेडसीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स के एसोसिएट पार्टनर मुकेश कुमार ने कहा, 'इस बदलाव को जो बात अलग बनाती है, वह यह है कि एआई विज्ञापन उद्योग में केवल एक नई परत नहीं जोड़ रहा, बल्कि पूरे सिस्टम को एक साथ नए सिरे से परिभाषित कर रहा है।'

उन्होंने कहा कि मशीन लर्निंग-आधारित बोली प्रणाली, आइडेंटिटी ग्राफ, ट्रांसफॉर्मर-आधारित रिकमेंडेशन इंजन और एजेंटिक विज्ञापन ढांचे जैसी तकनीकों के विकास के लिए जिस इंजीनियरिंग क्षमता की जरूरत है, वह भारत ने पिछले तीन दशकों में तैयार की है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मूल की एडटेक कंपनियां अब केवल तकनीकी सेवाएं देने वाली कंपनियां नहीं रह गई हैं, बल्कि वे वैश्विक उत्पाद कंपनियों के रूप में उभर रही हैं। साथ ही वे पारंपरिक सेवा कारोबार के बजाय सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म-आधारित अधिक लाभकारी मॉडल से कमाई कर रही हैं।

खतरे में हैं 75 प्रतिशत से ज्यादा रीफ, ईएसए ने स्पेस से दिखाई खूबसूरत 'कोरल रीफ' की झलक

नई दिल्ली। समुद्री जीवन के रक्षक और आधार कोरल रिफ्स इकोसिस्टम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इनके महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल (1 जून को) विश्व कोरल रीफ दिवस भी मनाया जाता है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी (ईएसए) और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) के एस्ट्रोनॉट्स ने स्पेस से ली खास तस्वीरें शेयर की हैं।

इसके साथ ही पृथ्वी की कक्षा से ली गई कोरल रीफ की आश्चर्यजनक तस्वीरों के जरिए उन्होंने इन नाजुक इकोसिस्टम को बचाने की अपील भी की है। कोरल रीफ समुद्र की सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक हैं। ऊपर से देखने पर ये फिरोजी, नीले और हरे रंगों में चमकते नजर आते हैं।

एस्ट्रोनॉट्स ने बताया कि ये रीफ न सिर्फ बेहद सुंदर हैं बल्कि पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी हैं। ये समुद्र तटों को तेज लहरों और कटाव से बचाते हैं, हजारों समुद्री प्रजातियों को आश्रय और भोजन देते हैं। सदियों में परत दर परत बनने वाले ये रीफ पूरे इकोसिस्टम का आधार होते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि इनमें से 75 प्रतिशत से ज्यादा रीफ पहले ही खतरे में हैं। मानवीय गतिविधियां, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण ये तेजी से नष्ट हो रहे हैं।

ईएस ने 9 कोरल रीफ सिस्टम की तस्वीरें साझा की हैं। इनमें शामिल हैं- फ्रेंच पोलिनेशिया का टुपाई और मौपिटी, ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, मॉरिशस का सेंट-ब्रैंडन, बेलीज रीफ, किरिबाती का तरावा, टोंगा का टोंगाटापु, मालदीव का एरी एटोल और फिजी का विटी लेवु। ये तस्वीरें स्पेस से देखने पर और भी आकर्षक लगती हैं।

एस्ट्रोनॉट सोफी ने बताया कि स्पेस से साफ दिखता है कि समुद्री और तटीय जीवन के लिए ये इकोसिस्टम कितने जरूरी हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर हमें जीवन को फलते-फूलते रखना है तो पृथ्वी के सभी इकोसिस्टम को बचाना होगा।

इसके लिए छोटे-छोटे कदम जैसे प्लास्टिक का कम उपयोग, समुद्री प्रदूषण रोकना और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रयास इन रंगीन रीफ्स को बचाने में मदद कर सकते हैं। कोरल रीफ न सिर्फ समुद्री जीवन का आधार हैं बल्कि लाखों लोगों की आजीविका भी हैं जो मछली पकड़ने और पर्यटन से जुड़े हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते इन्हें बचाने के ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियां इनकी सुंदरता कभी नहीं देख पाएंगे।

कब्ज और पीठ दर्द से छुटकारा दिलाएगा धनुरासन, बढ़ती उम्र की समस्याओं में कारगर

नई दिल्ली। आज की अनियमित जीवनशैली बढ़ती उम्र के लोगों की शारीरिक व मानसिक समस्याओं को बढ़ाती दिख रही है। उम्र बढ़ने के साथ बार-बार कब्ज, पाचन संबंधी समस्याएं और लगातार पीठ दर्द आम हो जाते हैं, जो समग्र स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। इसी कड़ी में आयुष मंत्रालय ने धनुरासन यानी बो पोज को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सिफारिश की है।

विश्व योग दिवस 2026 (21 जून) में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में भारत सरकार का आयुष मंत्रालय योग को दैनिक जीवन में शामिल करने की सलाह देते हुए नागरिकों को लगातार नए-नए योगासनों के बारे में जानकारी देते हुए स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कर रहा है।

मंत्रालय के अनुसार, उम्र बढ़ने के साथ बार-बार कब्ज, पाचन संबंधी समस्याएं और लगातार पीठ दर्द आम हो गए हैं,

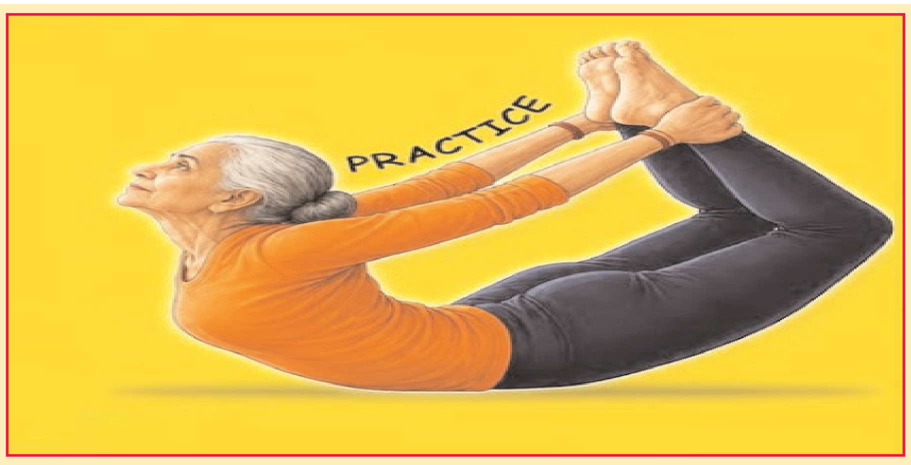

जो आराम, चलने-फिरने और स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। ऐसे में धनुरासन के अभ्यास से कई समस्याओं को हमेशा के लिए अलविदा कहा जा सकता है।

धनुरासन पेट के हिस्से को अच्छी तरह स्ट्रेच करता है, पाचन अंगों को उत्तेजित करता है, पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और शरीर की लचक बढ़ाता है। धनुरासन के अभ्यास से पेट की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं जिससे कब्ज की समस्या में राहत मिलती है और पाचन क्रिया सुधरती है।

साथ ही यह रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और पीठ दर्द को कम करने में काफी मददगार साबित होता है।

इसके रोजाना अभ्यास से मांसपेशियों और जोड़ों का लचीलापन बढ़ता है, जिससे उम्र बढ़ने के बावजूद शरीर सक्रिय और चुस्त रहता है।

धनुरासन अभ्यास के लिए सबसे पहले लेटकर दोनों घुटनों को मोड़ें, एड़ियों को पीछे की ओर ले जाएं और हाथों से पैरों की एड़ियों को पकड़ें। सांस भरते हुए छाती और जांघों को ऊपर उठाएं ताकि शरीर धनुष जैसा आकार ले ले। कुछ सेकंड इसी स्थिति में रहें और फिर धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में आएं। शुरुआती अभ्यास स्तर वाले लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए और किसी योग विशेषज्ञ की देखरेख में शुरू करना बेहतर है।

गर्दन-कंधों की जकड़न दूर करेंगे ये 4 योग मूवमेंट्स, बढ़ेगी ऊर्जा और घटेगा तनाव

नई दिल्ली। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय योग को दिनचर्या में शामिल करने की सलाह देता है। मंत्रालय के अनुसार, आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में हमारा दिमाग लगातार सोचने से कहीं ज्यादा जानकारी प्रोसेस कर रहा है, जिसका असर शरीर पर तनाव, मांसपेशियों में अकड़न और थकान के रूप में सामने आता है।

मंत्रालय बताता है कि स्ट्रेस गर्दन, कंधों और पीठ में जमा न हो इसके लिए पहले कुछ मिनट रुककर गहरी सांस लेनी चाहिए और खुद को रीसेट करना चाहिए। मंत्रालय ने हल्के-फुल्के योग मूवमेंट्स को अपनाने की सिफारिश की है जो शारीरिक तनाव कम करने, शरीर की मोबिलिटी बढ़ाने और ध्यान को वर्तमान पल में लाने में कारगर होते हैं।

आयुष मंत्रालय द्वारा सुझाए गए आसान मूवमेंट्स में ट्रंक ट्विस्टिंग, नी मूवमेंट, शोल्डर मूवमेंट और नेक मूवमेंट शामिल हैं। ये सभी मूवमेंट्स बिना किसी उपकरण के कहीं भी आसानी से किए जा सकते हैं। इन आसान अभ्यासों से न सिर्फ शारीरिक थकान कम होती है बल्कि मन भी शांत रहता है। इन आसान मूवमेंट्स को अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करें। नियमित अभ्यास से ऊर्जा बढ़ती है, तनाव कम होता है और स्वास्थ्य बेहतर होता है।

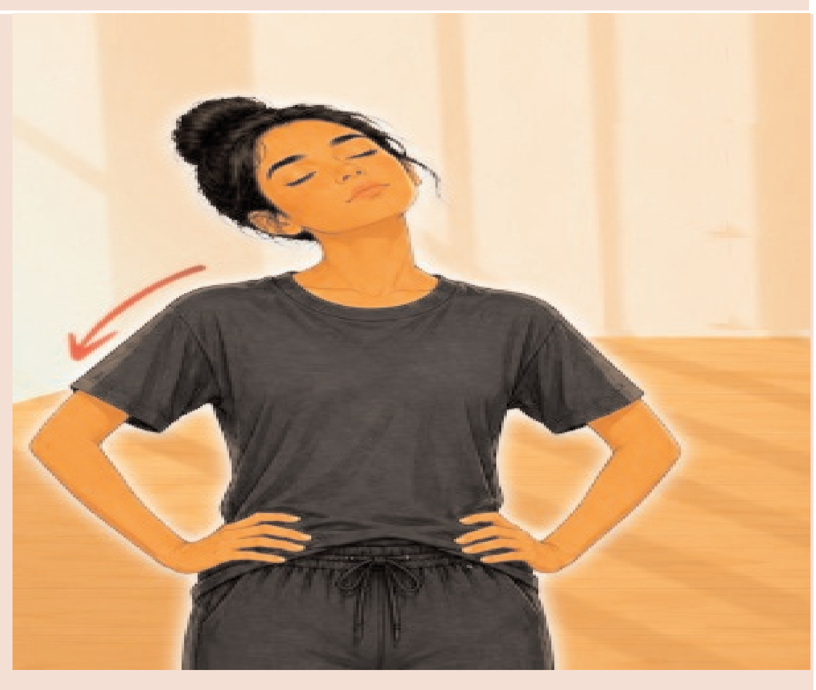

ट्रंक ट्विस्टिंग :- कमर को दाएं-बाएं घुमाने वाला यह मूवमेंट पीठ और कमर की अकड़न को दूर करता है। इससे रीढ़ की हड्डी लचीली होती है और पाचन भी बेहतर होता है।

नी मूवमेंट :- घुटनों को हल्के-हल्के घुमाने या ऊपर-नीचे करने से पैरों और घुटनों की जकड़न कम होती है। लंबे समय तक बैठने वाले लोगों के लिए यह बहुत उपयोगी है।

शोल्डर मूवमेंट :- कंधों को आगे-पीछे और घुमाकर करने वाला यह अभ्यास कंधों और गर्दन के ऊपरी हिस्से के तनाव को तुरंत कम करता है। नेक मूवमेंट :- गर्दन को धीरे-धीरे दाएं-बाएं, ऊपर-नीचे और घुमाकर करने से स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताने से होने वाली नेक पेन में राहत मिलती है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 की थीम 'स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग' घोषित, दीर्घायु और खुशहाली का देगा संदेश

नई दिल्ली। 21 जून 2026 को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) की थीम 'स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग' निर्धारित की गई है। यह थीम भारत की उस प्राचीन और समग्र जीवनशैली को दर्शाती है, जो स्वस्थ, सक्रिय और गरिमापूर्ण जीवन के साथ दीर्घायु को बढ़ावा देती है। योग को आज विश्व भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रभावी साधन के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।

आयुष मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव ने कहा कि बढ़ती जीवन प्रत्याशा के दौर में स्वस्थ और सम्मानजनक ढंग से बुढ़ापा बिताना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन परंपरा में ऋषि-मुनियों और योगियों ने योग एवं आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार, योग व्यक्ति को स्वस्थ एवं संतुलित जीवन जीने की कला सिखाता है।

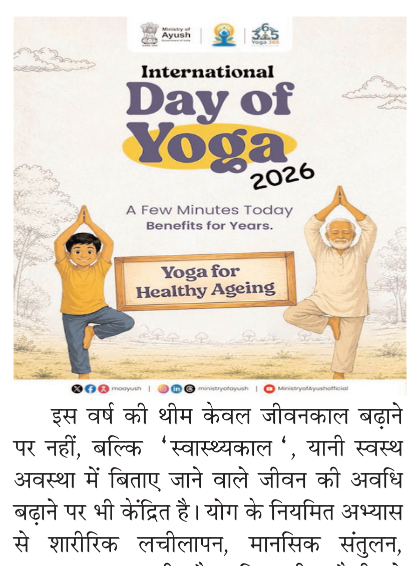

इस वर्ष की थीम केवल जीवनकाल बढ़ाने पर नहीं, बल्कि 'स्वास्थ्यकाल', यानी स्वस्थ अवस्था में बिताए जाने वाले जीवन की अवधि बढ़ाने पर भी केंद्रित है। योग के नियमित अभ्यास से शारीरिक लचीलापन, मानसिक संतुलन, भावनात्मक मजबूती और सक्रिय जीवनशैली को बढ़ावा मिलता है, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को अधिक सहज बनाया जा सकता है।

योग और स्वस्थ बुढ़ापे के संबंध में वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक शोधों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2014 में इस विषय पर 183 शोध-पत्र प्रकाशित हुए थे, जबकि 2025 तक यह संख्या बढ़कर 1,207 तक पहुंच गई। यह वृद्धि उम्र से जुड़ी शारीरिक और मानसिक चुनौतियों के समाधान में योग की उपयोगिता को लेकर बढ़ती वैज्ञानिक रुचि को दर्शाती है। आयुष मंत्रालय योग को वर्षभर अपनाने योग्य जीवनशैली के रूप में बढ़ावा दे रहा है। इसके तहत 'योग 365 ', 'योग समावेश' तथा गैर-संक्रामक रोगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष योग प्रोटोकॉल जैसी पहलें संचालित की जा रही हैं। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य बुजुर्गों में संतुलन, गतिशीलता, श्वसन क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। आयुष मंत्रालय ने योग को सालभर चलने वाली वेलनेस पद्धति के रूप में बढ़ावा देने और निवारक स्वास्थ्य सेवा में इसकी भूमिका को मजबूत करने के लिए कई पहलें की हैं।

देश में इबोला का कोई मामला नहीं, प्रभावित देशों से लौटे यात्रियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने इबोला वायरस बीमारी को लेकर एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 2 जून 2026 तक भारत में इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियात के तौर पर लोगों को सतर्क रहने और निर्धारित स्वास्थ्य दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी संदेश में कहा कि यदि कोई व्यक्ति पिछले 21 दिनों के भीतर इबोला प्रभावित किसी देश की यात्रा करके आया है या वहां से होकर गुजरा है

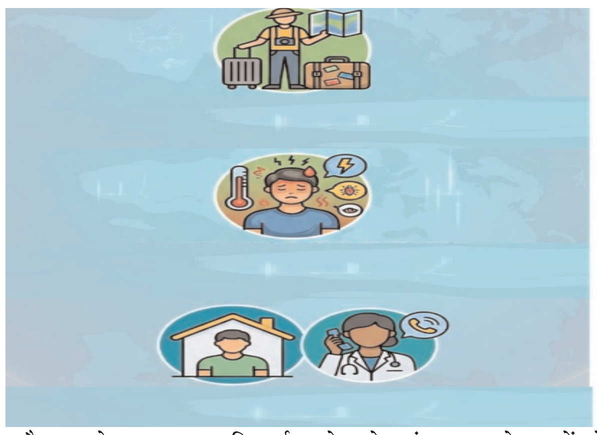

और उसे बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी, दस्त या बिना किसी स्पष्ट कारण के रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो उसे तुरंत खुद को दूसरों से अलग कर लेना चाहिए। साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों को इसकी जानकारी देनी चाहिए, ताकि समय रहते आवश्यक जांच और उपचार की व्यवस्था की जा सके।

मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध लक्षण को नजरअंदाज न करें। शुरुआती स्तर पर बीमारी की जानकारी देने से मरीज का इलाज जल्दी शुरू किया जा सकता है और संक्रमण के संभावित फैलाव को भी रोका जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, समय पर रिपोर्टिंग कई लोगों की जान बचाने में मददगार साबित हो सकती है। लोगों की सहायता के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध हेल्पलाइन सेवा का भी उल्लेख किया है।

सेहत और स्वाद का शानदार मेल 'लौकी कलाकंद', घर पर बनाएं गर्मियों की खास मिठाई

नई दिल्ली। गर्मियों के मौसम में लोग ऐसे खानपान या मिठाइयों की तलाश करते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ सेहतमंद भी हो। ऐसी ही एक मिठाई का नाम है 'लौकी कलाकंद', जो न केवल मिठास से भरपूर बल्कि सेहतमंद भी है।

आमतौर पर लौकी का इस्तेमाल सब्जी बनाने में किया जाता है, लेकिन इससे तैयार होने वाला कलाकंद मिठाई प्रेमियों के लिए एक खास विकल्प है। यह मिठाई कम कैलोरी वाली होने के साथ-साथ कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है। यही वजह है कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग भी इसे पसंद करते हैं।

लौकी में पानी की मात्रा काफी अधिक होती है, जिससे शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद मिलती है। इसमें फाइबर, पोटैशियम, कैल्शियम और कई जरूरी विटामिन पाए जाते हैं। यही कारण है कि यह पाचन तंत्र को बेहतर बनाने, पेट को ठंडक देने और शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में सहायक मानी जाती है। फाइबर, विटामिन ए, पोटैशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।

ऐसे में लौकी कलाकंद पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होती है। फाइबर की वजह से कब्ज, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। कम कैलोरी होने के कारण वजन नियंत्रण में मदद करती है। पोटैशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है और दिल को स्वस्थ बनाता है। साथ ही यह त्वचा को चमकदार बनाने और शरीर से विषाक्त तत्व निकालने में भी सहायक है। गर्मियों में यह एनर्जी बनाए रखने में कारगर साबित होती है।

लौकी कलाकंद बनाना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले ताजी लौकी को अच्छे से धोकर छील लें, बीज निकाल दें और कद्दूकस कर लें। कढ़ाई में दो बड़े चम्मच घी गरम करें, उसमें कद्दूकस की हुई लौकी डालकर मध्यम आंच पर लगभग 10-15 मिनट तक भून लें। फिर स्वाद के अनुसार चीनी मिलाकर पानी सूखने तक पकाएं।

विमेंस नेशंस कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, सलीमा टेटे संभालेंगी कमान

नई दिल्ली। हॉकी इंडिया ने एफआईएच हॉकी विमेंस नेशंस कप के लिए विमेंस टीम का ऐलान कर दिया है। यह टूर्नामेंट 15 से 21 जून तक न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेला जाना है।

सलीमा टेटे टूर्नामेंट के लिए टीम की कैप्टन बनी रहेंगी। सविता और बीचू देवी खारीबाम भरोसेमंद, अनुभवी गोलकीपर के तौर पर काम करेंगी। डिफेंस में सुशीला चानू पुखरामबम, इशिका चौधरी, निक्की प्रधान और ज्योति बैकलाइन में अपना इंटरनेशनल अनुभव लेकर आएंगी। उनके साथ लालथंतलुआंगी और शिल्पी डबास भी होंगी, जिन्हें हाल ही में ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान पहली बार सीनियर टीम में शामिल किया गया था।

सलीमा मिडफील्ड की अगुवाई करेंगी, जिन्हें नेहा, सुनीता टोप्पो और साक्षी राणा का सपोर्ट मिलेगा। सलीमा को दीपिका सोरेंग का भी साथ मिलेगा, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में फ्रेंडली सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था। नवनीत कौर अटैक को लीड करेंगी और उम्मीद है कि वह हाल के इंटरनेशनल मुकाबलों में अपने शानदार गोल करने के सिलसिले को बनाए रखेंगी। नवनीत को दीपिका, रुतुजा दादासो पिसल, अन्नू और इशिका का साथ मिलेगा। इसके साथ ही अनुभवी अटैकिंग मिडफील्डर लालरेमसियामी और सोनम भी टीम के अटैक को मजबूती प्रदान करेंगी।

भारत की महिलाएं ऑस्ट्रेलिया के सफल दौरे के बाद नेशंस कप के लिए तैयार हैं, जहां उन्होंने एफआईएच हॉकी विमेंस नेशंस कप न्यूजीलैंड 2025-26 से पहले पर्थ में चार मुकाबलों की फ्रेंडली सीरीज में हिस्सा लिया था। इस सीरीज से टीम को जरूरी अनुभव मिला और चीफ कोच शोर्ड मारिन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर निगाहें भी रख सके। भारत ने चार मुकाबलों में मेजबान टीम के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला।

भारत को टूर्नामेंट के पूल ए में जापान, अमेरिका और उरुग्वे के साथ रखा गया है, जबकि पूल बी में मेजबान न्यूजीलैंड, चिली, कोरिया और फ्रांस शामिल हैं। चीफ कोच मारिन ने आने वाले एक जरूरी फेज के लिए टीम की तैयारियों के महत्व पर जोर दिया, जिसकी शुरुआत एफआईएच हॉकी विमेंस नेशंस कप 2025-26 से होगी। इसके बाद एफआईएच वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स में भी टीम को हिस्सा लेना है।

मारिन ने कहा, 'नेशंस कप हमारे लिए एक जरूरी टूर्नामेंट है। हम वहां जाकर अपने लिए एक मानक सेट करने के लिए उद्देश्य के साथ खेलना चाहते हैं, जिसे हम आगे बढ़ा सकें। हमने अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया टूर में उन पहलुओं पर काम किया है, जिससे हमें एक टीम के तौर पर अच्छी तैयारी मिली। अब अगला कदम उठाने और पूरे टूर्नामेंट में लगातार उस लेवल को दिखाने की बात है। टीम प्रेरित है और चैलेंज के लिए तैयार है।'

स्क्वॉड सिलेक्शन पर अपने विचार शेयर करते हुए उन्होंने कहा, 'हमने एक ऐसा स्क्वॉड चुना है जिसमें अनुभव और जोश का सही संतुलन है। सविता, सुशीला, निक्की और नवनीत जैसी खिलाड़ी पहले भी बड़े टूर्नामेंट्स में खेल चुकी हैं और जानती हैं कि दबाव में प्रदर्शन करने के लिए क्या करना होता है। इसके साथ ही, हमारे पास ऐसी खिलाड़ी हैं जो अभी भी उच्च स्तर पर अपने खेल को विकसित कर रही हैं और इस तरह का टूर्नामेंट वह माहौल देता है जहां उनका विकास होता है।'

भारतीय टीम ने नेशंस कप में अपने अभियान का आगाज 15 जून को अमेरिका के खिलाफ करेगी। इसके बाद टीम की अगली भिड़ंत जापान से 16 जून को होगी। 18 जून को टीम का सामना उरुग्वे से होगा। टूर्नामेंट का सेमीफाइनल मुकाबला 20 और फाइनल मैच 21 जून को खेला जाना है।

एफआईएच हॉकी विमेंस नेशंस कप 2025-26 के लिए भारत की 20 सदस्यीय टीम

गोलकीपर: सविता, बीचू देवी खारीबाम

डिफेंडर: सुशीला चानू पुखरामबम, इशिका चौधरी, लालथंतलुआंगी, शिल्पी डबास, ज्योति, निक्की प्रधान

मिडफील्डर: सलीमा टेटे (कप्तान), नेहा, सुनीता टोप्पो, साक्षी राणा, दीपिका सोरेंग, सोनम, लालरेमसियामी

फॉरवर्ड: नवनीत कौर, दीपिका, रुतुजा दादासो पिसल, इशिका, अन्नू।

तृप्ति मुर्गंडेः दक्षिण एशियाई खेलों में जीते 5 गोल्ड, कॉमनवेल्थ गेम्स में भी देश को दिलाया ब्रॉन्ज मेडल

नई दिल्ली । तृप्ति मुर्गंडे की गिनती भारत की बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ियों में की जाती है। उन्होंने उस दौर में इस खेल में उल्लेखनीय सफलताएं हासिल कीं, जब खिलाड़ियों को आज जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं। तीन बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में हार का सामना करने के बावजूद तृप्ति ने हिम्मत नहीं हारी और चौथे प्रयास में राष्ट्रीय चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों की टीम स्पर्धा में भारत को कांस्य पदक दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई।

तृप्ति मुर्गंडे का जन्म 3 जून 1982 को पुणे में हुआ था। उन्हें बचपन से ही बैडमिंटन में गहरी रुचि थी। महज नौ वर्ष की उम्र में उन्होंने पुणे स्थित एक अकादमी में दाखिला लिया और वसंत गोरे के मार्गदर्शन में खेल की बारीकियां सीखीं।

बैडमिंटन के प्रति उनके जुनून का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कम उम्र में ही वह अपने खेल को निखारने के लिए बेंगलुरु पहुंच गईं। वहां उन्होंने प्रकाश पादुकोण की अकादमी में प्रशिक्षण लिया। कड़ी मेहनत और लगातार अभ्यास का नतीजा यह रहा कि वह जल्द ही जूनियर स्तर पर राष्ट्रीय चैंपियन बन गईं।

हालांकि, तृप्ति को नेशनल चैंपियन बनने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। तृप्ति का नेशनल चैंपियन बनने का सपना तीन बार बेहद करीब आकर टूटा। वह फाइनल तक पहुंची, लेकिन तीनों बार उन्हें खिताबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। आखिरकार वर्ष 2009 में उनका इंतजार समाप्त हुआ और वह महिला एकल राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियन बनीं।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी तृप्ति ने अपनी अलग पहचान बनाई। दक्षिण एशियाई खेलों में उनका प्रदर्शन शानदार रहा, जहां उन्होंने कुल पांच स्वर्ण पदक जीते। इनमें 2004 और 2006 की एकल स्पर्धाओं के स्वर्ण पदक भी शामिल हैं।

वर्ष 2006 में मेलबर्न में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में तृप्ति भारतीय टीम का हिस्सा रहीं, जिसने टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अपने करियर के दौरान उन्होंने छह अंतरराष्ट्रीय खिताब भी अपने नाम किए। बैडमिंटन में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2020 में ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

संन्यास के बाद तृप्ति भारतीय राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम की चयनकर्ता भी रहीं।

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप से पहले 'नंबर-1' गेंदबाज बनीं लिंसी स्मिथ

दुबई। इंग्लैंड की लेफ्ट-आर्म स्पिनर लिंसी स्मिथ विमेंस टी20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले अपने करियर में पहली बार आईसीसी विमेंस टी20 अंतरराष्ट्रीय बॉलिंग रैंकिंग के शिखर पर पहुंच गई हैं।

31 वर्षीय खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान की सादिया इकबाल को पछाड़कर 'नंबर-1' स्थान हासिल किया है। स्मिथ को यह ताज 'व्हाइट फर्न्स' (न्यूजीलैंड) के खिलाफ 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' के तौर पर बेहतरीन प्रदर्शन और ब्रिस्टल में भारत के विरुद्ध इंग्लैंड की हालिया जीत में एक और प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद मिला है।

लिंसी स्मिथ ने साल 2018 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था, जिसके बाद लंबे वक्त तक नेशनल टीम से बाहर बैठना पड़ा। पिछले साल के आखिर में ही इंग्लैंड की टी20 टीम में एक निमयित सदस्य के तौर पर अपनी जगह पक्की करने के बाद, अब वह इस वर्ल्ड कप में इस फॉर्मेट की सबसे ऊंची रैंक वाली गेंदबाज के तौर पर उतर रही हैं।

इंग्लैंड के शानदार प्रदर्शन की झलक गेंदबाजी रैंकिंग में दूसरी जगहों पर भी देखने को मिली है। तेज गेंदबाज लॉरेन बेल एक स्थान ऊपर चढ़कर तीसरे नंबर पर पहुंच गई हैं। वहीं, स्टैंड-इन कप्तान चार्ली डीन दो स्थान ऊपर चढ़कर पांचवें नंबर पर आ गईं।

भारत की उभरती हुई स्पिनर श्री चरणी इस ताजा रैंकिंग में सबसे ज्यादा फायदा पाने वाली खिलाड़ियों में से एक रहीं। इंग्लैंड के खिलाफ 3 विकेट लेने के बाद चरणी 7 पायदान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर पहुंच गई हैं। टॉप 10 गेंदबाजों के बीच सिर्फ 39 रेटिंग प्वाइंट्स का अंतर है। ऐसे में वर्ल्ड कप से पहले 'नंबर 1' बनने की दौड़ रोमांचक बनी हुई है।

बल्लेबाजी रैंकिंग में, ऑस्ट्रेलियाई ओपनर जॉर्जिया वोल ने टॉप स्थान बरकरार रखा है। इस बीच टॉप 10 से बाहर मौजूद कई खिलाड़ियों ने भी रैंकिंग में काफी सुधार किया।भारत की जेमिमा रोड्रिग्स बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 11वें स्थान पर पहुंच गई हैं। आयरलैंड की ऑलराउंडर ओर्ला प्रेंडरगास्ट 10 स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 16वें स्थान पर पहुंच गईं।

फ्रेंच ओपन 2026: माटेओ अर्नाल्डी ने बनाई क्वार्टर फाइनल में जगह, कड़े मुकाबले में टियाफो को दी मात

पेरिस। माटेओ अर्नाल्डी ने फ्रेंच ओपन 2026 के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। पांच सेट तक चले मुकाबले में अर्नाल्डी ने फ्रांसिस टियाफो को हराकर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल किया।

25 साल वर्षीय खिलाड़ी ने मंगलवार को 19वें नंबर के अमेरिकी खिलाड़ी को 7-6(5), 6-7(5), 3-6, 7-6(3), 6-4 से हराया। यह रोमांचक मुकाबला पांच घंटे 26 मिनट तक चला। इटली के खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में कुल 17 घंटे 42 मिनट का समय लगाया है। यह 1991 से अब तक के रिकॉर्ड के अनुसार किसी भी ग्रैंड स्लैम में क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने का सबसे लंबा समय है। यह पिछले रिकॉर्ड से लगभग 1 घंटा 58 मिनट ज्यादा है।

दोनों खिलाड़ियों ने पहले सेट में बराबरी की, लेकिन इसके बाद अमेरिकी खिलाड़ी टियाफो ने बेहतरीन खेल खेलते हुए अपनी क्षमता दिखाई। उन्होंने चौथे सेट में 4-1 की बढ़त बना ली और ऐसा लग रहा था कि वह लगातार दूसरे साल फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएंगे। टाईब्रेक में 25 साल के टियाफो ने आक्रामक खेल दिखाया और कई तेज और रोमांचक रैलियों में बढ़त बनाई। हालांकि, अर्नाल्डी ने भी शानदार वापसी की, उन्होंने हवा में कूदकर एक जोरदार बैकहैंड मारा और कुछ ही देर बाद निर्णायक अंक जीत लिया।

इस समय अर्नाल्डी पूरी तरह लय में थे और अपने शानदार ग्राउंडस्ट्रोक्स की मदद से उन्होंने 4-2 की बढ़त बना ली। हालांकि, टियाफो ने हार नहीं मानी और एक दमदार फोरहैंड लगाकर स्कोर 4-4 से बराबर कर दिया। रोमांचक मुकाबले के दौरान एक ही रैली में टियाफो दो बार गिर भी पड़े। इसके बाद अर्नाल्डी ने फिर से अपना नियंत्रण वापस पाया और आखिर में अपने तीसरे मैच पॉइंट को जीत में बदलकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

अर्नाल्डी अब अपने ही देश के खिलाड़ी माटेओ बेरेटिनी से भिड़ेंगे। खास बात यह है कि अर्नाल्डी, बेरेटिनी और फ्लेवियो कोबोली मिलकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

ब्रिटिश ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप: हार के साथ अभय और चोटरानी का सफर समाप्त

बर्मिंघम । ब्रिटिश ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप के पुरुषों के ड्रॉ में भारत की चुनौती मंगलवार को खत्म हो गई। अभय सिंह और वीर चोटरानी को अपने से बेहतर रैंक वाले विरोधियों के खिलाफ दूसरे राउंड में हार का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड नंबर 24 भारतीय खिलाड़ी अभय ने मिस्र के स्टार मोहम्मद जकारिया के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार चार गेम तक चले करीबी मुकाबले में 9-11, 4-11, 11-7, 10-12 से हार गए। अभय ने मैच की शुरुआत अच्छी की, लेकिन पहले दो गेम गंवा बैठे। इसके बाद उन्होंने दमदार वापसी करते हुए तीसरा गेम 11-7 से जीत लिया और मुकाबले में वापसी के संकेत दिए। चौथे गेम में भी दोनों खिलाड़ियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। अभय ने मैच को निर्णायक पांचवें गेम तक ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अहम मौकों पर मोहम्मद जकारिया ने बेहतर खेल दिखाया और 12-10 से गेम जीतकर मैच अपने नाम कर लिया। अभय की इस हार के साथ टूर्नामेंट में उनका शानदार सफर भी समाप्त हो गया। भारतीय खिलाड़ी ने प्रतियोगिता की शुरुआत बेहतरीन अंदाज में की थी और पहले दौर में कोलंबिया के मटियास नुडसेन को सीधे गेम में हराकर अपनी छाप छोड़ी थी।

'वर्ल्ड चैंपियन होने से बेहतर कुछ नहीं', फीफा वर्ल्ड कप 2026 से पहले बोले फ्रांस के हेड कोच डेसचैम्प्स

पेरिस। फ्रांस के हेड कोच डिडिएर डेसचैम्प्स ने फीफा वर्ल्ड कप जीतने को फुटबॉल की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। टीम की कमान संभालते हुए अपने चौथे वर्ल्ड कप और आखिरी टूर्नामेंट की तैयारी करते हुए डिडिएर ने कहा कि 'वर्ल्ड चैंपियन होने से बेहतर कुछ नहीं है'।

विश्व कप 2026 से पहले 'फीफा' से बात करते हुए डेसचैम्प्स ने फ्रांस के साथ अपने शानदार सफर के बारे में बताया, जिसमें उन्होंने 1998 में कैप्टन और 2018 में कोच के तौर पर ट्रॉफी जीती थी। उन्होंने कहा, 'मैं क्लब लेवल, चैंपियंस लीग और भी बहुत कुछ जीतने के लिए काफी खुशकिस्मत रहा हूं, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन होने से बढ़कर कुछ नहीं है। आपका नाम वहीं रहता है, लेकिन दो शब्द हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं: 'वर्ल्ड चैंपियन।'

57 वर्षीय के डेसचैम्प्स फुटबॉल इतिहास के उन तीन लोगों में से एक हैं जिन्होंने प्लेयर और कोच दोनों के तौर पर वर्ल्ड कप जीता है। उनके अलावा यह कारनामा ब्राजील के मारियो जागालो और जर्मनी के फ्रांज बेकनबाउर ही कर सके हैं। अगर इस गर्मी में वह एक और खिताब जीत लेते हैं, तो यह उनकी विरासत को और मजबूत कर देगा। इससे वे ऐसे पहले कोच बन जाएंगे जिन्होंने खिलाड़ी और कोच दोनों रूप में वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती है, और बतौर कोच दो बार वर्ल्ड कप जीतने का रिकॉर्ड भी उनके नाम हो जाएगा।

अपनी उपलब्धियों के बावजूद डेसचैम्प्स ने जोर देकर कहा कि वह अतीत के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन्होंने कहा, 'मैं हमेशा सिर्फ आज और कल के बारे में सोचता हूं; मैं बस ऐसा ही हूं। सच कहूं तो और कुछ मायने नहीं रखता। मैं आगे क्या होने वाला है, इस पर फोकस कर रहा हूं। 1998 और 2018 में जो हुआ, वह हमेशा मेरे साथ रहेगा, लेकिन जो बीत गया उसे कोई नहीं बदल सकता। अब मायने यह रखता है कि हम आगे क्या करते हैं।'

फ्रांस 2018 में वर्ल्ड कप जीतने और 2022 में फाइनल में पहुंचने के बाद इस बार भी खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। हालांकि, डेसचैम्प्स ने चेतावनी दी कि सिर्फ प्रतिष्ठा से सफलता नहीं मिलेगी। 'हमने अपने नतीजों की वजह से उम्मीदें बनाई हैं। हमने 2018 में ट्रॉफी उठाई और 2022 में फाइनल में पहुंचे, इसलिए हमारे समर्थकों को उम्मीद है कि हम आखिर में फिर से वहां होंगे।

15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी की सफलता पर आईआईएम इंदौर करेगा अध्ययन

इंदौर। महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने अपनी आतिशी बल्लेबाजी से हर तरफ सनसनी फैला रखी है। आईपीएल में कम उम्र में अपनी असाधारण प्रतिभा और शानदार प्रदर्शन से राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले वैभव अब एक खास अकादमिक अध्ययन का विषय बनेंगे।

दरअसल, आईआईएम इंदौर उनकी 15 वर्ष की आयु में मिली सफलता, उसके पीछे के कारणों और उपलब्धियों के प्रभावों पर व्यापक शोध करेगा।

आईआईएम इंदौर के डायरेक्टर हिमांशु राय ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि असाधारण प्रतिभा को यदि सही वातावरण, मार्गदर्शन और अवसर मिलें तो वह असाधारण परिणाम दे सकती है। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़ी उपलब्धि के पीछे केवल व्यक्ति का प्रयास नहीं होता, बल्कि परिवार, प्रशिक्षकों, सामाजिक सहयोग और संस्थागत समर्थन की भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हालांकि, हिमांशु राय ने माना कि कम उम्र में मिलने वाले यश और सफलता अपने साथ कई तरह की चुनौतियां भी लेकर आती हैं। उन्होंने कहा कि अचानक लगातार मौके मिलने, उम्मीदों का दबाव और सोशल मीडिया की निगरानी से युवा प्रतिभा प्रभावित हो सकती है। आईआईएम इंदौर के डायरेक्टर के मुताबिक, विश्व स्तर पर ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं, जहां जरूरत से अधिक अपेक्षाओं और मानसिक दबाव की वजह से प्रतिभाशाली खिलाड़ी मानसिक थकान और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर हुए हैं। हिमांशु राय ने बताया कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आईआईएम इंदौर इस विषय पर व्यापक अध्ययन करने जा रहा है। इस शोध में उन सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, पारिवारिक और संस्थागत कारणों का विश्लेषण किया जाएगा, जो कम उम्र में शानदार प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं के विकास में अहम किरदार निभाते हैं। उन्होंने बताया कि नेतृत्व, व्यवहार विज्ञान और मानव क्षमता के विशेषज्ञ मिलकर यह समझने का प्रयास करेंगे कि शुरुआती सफलता युवा प्रतिभाओं के आत्मविश्वास, व्यक्तिगत विकास और भविष्य की दिशा को किस तरह से प्रभावित करती है।

डायरेक्टर के अनुसार, इस अध्ययन का उद्देश्य महज एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी की सफलता का विश्लेषण करना नहीं है, बल्कि ऐसे निष्कर्ष तैयार करना है, जो भविष्य में उभरने वाली युवा प्रतिभाओं के लिए मार्गदर्शक साबित हो सकें। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि खेल उपलब्धियों के साथ मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और समग्र विकास को समान महत्व मिले।

स्वात्वधिकारी राइवल्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक सुजीत कुमार द्वारा साई प्रींटिंग प्रेस, डी-85, सेक्टर 6 नोएडा,गौतम बुध्द नगर पिन कोड -201301 उ.प्र. से मुद्रित और मकान संख्या एन-58 जगतराम पार्क के सामने, लक्ष्मी नगर पूर्व दिल्ली-110053 से प्रकाशित
समाचार संपादक : चन्द्रमणी साव (पीआरबी एक्ट के अनुसार समाचार पत्र चयन एवं संपादन के लिए उत्तरदायी। नोट किसी भी विवाद के निपटारे के लिए न्यायक्षेत्र दिल्ली होगा) मोबाइल 9340573892 ई-मेल: vishwakesari2026@gmail.com,आर.एन.आई.नं. DLHIN/2015/61415